हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2021

खण्ड–1, अंक–9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 16 मार्च, 2021 (द्वितीय बैठक)

पृष्ठ संख्या

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त कीमत की पुनर्गणना के विषय में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश तथा साथ ही साथ पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायधीशों (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के लागू न करने संबंधी

वक्तव्य–

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार, 16 मार्च, 2020 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पश्चात् 02.35 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का मामला उठाना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के पुनरारम्भण से पहले सदन में एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूं । अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट अब टेबल की गई है । At this stage, what is the use of these figures? जिस दिन बजट पेश होता है कैग की रिपोर्ट उसी दिन टेबल करनी होती है । यह गलत प्रथा है । यह संविधान के तहत अपेक्षित है कि कैग रिपोर्ट बजट के साथ टेबल होती है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अभी चर्चा चल रही है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, बेशक चर्चा चलती रहे लेकिन आप बताइये कि जो डिबेट ओपन करता है वह क्या करेगा ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या यह रिपोर्ट उसी दिन टेबल नहीं होनी चाहिए थी ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अफसरशाही पूरी तरह से भ्रमित कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आगे से हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि कैग रिपोर्ट समय से टेबल हो ।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त कीमत की पुनर्गणना के विषय में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश तथा साथ ही साथ पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के लागू न करने संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा अन्य छः विधायकों (श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री वरूण चौधरी, श्री शीशपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र पंवार) के द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त कीमत की पुनर्गणना के विषय में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश तथा साथ ही साथ पंजाब तथा हरियाणा उच्च

न्यायालय के तीन माननीय न्यायधीशों (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के लागू न करने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 प्राप्त हुई है । मैंने इसको स्वीकार कर लिया है । अब श्री भारत भूषण बतरा, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें । हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 73(2) के तहत इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चार अन्य हस्ताक्षरी सदस्य भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, उस झगड़े का निपटान करने के लिये तीन जजों की समिति बनाई गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इन सैक्टर्ज में कौन सी जमीन उन पर लोड हो गई है और कौन सी जमीन लोड नहीं होगी, इस बात पर मंथन किया गया। इस संबंध में कमेटी ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। निर्णय देने के बाद दिनांक 22.08.2019 को एक फ्रैश आर्डर जारी कर दिया गया कि उन तीन जजों की समिति की रिपोर्ट हमने स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर हरेक सैक्टर का री–कैलकुलेशन किया जाएगा। री–कैलकुलेशन करने का काम अभी चल रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर्ज की इन्हांसमैंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए सरकार ने 20 मार्च की नई डेडलाइन तय कर दी है। दिनांक 20 मार्च तक हरेक सैक्टर की रिपोर्ट आ जायेगीख इसके तुरन्त बाद अलॉटीज को बता दिया जायेगा कि फलां सैक्टर में इतनी इन्हांसमैंट बकाया है। हरेक सैक्टर का अलग–अलग बताना पड़ेगा। क्योंकि किसी सैक्टर ने कम इन्हांसमैंट की किस्त कम जमा करवाई हुई है। और किसी सैक्टर ने इन्हांसमैंट की किस्त ज्यादा जमा करवाई हुई है। अब इस कमेटी के पास जो फाइनल आउट स्टैंडिंग अमाउण्ट सैक्टर्ज की बाकी है वह उनको जमा करवानी होगी। अगर यह अमाउण्ट जमा नहीं हुई तो आगे विभाग जो कार्रवाही करेगा सो करेगा। मैंने इस प्रकार से इन्हांसमैंट की सारी की सारी बातें आपके माध्यम से सदन में बताई है। समिति की रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने दूसरी गणना के लिये नई नीति बनाई है। उसके अनुसार 20 मार्च से पहले दूसरी गणना कर आवंटियों को बता दिया जायेगा कि उनके खाते में कितनी इन्हांसमैंट निकली है। अंतिम राशी जो भी होगी, उन्हें जमा करानी पड़ेगी। भविष्य में हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण व एच0एस0आई0आई0डी0सी0 में इन्हांसमैंट नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संबंधित मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

वक्तव्य–

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त मूल्य की अन्तरिम गणना 20.03.2020 तक क्षेत्रीय समितियों, क्षेत्रीय प्रशासकों की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने की संभावना थी। उनके द्वारा उक्त तिथि तक इन गणनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और इसके बाद करोनावायरस (कोविड–19) की चल रही महामारी के कारण पूरे राज्य में तालाबंदी हुई। इस महामारी से अतिरिक्त कीमत की गणना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसके बाद, प्राथमिकता पर गणना को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श प्राधिकरण की 120 वीं बैठक जो कि 29.09.2020 तथा 121 बैठक जोकि 12.11. 2020 को सम्पन्न हुई, में भी हुआ।

1. निम्नलिखित तीन माननीय न्यायधीशों (सेवानिवृत्त) का एक पैनल अधिसूचना नंबर 197601 दिनांक 01.10.2018 द्वारा गठन किया गया।

(क) माननीय न्यायमूति (सेवानिवृत्त) श्री प्रीतम पाल

(ख) माननीय न्यायमूति (सेवानिवृत्त) डॉ भारत भूषण परसन

(ग) माननीय न्यायमूति (सेवानिवृत्त) श्रीमती राज राहुल गर्ग।

निम्नलिखित मुद्दे पर राय देने और निविदा करने के लिएः

क्या स्थानातंरण करने वाले या पट्टेदार जोकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विनियम, 1977 की धारा 2(x) एवं हरियाणा शहरी विकास (भूमि और भवनों का निपटान) विनियम, 1978 के नियम 10(1) के साथ 2(b) एवं 2(h) के अनुसार अतिरिक्त मूल्य देने के लिए बाध्य है, को उसी सैक्टर में, common land का भी अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के उत्तरदायी है या नहीं।

मननीय न्यायाधीशों के पैनल ने 31.03.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने 25.04.2019 को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् नीति निर्देश नंबर 63, दिनांक 22.08.2019 सभी सबंधित कार्यालयों को परिचालित किया गया। इस नीति निदेश में अतिरिक्त मूल्य की पुनः गणना के लिए सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है जिसमें पैरा 2 (xvii) उन सुविधाओं की सूची है जो आवासीय/गैर आवासीय वाणिज्यिक या अन्य के आधार पर आबंटियों/भूखंड धारकों के लिए पारित की

जानी है या नहीं अथवा या पट्टेदारों को बिक्री योग्य क्षेत्र के आधार पर दिया जाना है। न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों के अनुसार आबंटियों से 43 सुविधाओं का संवर्द्धन मुआवजा नहीं लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निर्देश संख्या 63 के पैरा 6 में उल्लेखित किया गया है कि मौजूदा प्रथा को भी बदला जा रहा है और अब क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रशासक की अध्यक्षता में रेज़ीडेन्स वैलफेयर एसोसियशन/आबंटियों/याचिकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श करने उपरान्त अतिरिक्त मूल्य की गणना क्षेत्रीय प्रशासक की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की जाएगी।

(क) सम्बधित शहरी सम्पदा के सम्पदा अधिकारी।

(ख) संबधित क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण अधिकारी।

(ग) शहरी सम्पदा के जिला नगर योजनाकार।

निर्देश नं. 63 दिनांक 22.08.2019 में निहित सिद्धान्त तथा पुनः संशोधित निर्देश नं. 67 दिनांक 04.12.2020 को भविष्य के संवर्द्धन के मामलों में लागू किया जाना था जहां ह.श.वि.प्रा. द्वारा 2019 के निर्देश जारी होने के बाद अतिरिक्त कीमत की मांग की जानी है ना कि पहले की मांगों के लिए।

यह महसूस किया गया है कि निर्देश नं. 63 दिनांक 22.08.2019 तथा निर्देश नं. 67 दिनांक 04.12.2020 के सिद्धान्त को Last and Final Settlement Scheme योजना के लिए विचारा जाए जिस पर ह.श.वि.प्रा.ने अतिरिक्त मूल्य (वृद्धि) चार्ज करने की कार्यवाही में देरी की जिस पर आंबटियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया गया है तथा 01.04.2015 के बाद उठाए गए लंबित विवादों के निपटान तथा अतिरिक्त कीमत वृद्धि के अवैतनिक भुगतान के लिए विचारा जाए।

Last and Final Settlement Scheme योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों की अतिरिक्त कीमत (वृद्धि) की गणना विभिन्न क्षेत्रों के आरडब्ल्यूए के परामर्श से क्षेत्रीय प्रशासकों, ह.श.वि.प्रा. की अध्यक्षता में क्षेत्रीय समिति द्वारा की गई है। जहां भी आवश्यकता होगी, क्षेत्रीय प्रशासक माननीय न्यायालयों की दिशा के अनुपालना में सकारण आदेश भी पारित करेंगे। 24.02.2021 को 122वीं बैठक में प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ last and final settlement scheme योजना 03.03.2021 को शुरू की गई है और यह 30.04.2021 तक लागू रहेगी। लगभग 15500 आंबटियों को योजना के तहत लाभान्वित होने की संभावना है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, the matter is not so simple as has been answered by the Hon'ble Agriculture and Farmers' Welfare Minister. The Policy has been announced by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House categorically that we will accept condition 63 accordingly. I would like to read condition 63. (Interruptions) Speaker Sir, I will take slight time not more time to explain it. It is faked. Money involved in it. It is not only one person is affected but also all the residents in the State even Panchkula residents they are also very badly affected from this law. इसमें घग्गर का भी झगड़ा था लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंडीशन–63 के डिसीजन को चेंज किया? क्यों चेंज किया और चेंज करने के क्या रिजन थे? मैं इस बात को सदन के सामने जरूर रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं परन्तु इस विषय पर सदन में डिबेट नहीं की जा सकती।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है परन्तु why is Government concealing the facts इतनी बड़ी एडवर्टाइजमैंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी पटिका को रिलीज किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि why it has been changed. सरकार ने कंडीशन 63 को कमेंट क्यों किया और किस बात के लिए किया? सरकार ने इसको पार्ट्स में बांट दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दिनांक 01.04.2015 से पहले इन्हांसमैंट के पैसे भर दिये थे। यह बात सरकार कह रही है कि उनके ऊपर पॉलिसी ऐप्लीकेबल नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि उन लोगों ने पैसा भर दिया तो उन लोगों को वह पैसा वापिस देना चाहिए था इसलिए मैं सदन के सामने कुछ सबमिशन रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो आपने 3–4 ऑब्जर्वेशन दी हैं। मेरे ख्याल से आपके वही क्वैश्चन हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरी आपसे humble request है कि अभी आप कृपया करके मुझे बोलने दें और मेरे द्वारा जो भी सवाल पूछे जायें उन सभी का रिप्लाई मुख्यमंत्री महोदय को देने दें।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, कालिंग अटैंशन मोशन के निर्धारित नियमों के तहत आप एक सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछें।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, there is no use of supplementary question because it is a technical matter. टैक्नीकल मैटर में माननीय मुख्यमंत्री जी दो मिनट में जवाब दे देंगे और यह मामला खत्म हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, कालिंग अटैंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। Relevant Rules are very clear and you know very well.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं और मैं डिबेट करूंगा भी नहीं because I know the Rules.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछें।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। सप्लीमैंट्री कवैश्चन पूछने से पहले तो मैं गवर्नमैंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। इस पॉलिसी को पहले वाली पॉलिसी को चेंज करके अनाउंस किया गया है। वह हाउस के अंदर स्टेटमैंट थी। Why the Chief Minister is backing out from the statement, which was made on the floor of the House? How can he back out from his statement? मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में स्थिति तो क्लीयर करें। क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने क्यों back out किया?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ बताने का मौका देंगे तभी तो वे कुछ बता पायेंगे ?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, अगर आप मुझे पांच मिनट का समय दे देंगे तो मैं उसको आपको पढ़कर सुना देता हूं। उसके बाद मैं सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, कालिंग अटैंशन मोशन के सम्बन्ध में रूल बुक में यही प्रोसीजर lay down है। इसी रूल बुक को आप ही मुझे हमेशा दिखाते हो।

श्री भारत भूषण बतरा : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं समराईज करता हूं। यह मामला बहुत सीरियस है जिसके लिए आप मुझे अपनी बात कहने की परमीशन नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस पूरी की पूरी स्कीम को अनाउंस करके वाहावाही लूटने का काम करना चाहते हैं। अगर हम इस सम्बन्ध में हाउस में बात करना चाहते हैं तो

आप हमें अपनी बात कहने की परमीशन नहीं देते हैं। स्पीकर सर, यह लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो आपने कालिंग अटैंशन मोशन दिया उसमें आपने पूरी डिटेल के साथ सभी कुछ पूछा है।

श्री भारत भूषण बतरा : ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर आप मुझे अपनी बात कहने के लिए अलाऊ ही नहीं कर रहे हैं तो मैं अपना सप्लीमैंट्री क्वैश्चन ही पूछ लेता हूं। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? अगर आप मुझे यहां पर अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देंगे तो प्रदेश के लोगों के हितों की लड़ाई को इस हाउस के अंदर कैसे लड़ा जायेगा?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, ऐसी बात नहीं है कि आपको यहां पर बोलने का मौका नहीं दिया गया है। आपको गवर्नर एड्रैस के ऊपर अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। इसी प्रकार से आपको बजट के ऊपर भी बोलने का मौका दिया गया है। जहां तक कालिंग अटैंशन मोशन पर बोलने का सम्बन्ध है as per procedure you can ask one supplementary question और जो बाकी के चार सदस्य इसमें शामिल हैं वे भी सप्लीमैंट्री क्वैश्चन ही पूछेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मेरे हिस्से का सप्लीमैंट्री क्वैश्चन भी आदरणीय बतरा साहब ही पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है गीता जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमैंट ने एक पॉलिसी अनाऊंस की। सर, गवर्नमैंट ने जो पॉलिसी अनाऊंस की है मैं उस पॉलिसी के ऊपर में कुछ रिएक्शंज आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा और वे रिएक्शंज कहीं और के नहीं हैं बल्कि वे पंचकूला के रिएक्शंज हैं। मैं उनको हाउस में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आपको मुझे उसके लिए इजाजत देनी होगी। मैं यहां पर कोई ऐसी–वैसी डिबेट नहीं करने जा रहा हूं। स्पीकर सर, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही आर्गूमैंट्स करते रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात कैसे कह पाउंगा? स्पीकर सर, आप मुझे घड़ी में देखकर पूरे पांच मिनट अपनी बात कहने के लिए दे दें। मैं पांच मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा और आपसे छठे मिनट की डिमाण्ड नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बतरा जी, आप अपनी बात कहें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, पंचकूला की रैजीडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हमने प्लॉट खरीदकर गुनाह कर दिया है। ये पॉलिसी के बाद लोगों के रिएक्शंज हैं। यह मेरा रिएक्शन नहीं है। मैंने तो कोई प्लॉट लिया हुआ भी नहीं है। हुडा के सैक्टर में मेरा कोई प्लॉट नहीं है। उसके बाद वे कहते हैं कि अपनी कमेटी की सिफारिशों को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। This is being said by the residents of Panchkula not Hisar or Rohtak. मैं किसी दूसरी जगह के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मनमर्जी से इनहांसमैंट राशि तय कर दी है। सरकार की को दोनों स्कीमें हैं। इस मामले में जो 120वीं मीटिंग हुई जिसको अब सी.एम. साहब ने एप्रूव किया है उस मीटिंग में जब फाइनैंशियल सैट–अप सहित सब कुछ सामने आया तो सरकार की प्लॉटधारकों की तरफ बहुत सी देनदारियां बनती थी। इसी कारण से सरकार द्वारा पॉलिसी को चेंज किया गया। इस प्रकार से सरकार ने उस पुरानी पॉलिसी को प्लॉटधारकों के इंट्रैस्ट के खिलाफ एकदम चेंज कर दिया। इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी को दो पार्ट्स में भी बांट दिया। स्पीकर सर, इससे सम्बंधित हुडा के रेगुलेशन के सैक्शन 10 में यह कहा गया है कि हुडा जब प्रिंसीपल अमाउंट में एनहांसमैंट का नोटिस देगा उसक बाद ही उसका इंट्रैस्ट शुरू होगा। अगर हुडा सात साल तक कोई नोटिस नहीं देता तो इसमें प्लॉट के अलॉटी का कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ उस सूरत में होता यदि उससे पहले पैसा मांगा गया होता और उस समय उसने पैसा न दिया होता। अदरवाइज वह 12 या 15 परसैंट कम्पाउंडिंग इंट्रैस्ट क्यों देगा? सरकार द्वारा यह सब कुछ अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया गया है। यह सब इनकी रिपोर्ट्स और प्रौसीडिंग्स के अंदर आया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने जो नोटिंग एप्रूव की उसके पेज के ऊपर लिखा है – During the calculation of the additional price enhancement by applying the principles of the Instruction No. 63 decision taken by the Pradhikaran in such and such meeting, it was observed that in some cases net outstanding payable by the defaulters should come negative. अब उससे बचने के लिए सरकार ने क्या कर दिया कि 01.04.2015 की तारीख रख दी कि उससे पहले का जो भी अलॉटी होगा उसको किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इन्हांसमैंट रीकैल्कुलेशन के लिए जजिज की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने एक सैटअप बना दिया कि ये

चीजें ऑफलोड होंगी और ये चीजें ऑफलोड नहीं होगी। इतना कुछ होने के बाद जो भी डिफॉल्टर हैं उनको आप सैग्रीगेट कैसे कर सकते हैं। जिस आदमी ने समय पर अपनी इनहांसमैंट भर दी उसकी क्या गलती थी? उसको भी तो रिलीफ मिलना चाहिए था। आपने यूनीलेटरली डिसाइड कर दिया कि 01.04.2015 से पहले वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और बाकी सभी पर यह एप्लीकेबल होगी। यहां हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन नं. 63 के तहत कमेटी बनेगी और उस कमेटी में आर.डब्ल्यू.ए. के भी प्रतिनिधि होंगे। इस बारे में मेरा कहना यही है कि इस पॉलिसी में इतने मैनीफोल्ड लिटिगेशन होंगे कि सरकार के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जायेगी। एक–एक सैक्टर में प्लॉट का साइज वगैरह सेम होने के बावजूद भी अलग–अलग अलॉटीज को अलग–अलग रिलीफ दिया गया है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपका समय समाप्त होने वाला है इसलिए आप जल्दी से वाइंडअप कीजिए।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्कीम को दो पार्ट में क्यों बांटा गया? 01.04.2015 से पहले वाले अलाटियों का क्या कसूर था, उनको स्कीम का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया। Why uniform scheme has not been applied by the Government. दूसरी बात यह है कि जब पहली स्कीम जजिज की रिपोर्ट के साथ और इंस्ट्रक्शन नं. 63 के अनुसार रीकैल्कुलेशन होनी थी तो उसको क्यों चेंज किया गया? कैल्कुलेशन में जोनल हैड और आर.डब्ल्यू.ए. की कमेटी बना कर प्रत्येक सैक्टर का फैसला क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट पर एक मीटिंग होती है जिसमें मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और अगली मीटिंग में ही उस निर्णय को बदल दिया जाता है। यह प्लॉट होल्डर्स के साथ अन्याय है। पहले प्लॉट होल्डर्स ने समय पर इन्हांसमैंट भर दी। उसके बाद जजिज की कमेटी ने 40 प्रतिशत का बैनिफिट देकर लम्प–सम अमाउंट जमा करवाने का सुझाव दिया तो जिन्होंने समय पर इन्हांसमैट जमा करवाई थी उनको भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए था, उनको पैसा वापिस मिलना चाहिए था लेकिन सरकार ने कह दिया कि किसी को भी रिफंड नहीं मिलेगा। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, एक बार सभी सदस्यों की सप्लीमैंट्री हो जाएं उसके बाद आप इक्ट्ठा जवाब दे देना।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह जो कैलकुलेशन है, यह जो कमी आई है उसको दोबारा से रीकैल्कुलेट करवा रहे हैं। इसमें विभाग ने क्या कमियां छोड़ दी थी? जैसा कि बतरा जी ने बताया कि 1.4.2015 से पहले वाले लोगों का क्या कसूर था, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए था। ये कॉमन प्लेसिज हैं कम्युनिटी सैन्टर, पार्क, स्कूल इत्यादि हैं, उनकी इन्हांसमैंट रेजीडैंट्स पर किसलिए लगाई जा रही है? रेजीडैंट्स को आज आप कमेटी में शामिल कर रहे हैं, उस समय उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, उस समय क्या दिक्कत थी। ये सारी बातें और जिस ढंग से पॉलिसी बनाई गई है यह विभाग को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। कहीं पर कुछ राहत दी गई है और कहीं पर कुछ राहत दी गई है। सभी को एक समान राहत प्रदान नहीं की गई है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, the reply to the statement should come from the mouth of the Hon'ble Chief Minister and not from the Minister because the Chief Minister has given the statement in the House.

Mr. Speaker: Batra Ji, on behalf of the Hon'ble Chief Minister, any Minister can give reply.

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, we have challenged the statement given by the Hon'ble Chief Minister. The Minister has no complete knowledge of the facts.

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, बतरा जी ने जो इतना लम्बा–चौड़ा भाषण दिया है उसमें अलग–अलग वक्त पर तीन स्कीम्ज आई हैं। इसमें जो पहली स्कीम आई उसमें लगभग 568 करोड़ रुपये का रिबेट दिया गया था। जब दोबारा स्कीम आई तो उसमें 4 हजार बेनिफिशरीज को साढ़े सैंतीस प्रतिशत रिबेट दिया गया। तीसरी स्कीम जो एक जजिज द्वारा रिक्मैंड की गई थी उसमें भी प्लॉट धारकों को लगभग 764 करोड़ रुपये का रिबेट मिलेगा। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि पहले वाले प्लॉट धारकों को अब के फॉर्मूले के हिसाब से रिबेट क्यों नहीं दिया गया। यह तो ऐसा सवाल है जैसे शुरू में 100 रुपये से बुढ़ापा पैंशन शुरू हुई थी अब ये कहेंगे कि उन पहले वाले पैंशन धारकों को 2500 रुपये क्यों नहीं दे रहे। यह इस तरह का सवाल किया गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त की जो

स्कीम थी उसका उस वक्त के हिसाब से रिबेट दिया गया है। अबकी जो स्कीम है उसका इस समय के हिसाब से रिबेट दे रहे हैं। अभी बतरा जी का सवाल आने से पहले हमने ये सारी स्कीम्ज लागू कर दी हैं। मैं आदरणीय सदस्य महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मार्च को ही लास्ट एण्ड फाईनल सैटलमैंट स्कीम इनके सवाल से पहले ही लागू कर दी थी। इससे प्लॉट धारकों को बहुत फायदा होगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वास्तव में उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि पॉलिसी बनाने का काम सरकार का होता है और इस दौरान अगर कोई पॉलिसी बनाते समय और उससे पहले व बाद में कोई चेंजिज करते समय एक कमेटी बनाई जाती है और वह कमेटी एक रिपोर्ट देती है। वह रिपोर्ट पॉलिसी का पार्ट तब बनती है, जब सरकार उसको स्वीकार कर लेती है। कई बार कमेटी की रिपोर्ट को सरकार रिजैक्ट भी कर देती है और कई बार उस कमेटी की रिपोर्ट में से रिपोर्ट का एक पार्ट भी स्वीकार किया जा सकता है और पूरी रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है। यह सरकार का एक प्रैरोगेटिव है। आपको पता है क्योंकि आप लोग भी पहले सरकार चलाते रहे हैं। दूसरी बात जो ये एच.एस.वी.पी. की पॉलिसी है जिसका नाम पहले हुडा डिपार्टमैंट था। हमने उसमें कहा कि बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी उस हुडा का श्रेय और अपश्रेय इधर चला जाता तो कभी इन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का श्रेय और अपश्रेय उधर चला जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या इस डिपार्टमैंट के नाम बदलने का यही कारण है?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, यह एक बहुत बड़ा कारण है। हमने इस विभाग का नाम नहीं बदला है। हमने तो केवल उस विभाग के नाम का हिन्दीकरण किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई एक सज्जन विदेश से आ गये और वे विदेश से आने के बाद कई जगह घूम गये। कहीं पंचकूला गये, कहीं गुरूग्राम गये। जगह–जगह लिखा था कि हुडा प्लॉट, हुडा प्लॉट। अब वह आदमी कहता है कि Hooda is such a rich person. He has thousand acres of land तो हमने बताया कि यह वह हुडा नहीं है, वह और हुड्डा हैं इसलिए हमने 'हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी' का हिन्दीकरण करके 'हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण' किया है। यह वही एच.एस.वी.पी. है। हमने कोई नाम नहीं बदला है। हमने केवल

उसका अंग्रेजी से हिन्दीकरण किया है इसलिए उसका नाम 'हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण' ''एच.एस.वी.पी.'' किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी यह सवाल आया था तो मैंने लोगों को समझा दिया था कि एक है Huda ('हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी') दूसरा है Hooda (हरियाणा ऑवर ऑल डिवैल्पमैंट अथोरिटी)।

श्री मनोहर लाल : चलो यह तो अच्छी बात है कि आप लोगों को ये समझा पाए, लेकिन हमें लगा कि अगर हम समझाने में फेल हो गये तो सारा कुछ इनके ऊपर आ पड़ेगा। कभी ये मुश्किल में ना फंस जाएं। इनको बचाने के लिए हमने इस विभाग का नाम ''एच.एस.वी.पी.'' कर दिया।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, लोग तो दूसरी तरह ही बोलते हैं। 'harassment till death.' **(हंसी)**

15:00 बजे

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब क्योंकि वह पॉलिसी उस समय की बनी हुई है। आज की बनी हुई नहीं है। इसमें जमीन के ऊपर इन्हांसमैंट आने का जो सिस्टम है, वह पहले से ही है। यह हमारे आने के बाद नहीं हुआ है। मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं कि पहले जो इन्हांसमैंट आती थी, उसका सारा का सारा पैसा किसान को एक साथ नहीं दिया जाता था। किसी किसान को कभी दे दिया, किसी किसान को कभी दे दिया क्योंकि वह पूरे सैक्टर का मामला होता था और सारी इन्हांसमैंट पूरे सैक्टर के ऊपर पड़ती थी। जब भी किसी किसान की पेमैंट दी गई या उस किसान को पार्ट पेमैंट दी गई तो उसको उतने ही पोर्शन का नोटिस देते थे। मान लीजिए किसी सैक्टर के 10 किसानों का पैसा है। एक को दिया तो इन्हांसमैंट दे दी, दूसरे को दिया तो फिर इन्हांसमैंट का नोटिस दे दिया। यह एच.एस.वी.पी. यानी हुडा डिपार्टमैंट के जो पुराने अधिकारी हैं उनसे हम कन्फर्म कर सकते हैं। इन्हांसमैंट का विषय इतना लम्बा है कि उसके ऊपर अगर मैं यह कहूं कि कोर्ट की लगातार इतनी इन्हांसमैंट आती रही कि एच.एस.वी.पी. और एच. एस.आई.आई.डी.सी. की अगर माली हालत खराब हुई और कैश क्रन्च आया तो केवल एनहांसमैंट के कारण से ही आया। यह जो एनहांसमैंट किसान को मिलती है न तो सरकार को भरनी होती है न हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भरनी होती है बल्कि इसको प्लॉट के होल्डर्ज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यह उन्हें ही भरनी होती है। अल्टीमेटल जब हम सत्ता में आये तो हमने इस प्रकार की

समस्या को देखा कि एक–एक प्लॉट होल्डर को आज एक इन्हांसमैंट, कल दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी एनहांसमैंट जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास पैसा नहीं था तो यूं कहें कि वहां भी सब एक तरह से उधार पर ही चल रहा था और अनाप शनाप ढंग से 15 परसेंट का इंट्रस्ट लगाने का काम भी चल रहा था और देखिए किसान को भी अगर एनहांसमैंट का पैसा नहीं मिल रहा था तो उसे चिंता नहीं थी क्योंकि एक तरह यह एक नम्बर का पैसा था और उस पर 15 परसेंट इंट्रेस्ट मिल रहा था तो चिंता किस बात की, आज नहीं तो कल पैसा विद इंट्रस्ट जो मिलेगा और इतना ज्यादा इंट्रस्ट तो एफ.डी. पर भी नहीं मिलता। दोनों तरफ से इस प्रकार का सिस्टम चल रहा था लेकिन हमने कहा कि नहीं यह सिस्टम ठीक नहीं है बल्कि अब तक जितनी इन्हांसमैंट आ चुकी हैं, उन सभी इन्हांसमैंट्स के एक साथ नोटिसिज दे दो क्योंकि हमने देखा कि जैसे इन्हांसमैंट वर्ष 2012 में आई और नोटिस वर्ष 2016 में जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार इन्हांसमैंट वर्ष 2008 में आई और नोटिस जा रहा है वर्ष 2015 में। इन सब व्यवस्थाओं को बदलते हुए हमने इन्हांसमैंट्स के सारे नोटिसिज एक साथ लोगों के पास भेज दिए और इनहांसमैंट के नोटिस इक्ट्ठें दिए जाने से लोगों में हलचल शुरू हो गई कि आखिरकार जो यह इतनी बड़ी संख्या में पैसा विद इंट्रस्ट उनके उपर निकल आया हैं, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? कुछ ने कह दिया कि हम तो यह पैसा नहीं देते और झगड़ा शुरू हो गया और मामला कोर्ट में चला गया उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब कोर्ट का डिसीजन है तो मानना तो पड़ेगा ही, वैसे सैद्धांतिक तौर पर उस डिसीजन के पीछे कोई बड़ा तर्क भी नहीं है लेकिन कोर्ट का डिसीजन मानना तो पड़ेगा। कोर्ट न कहा की जिस अवधि तक अलॉटिज को नोटिस नहीं दिया गया तब तक की एनहांसमैंट के पैसे पर इंट्रस्ट नहीं लगेगा जबकि हमारा यह कहना था कि मान लो कोई पैसा अलॉटीज को वर्ष 2012 में देना था और उसको वर्ष 2016 तक कोई नोटिस नहीं गया तो चाहे नोटिस नहीं गया लेकिन इस अवधि के दौरान पैसा तो अलॉटी के पास ही रहा और संभव सी बात है कि कास्ट ऑफ मनी उसी को देनी पड़ती है जिसके पास पैसा होता है। वर्ष 2012 से अलाटी को पैसा देना है, किसान भी इस पैसे को वर्ष 2012 से ही लेगा और विद इंट्रस्ट लेगा तो वैसे तो यह सारा पैसा अलाटी को वर्ष 2012 से ही देना चाहिए लेकिन कोर्ट ने फैंसला किया कि नहीं जो बीच का पीरियड है अर्थात जब तक अलाटीज को नोटिस नहीं गया तब तक उसको पता ही

नहीं चला कि उसको पैसा देना है कि नहीं देना है इसलिए इस पीरियड के पैसे को माफ करने का काम किया जाये। इसके बाद दूसरा झगड़ा शुरू हो गया कि कॉमन लैंड की इन्हांसमैंट प्लॉट्स अलाटीज क्यों दें? इसमें मेरा यह कहना है कि कॉमन लैंड की इन्हांसमैंट संबंधी स्कीम हमारी पार्टी के सत्ता में आने से पहले की बनी हुई है तथा जब से हुडा बना है जिसको अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, तब से ही यह स्कीम चल रही है और इसके बाद म्यूचुअल अंडस्टैंडिंग हुई कि इस संबंध में तीन रिटायर्ड जजिज की कमेटी बना दी जाये, कमेटी बना दी गई इसके बाद एक जो फैसला हुआ उससे एक और विषय पैदा हो जाता है कि ठीक है कि कॉमन लैंड के उपर इन्हांसमैंट नहीं होनी चाहिए लेकिन आखिरकार अब कामन लैंड संबंधी इन्हांसमैंट की अदायगी कौन करेगा? अब यहां सदन में हमारे अनेक सदस्य वकील हैं, वे कांट्रैक्ट ला को अच्छी तरह से समझते हैं कि कांट्रैक्ट लॉ के तहत किसी विषय को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और अगर कोई झगड़ा पड़ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितना मान लिया गया है उसको कोई छोड़ नहीं सकता जो नहीं माना गया है उस पर कोई आर्बिट्रेशन भी हो सकती है या फिर कोई कोर्ट में भी जा सकता है और कोई फैसला भी हो सकता है। तब एक यह विषय भी आया कि जिस आदमी ने लास्ट इंस्टालमेंट की पेमेंट जिस दिन की है, का मतलब यह लगाया जाये कि उस व्यक्ति ने कांट्रैक्ट लॉ को माना हुआ है और सारी पॉलिसी देखकर ही प्लॉट्स वगैरह लिए थे और उसको यह भलीभांति ज्ञान था कि अगर भविष्य में कोई लोड आयेगा तो उसे अलॉटी को ही पे करना पड़ेगा। इस प्रकार यह भी विषय आया कि सब जानकारियां होने के बावजूद जिस दिन से अलॉटी ने पेमेंट देनी बंद कर दी, समझो उसी दिन से वह झगड़े में आ गया। इस सारे झगड़े की सैटलमैंट यही है कि जिस दिन उसने लास्ट पेमेंट की थी और उस समय तक he is following the terms and conditions of the Contract law इसलिए यह विषय आया कि पुराने लोगों को जिन्होंने सारी पेमेंट वगैरह कर दी है, इस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया, का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने टर्म्ज एंड कंडीशंज को मानकर ही पेमेंट की है और यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल बात बताता हूँ कि अगर यह सब पुराने लोगों पर लगा देना शुरू कर देंगे तो बताओ आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा इसकी कोई लिमिट तो होती है? इस तरह से यह प्रोसैस वर्ष 1977 तक चला जायेगा तो पता नहीं अथॉरिटी का क्या

बनेगा, वह अथॉरिटी बचेगी या नहीं बचेगी? अथॉरिटी के घाटे को पूरा करने के लिये जैसे 'उदय' स्कीम में 27 हजार करोड़ रुपये देने पड़े थे, उसी तरह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी देने पड़ेंगे। अभी तक जो इन्हांसमैंट के पैसे दिये भी नहीं गये हैं इससे ज्यादा और बढ़ जाते हैं। इसलिए नियमानुसार प्लॉट आवंटी ने पेमैंट जमा कर दी उससे पहले उस पर लागू नहीं होगी बल्कि उसके बाद लागू होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के बनने से पहले भी यह झगड़ा ध्यान में आ गया था। हम यह चाहते थे कि इस मामले का सैटलमैंट हो जाये। इन्हांसमैंट ज्यादा हो गई, झगड़े पैदा हो गये। ब्याज देना है या नहीं देना है या पिछली इन्हांसमैंट किस हिसाब से देनी है या नहीं देनी है, तरह–तरह की बातें होने लगी तब हम एक वन टाइम सैंटलमैंट स्कीम लेकर आये। स्कीम तो हमेशा स्कीम होती है और स्कीम कोई पॉलिसी नहीं होती है। सरकार ने जो भी इस संबंध में स्कीम बनाई वह जनता के हित में बनाई। जिसने इस स्कीम को स्वीकार करना है वह करे और जिसने इस स्कीम को स्वीकार नहीं करना है वह न करे अर्थात् उसकी इन्हांसमैंट पैंडिंग रहेगी। हम वन टाइम सैटलमैंट स्कीम दिनांक 15 मई, 2018 को लेकर आये। इस स्कीम के तहत जो प्लॉट आवंटी का अमाउण्ट पैंडिंग है, वह उसका 40 प्रतिशत जमा करवाये और 60 प्रतिशत की रिबेट ले और आगे से कोई भी हिसाब–किताब नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 67 हजार के करीब प्लॉट आवंटी डिफाल्टर थे, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद 24163 प्लॉट आवंटियों ने इस स्कीम का फायदा उठाया और लगभग 568 करोड़ रुपये का उनको रिबेट दिया गया। यह स्कीम दिनांक 16 जुलाई, 2018 को बंद हो गई। स्कीम की आखिरी तारीख निकलने के बाद एक विषय यह भी आया कि कुछ लोग पेमैंट भरने से रह गये और बाकी बचे लोगों ने कहा कि इस डेट को आगे बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फिर निर्णय किया और इस तरह से निर्णय करते–करते डेढ़ महीने का समय निकल गया और बाद में दूसरी स्कीम लास्ट एण्ड फाइनल सैटलमैंट लेकर आई। सरकार ने इसको 40 प्रतिशत की छूट न देकर 37.5 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया ताकि जिन लोगों ने पहले पेमैंट जमा करवा दी थी उनको यह न लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है। यह स्कीम भी दिनांक 1 नवम्बर, 2018 को शुरू हुई और 30 नवम्बर, 2018 तक चली। इस स्कीम के तहत 4027 लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया और उनको भी 93 करोड़ रुपये का रिबेट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से 24 प्लस 4 हजार टोटल लगभग

28 हजार लोगों ने इन स्कीम का फायदा उठाया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लगभग 32 हजार लोगों में से जब तक अगली स्कीम नहीं आई इंतजार करते–करते लगभग 15–16 हजार लोगों ने अमाउंट भर दी, अब शायद उनकी थोड़ी बहुत ही अमाउण्ट बाकी होगी उन्होंने बिना कोई रिबेट का लाभ लिये पूरा पैसा जमा करवा दिया। आज के दिन भी लगभग 15–16 हजार ऐसे लोग थे और उन्होंने कहा कि हमारा कोई न कोई सैटलमैंट किया जाये। हमने कहा कि पहले 40 प्रतिशत की रिबेट थी बाद में 37.5 प्रतिशत की रिबेट थी, अब एक और स्कीम हिसाब–किताब लगाकर निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तो सही तरीके से इन्हांसमैंट की पुनर्गणना होनी चाहिए। सही पुनर्गणना की बात आई तो उसके लिये एक कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद चूंकि यह विषय इतना ज्यादा उलझा हुआ विषय था कि उस सैक्शन की कीमत की हर कोई आदमी अपनी–अपनी अलग–अलग तरीके से पुनर्गणना का हिसाब–किताब करने लगा। जो डिफॉल्टर थे वे अपने–अपने हिसाब–किताब से पुनर्गणना कर रहे थे और प्रशासन अपने हिसाब–किताब से पुनर्गणना कर रहा था। यह विषय इसलिये उलझा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि पिछले लोगों को रिबेट क्यों नहीं दिया। सरकार अगर उनके अनुसार रिबेट देना शुरू कर दे तो किसी को 15 लाख रुपये किसी को 10 लाख रुपये और किसी को 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो भी स्कीम आती है वह उसी समय शुरू होती है, उससे पहले लागू नहीं होती। तभी यह कहा गया था कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पहले प्लॉट आवंटियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि बाद वालों को लाभ मिलेगा। बाद में भी जिस दिन भी प्लॉट आवंटी ने अपनी लास्ट पेमैंट जमा करवा दी उससे पहले नहीं बल्कि बाद की डेट से लाभ मिलेगा। तभी यह सारा का सारा कम्प्यूटराइज सिस्टम बनाया गया था, यह बात भी सही है कि इस सिस्टम को बनने में समय लगा। सरकार ने एक स्टेटमैंट दी थी कि मार्च, 2020 में स्कीम को लेकर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2020 के बाद की परिस्थिति का सभी को पता है कि देश और प्रदेश में किस प्रकार से कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से गुजर रहा था। इस महामारी के 6–7 महीने के दौरान कोई भी ऑफिसिज काम करने के लिये नहीं बैठा। सारा का सारा सिस्टम इस महामारी के चलते शक्तिहीन हो गया था। सरकार ने ही इस महामारी के संक्रमण को रोकने की दिशा में यह कहा हुआ था कि ऑफिसिज में आना बंद कर दे। उनको हमने यह भी कहा था कि अपने घर पर बैठकर ही काम

करो । अतः हमें उस डिले को डिले नहीं मानना चाहिए । बाद में लगातार काम करके उसकी इंटीग्रिटी किस प्रकार की थी, उसे भी सुलझाया गया । हमें कोई लालच नहीं था कि हमने किसी को कम देना है । इसके अलावा हमें उस नुकसान को भी पूरा नहीं करना है कि स्कीम के माध्यम से हमें 5–10 लाख रुपये वापिस मिल जाएं । जो पैसा एक बार जमा हो गया वह किसी को वापिस नहीं मिलेगा । मैंने सदन में इस लॉ के बारे में पहले ही बता दिया है । आगे जो बचा हुआ है उसमें स्कीम का लाभ मिलेगा । उसमें किसी को 40 परसैंट मिल सकता है, किसी को 50 परसैंट मिल सकता है, किसी को 60 परसैंट मिल सकता है और किसी को 20 परसैंट लाभ भी मिलेगा । इसका कारण यह है कि इन्हांसमैंट का अलग–अलग पीरियड है, इन्हांसमैंट का अलग–अलग रेट है, हर सैक्टर में अलग–अलग जमीन एक्वायर हुई है, इसलिए जमीन भी कम–ज्यादा होगी । अतः यह एक कॉम्पलीकेटिड सिस्टम है और इसके तहत हरेक प्लॉट की एक अलग कैलकुलेशन होगी । इस कैल्कुलेशन के हिसाब से इस सारे विषय के लिए हमने एक स्कीम बनाई है और इस स्कीम का नाम Full and Final Settlement Scheme है । इस स्कीम को हमने 3 मार्च को ही लागू किया है । इस स्कीम को लागू किये हुए हमें आज 13 दिन हो चुके हैं और यह स्कीम 30 अप्रैल यानि लगभग 2 महीने तक लागू रहेगी । इस स्कीम के तहत 30 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है । आज की डेट में कुल 15,430 में से 762 लोगों ने इस स्कीम के तहत लाभ ले लिया है । टोटल 823 करोड़ रुपये की अमाउंट सैटल होनी है और इसमें से 19 करोड़ 74 लाख रुपये लोगों ने जमा भी करवा दिये हैं । इससे लोगों को 31.10 करोड़ रुपये का लाभ भी हो चुका है । मेरा विश्वास है कि लोग इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए इसमें शामिल होंगे क्योंकि लोग इस स्कीम को स्वीकार कर रहे हैं । हमें इस स्कीम को लागू किये हुए अभी सिर्फ 13 दिन हुए हैं और इस समयावधि में 762 लोग इस स्कीम के तहत लाभ ले चुके हैं । सामान्यतः लोग हर स्कीम का लाभ उसके अंत में लेते हैं । इस स्कीम की लास्ट डेट 30 अप्रैल है । अतः इस समयसीमा तक ज्यादातर लोग इस स्कीम के तहत लाभ ले जाएंगे क्योंकि सभी ने अपना बैनीफिट कैल्कुलेट किया हुआ है । इसमें एक इशू आ रहा है जिसको मैं बता देता हूं । कैल्कुलेशन करते समय कम्प्यूटर एक करोड़ रुपये पर भी वही फॉर्मूला लगाता है जो एक रुपये पर लगाता है । कुछ लोगों का कैल्कुलेशन के हिसाब से 10–20–40–50–100 रुपये बैलेंस बचा था

और उसके कारण उनको 2–2 लाख रुपये तक का नुकसान हो रहा था । हालांकि इसको अभी कम्प्यूटर दिखा नहीं रहा है । हमने निर्णय किया कि हम 50–100 रुपये के बैलेंस की वजह से किसी का 1–2 लाख रुपये का नुकसान नहीं होने देंगे और हमने इस बैलेंस को डिस्पॉज ऑफ करने के लिए आदेश कर दिए हैं । इस विषय को फिलहाल आई.टी. एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और जल्द ही इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा । इस तरह के 4–5 सौ लोग हैं जिनको हमारे इस निर्णय से 4–5 करोड़ रुपये का लाभ होने वाला है । इन्हांसमैंट से संबंधित सभी चीजों को मैं इस सत्र के समाप्त होने के बाद स्वयं चैक करूंगा । इस पॉलिसी के विषय में मैं स्वयं अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा हूं, इसलिए इस विषय से संबंधित हरेक चीज मेरी नॉलेज में है । इन्हांसमैंट से संबंधित सभी चीजों को मैं स्वयं देख रहा हूं, इसलिए मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा । हमारी कोशिश है कि हम सैक्टरवासियों को मैक्सिमम राहत देंगे ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं । रैगुलेशन 10(1) कहता है कि – "the additional price/premium shall be payable by the transferee or lessee within thirty days of the demand of notice." सरकार का कहना है कि हमने 5 साल नोटिस नहीं दिया, 7 साल नोटिस नहीं दिया तो इस पर मेरा कहना है कि अलॉटी तो गरीब है । अगर वह साइन नहीं करेगा तो सरकार उसका प्लॉट कैंसिल कर देगी या फिर उसके खिलाफ रिकवरी शो कर देगी । It is an economic duress otherwise also. मेरा कहना है कि आप रैगुलेशन 10(1) को बदलवाइये । अलॉटी को जिस दिन नोटिस इशू होता है उसको शुरू से लेकर उस दिन तक प्रिंसिपल अमाउंट विद इंट्रस्ट पे करना पड़ता है । यह सैक्शन इस बात के लिए नहीं कहता है बल्कि यह सैक्शन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कहता है । अलॉटी से सरकार टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मांगती तो इस पर मेरा कहना है कि सरकार को इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि अलॉटी नोटिस इशू होने के बाद से इंट्रस्ट पे करेगा और अलॉटी को शुरू से इंट्रस्ट पे नहीं करना पड़ेगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये सैक्शन हमने तो बनाया नहीं है । हम तो अक्तूबर, 2014 से सरकार में आये हैं लेकिन माननीय सदस्य को यह भी देखना

चाहिए कि उससे पहले के कोर्ट के कितने इन्हांसमैंट नोटिस आये हैं । अगर माननीय सदस्य के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस रिकॉर्ड को मैं अपने विभाग से लेकर माननीय सदस्य को दे दूंगा । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार से पहले के समय के नोटिस क्यों नहीं दिए गए और इसके पीछे क्या कहानी है ? मेरा कहना है कि 5–5 साल, 4–4 साल, 3–3 साल के नोटिस पिछली सरकार के समय के भी हैं । इन्हांसमैंट का फ्लक्स वर्ष 2009–10 के बाद से आना शुरू हुआ है । अगर फ्लक्स वर्ष 2009–10 के बाद से भी आना शुरू हुआ है तो जैसे ही इन्हांसमैंट आये तो उसका नोटिस तुरंत जाना चाहिए परन्तु डिपार्टमैंट उसी लेथार्जी पर चलता रहा । हमें वर्ष 2017 में इस बात का ध्यान आया कि सभी लोगों को एक साथ नोटिस दे दें। चाहे उनके पास पैसे हों या न हों। हमने यह भी प्रावधान करवाया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आपको बैंकों के माध्यम से लोन दिलवा देंगे। इसमें उनका प्लॉट बैंक के साथ हाईपोथेटिक हो जाएगा जो किश्त हमें देनी थी, उसको वे बैंक को दे देंगे। इस प्रकार हमने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किये हैं। इसके पीछे जो कहानी है, वह अच्छी नहीं है। अन्यथा मैं उसके बारे में सदन में भी बता देता।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इस बात का सबसे ज्यादा असर मेरे ऊपर पड़ा है। मैं इससे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ हूं।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आपका नाम इस कॉलिंग अटैंशन मोशन में नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वह इस विषय के संबंध में मुझसे बाद में मिल लें।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक–एक अलॉटी को एनहांसमैंट के 28–28 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः शीशपाल जी, इस विषय पर 5 से ज्यादा सप्लीमैंटरी नहीं पूछी जा सकती।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नाम भी शामिल है, इसलिए मुझे भी सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ईश्वर जी, मुझे पता नहीं था कि इसमें आपका नाम भी शामिल है। अभी आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा आरंभ होगी।

.....

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के तौर पर यह बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कोविड– 19 के चलते वर्ष 2021–22 के इस बजट में जनता के ऊपर कोई भी नया कर नहीं लगाया है। इससे ऐसा लगता है कि यह बजट सर्व जन के हित में है और सर्व जन को सुखी बनाने के लिए बनाया गया है। कोविड–19 का जो वर्ष बीत गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक डालने का काम किया है। इसके अतिरिक्त अनाज के करीब 50,000 हजार पैकेट भिवानी क्षेत्र के लोगों के लिए दिये हैं। हमारी तरफ से भी करीब 40–50 हजार पैकेट जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन दिये गये थे। हमने उनके लिए भोजन की अति उत्तम व्यवस्था करवायी थी। हम हर रोज उनके लिए सुनारिया की जेल और भिवानी की जेल से भोजन बनवाते थे और दोनों जेलों से लगभग 1,000–1,000 पैकेट खाने के बनवाते थे। इसके साथ ही साथ करीब 40 सामाजिक संस्थाएं ऐसी थीं, जिन्होंने सभी के साथ मिलकर श्रमिकों और दूसरे जरूरतमंदों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करवायी। मैं इसके लिए उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन सभी संस्थाओं ने मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुंचाया। जब बसों और रेलों की व्यवस्था शुरू हुई तो उनके लिए पानी की बोतलें और खाने की व्यवस्था करवाकर गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे लोगों ने करवाया। हमारे सफाई कर्मचारियों, मेडिकल स्टॉफ, पैरा मेडिकल स्टॉफ और पुलिस कर्मियों ने मिलकर उन लोगों की इतनी सेवा की, जिससे वे गदगद हो गए। वे इस बात से हर्षित थे कि हमारी सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छे काम किये हैं। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्ज में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने और 100 बैड्स से 200 बैड्स करने की घोषणा की है जो कि प्रत्येक जिले के लिए अच्छी शुरूआत है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके क्षेत्र के हॉस्पिटल्ज में 100 बैड्स की संख्या कम पड़ रही है, इसलिए

यह योजना उनके क्षेत्रों के हॉस्पिटल्ज में बैड्स की संख्या बढ़ाने के लिए अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त जैनरिक दवाइयों की दुकानें प्रत्येक जिले में खोली गयी हैं, यह सबके लिए फायदे की बात है। इसके अतिरिक्त संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की गयी है और इस वर्ष के लिए ऐसे 120 स्कूल्ज बनाने की मंजूरी मिली है तथा आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने नौंवी कक्षा से बढ़ाकर बारहवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल्ज में फ्री में शिक्षा देने की घोषणा की है। यह भी हमारी सरकार की ही देन है। हमारी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड करके करीब 4 हजार प्ले वे स्कूल खोलने का काम किया जा रहा है। हमारे भिवानी शहर के चारों तरफ 12 दरवाजे बने हुए हैं, हम इनका सौंदर्यकरण करना चाहते हैं। भिवानी में जो महापुरूष हुए हैं, इन 12 दरवाजों के नाम उन महापुरूषों के नाम पर रखे जायेंगे और जिन पर कुल 2 करोड़ रुपये की लागत आयेगी इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि भिवानी को सुन्दर बनाने के लिए हमें 2 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया जाये। भिवानी में हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान सैक्टर 31 ऐक्वायर हुआ था और सैक्टर 31 के लिए 350 एकड़ भूमि ऐक्वायर हो चुकी है। इस सैक्टर–31 में एक इन्डस्ट्रीज जोन, एक ट्रांसपोर्ट जोन बनाया जाये और जो सब्जी मंडी बनी हुई है, उसको वहां से शिफ्ट कर दिया जाये और इस मंडी के स्थान पर बैंक स्कवेयर की स्थापना की जाये। यह हमारे क्षेत्र वासियों की डिमांड है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि शहरी क्षेत्र में सीवरेज और पेयजल की पुरानी पाइप लाइनें डली हुई हैं, उनको ठीक करने का काम करवाया जाये। भिवानी शहर में वर्ष 1972 में चौधरी बंसी लाल जी ने यह पाइन लाइन डलवाने का काम किया था। हमारी सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों की अधिकतम आय सीमा को 1 लाख 80 हजार रुपये करने का काम किया है। इस बजट के माध्यम से इन परिवारों का भी ख्याल रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शहरी क्षेत्र की सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जाये क्योंकि हमारे सर्कुलर रोड की कुछ ऐसी सड़के हैं जो एन.एच. जींद और एन.एच. रोहतक के अंडर आती है। इन सड़कों को चौड़ा करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए मेरी मांग है कि इन सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जाये। हमारी एक रोड 148 (बी) हांसी गेट से हांसी शहर तक और बरवाला रोड तक जाती है। उस सड़क को चौड़ा करने और फोर

लेनिंग का कार्य करवाने का काम किया जाये। इसके अलावा मेरी यह भी मांग है कि दादरी रोड पर 70 एकड़ भूमि नगर परिषद की है उस भूमि पर गार्डन बनाया जाये या कोई आवास बोर्ड कॉलोनी बनाने का काम किया जाये और यदि हो सके तो सरकार गार्डन का नाम या आवास बोर्ड कॉलोनी का नाम डॉ. मंगल सेन के नाम पर रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे घर पर आज सुबह करीब 200 लोग पानी की समस्या को लेकर आये थे। उनका यह कहना था कि हमारे घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। उस समय हमारे टैंकों में भी पानी नहीं था माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो मैं उस दिन बीच में नहीं बोला था क्योंकि उस दिन माननीय मंत्री जी को इस बात ज्ञान नहीं था लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अगर चैक करवाकर देखेंगे तो आज की डेट में हमारे घर के किसी भी टेंक में पानी की एक बूंद भी इनको नहीं मिलेगी। इस सदन में भी हमारे अधिकारीगण बैठे हुए हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे भिवानी क्षेत्र के हिस्से का पानी किस क्षेत्र को दे दिया है। इस बात का मुझे पता नहीं है। मुझे इस बारे में भी बताया जाये। हमारी नहर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। दो महीने के बाद शायद दिनांक 19.03.2021 को नहर में पानी आयेगा। इस बात के लिए लोगों में हमारे प्रति नेगेटिविटी बनती जा रही है। मेरी सरकार से विनती है कि पानी की समस्या को दुरुस्त करने का काम किया जाये ताकि लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ सके। (विघ्न) भिवानी शहरी क्षेत्र में मीट शॉप्स खुली हुई हैं, उनको शहर से बाहर निकालकर इनके लिए एक अलग से मार्केट बनाई जाये जिससे शहर में स्वच्छता और सुन्दरता को बनाये रखा जा सके। इसके अलावा मेरी यह भी मांग है कि वहां पर सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग में एक्सीयन लगाया जाये। डिप्टी स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह डिमाण्ड है कि भिवानी शहर की ऑटो मार्किट में चौधरी देवी लाल जी की मूर्ति के पीछे सी.सी. रोड बनवाया जाये। इसी प्रकार भिवानी शहर की ऑटो मार्किट के सामने नगर सुधार मण्डल की मार्किट में सी.सी. के फर्श बनाये जायें। भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद् की भूमि पर पार्क बनाये जायें। लोहारू रोड पर सीमन सैंटर में पशु अस्पताल बनाया जाये। गांव मानेड़ और मनमाडवी गांवों में जल घर के नये टैंक बनाये जायें। गांव राजगढ़ और देवसर में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जायें। मेरे हल्के में जहां–जहां पर एस.सी. वर्ग की ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर एस.सी. सैंटर्ज

का निर्माण किया जाये। भिवानी शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑफिस में सभी खाली पदों को भरा जाये ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। डिप्टी स्पीकर सर, आदरणीय शिक्षा एवं वन मंत्री जी ने मेरे भिवानी में 10 हजार पौधे लगवाए। उस दौरान मैं भी उनके साथ था। इसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा एवं वन मंत्री का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से मेरे भिवानी में जहां–जहां पर भी बिजली की तारें लटकी हुई थी उन सभी को माननीय बिजली मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से खिंचवाने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय बिजली मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही माननीय परिवहन मंत्री जी को भी मैंने जो काम कहा वह उन्होंने अविलम्ब पूरा किया। मेरे भिवानी में श्री जय प्रकाश दलाल जी, कृषि मंत्री ने भी अपने विभाग से सम्बंधित सभी कामों को पूरा करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सी.): डिप्टी स्पीकर सर, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही सराहनीय बजट है। यह प्रदेश के सभी गरीबों का हित करने वाला बजट है। इस बजट को सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार बजट पेश किया है और उन्होंने दोनों ही बार टैक्स फ्री बजट पेश करने का काम किया है। यह एक बहुत ही अच्छा व सराहनीय काम है। इस बजट में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मैं आरक्षित वर्ग से आता हूं। यह मेरा दायित्व भी बनता है कि प्रदेश के आरक्षित वर्ग की सुरक्षा से सम्बंधित जो सवाल हैं और उनके हितकारी जो प्रश्न हैं विधान सभा में उनकी पैरवी करें और उनके समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत करवायें। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में प्राईवेट सैक्टर में मिलने वाली नौकरियों में हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 75 परसैंट नौकरियों को आरक्षित किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन 75 परसैंट आरक्षित नौकरियों के अंदर 20 परसैंट नौकरियां शिड्यूल्ड कॉस्ट के लिए आरक्षित की जायें ताकि हरियाणा प्रदेश के आरक्षित वर्ग के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। इससे प्रदेश के आरक्षित वर्ग के गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि सरकारी विभागों में तो इस समय बहुत ही

कम नौकरियां रह गई हैं। आज की तारीख में प्राईवेट सैक्टर ही है जिसमें कुछ नौकरी मिल सकती है। आरक्षित वर्ग के लगभग सभी लोग भूमिहीन हैं। उनको लगातार बेरोजगारी की मार को झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजगार के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। उनके पास एक मात्र मजदूरी का ही काम है। इसके दम पर वे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 10+2 तक ही पढ़ा सकते हैं। सदन में हमारी सरकार की तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि निकट भविष्य में प्रदेश में 500 डॉक्टर्ज की भर्ती की जायेगी। हैरानी की बात यह है कि आज भी हरियाणा प्रदेश में एस.सी. वर्ग के 200 डॉक्टर्ज का बैगलॉग पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन ही नहीं सकते। इसी प्रकार से वे ऊंची पढ़ाई करके इंजीनियर भी नहीं बन सकते। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर किसी भी प्रकार से सम्भव हो तो नियमों व कानूनों में थोड़ी बहुत वाजिब ढील देकर एस. सी. वर्ग के डॉक्टर्ज के बैकलॉग को पूरा किया जाये। सरकार के स्तर पर स्वच्छ भारत के बारे में भी बात की गई है। हमारी सरकार स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत के लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में हमारी सरकार के प्रयासों द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को भी शौचालय की सुविधा सहज में ही उपलब्ध करवा दी गई है। इसके लिए हमारी सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम ही होगी क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा काम है और इसके लिए हमारी सरकार की महिमा गाई ही जानी चाहिए। हमारी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया है जो पूरे समाज के लिए भी प्रत्येक दृष्टिकोण से हितैषी है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस के कनैक्शंज आबंटित किये गये। इनमें बहुत से गरीब इतने ज्यादा साधनहीन थे कि वे सपने में भी गैस का कनैक्शन लेने के बारे में नहीं सोच सकते थे। क्योंकि यह 1977 की बात है जब मैं विधान सभा में था उस समय गैस कनैक्शन एम.एल.एज. को मिले थे। उससे पहले तो एक साल की वेटिंग चलती थी। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि गरीब आदमी को भी गैस का कनैक्शन मिल सकता है। आज उनके घर में गैस जल रही है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। अब मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। इस बारे में हम सुझाव भी देंगे कि वहां पर क्या कमी है। गरीब आदमी कोई भूखा पेट न सोए इसके लिए फूड

सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ। उस समय मैं राज्यसभा में था। समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आया था कि हमें मुफ्त में खाने के लिए अनाज मिला। मिलता भी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। वहां बंटते–बंटते कहां पर गड़बड़ हुई कि डिपो होल्डर जो राशन की दुकानें हैं वे धीरे–धीरे करप्शन का अड्डा बनते चले गये। गरीब को लालच देकर वे लोग अंगूठा कहीं लगवा लेते हैं और अनाज कम देकर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी बनाई जाए क्योंकि यह सभी के लिए हितकारी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो गरीब आदमी होता है उसको थोड़ा बहुत लालच भी आ जाता है। वह सोचता है कि इसमें मैं कौन सा अमीर बन जाऊंगा इसलिए वह उस राशन को बेच भी देता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया है वह एक सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं तथा कस्तूरबा स्कूल खोलने जा रही मैं उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करता हूं। इसके अतिरिक्त सरकार खेल स्टेडियम खोलने जा रही है वह भी सरकार का सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों के साथ ही साथ एक चिन्ता का विषय यह भी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं और स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हम सभी सदस्य अगर अपने–अपने हल्कों में जा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 2–3 साल पहले जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे आज वे नहीं हैं और कई स्कूल तो बंद हो चुके हैं। यह जो ड्रॉप आउट रेट है इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ेगा। अमीर आदमी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कॉनवेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर कोई स्कूल बंद होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की एस.सी.,बी.सी. कमेटी का चेयरपर्सन हूं। कोरोना काल में स्कूल्स बंद थे और ऑनलाइन क्लासिज होती थी जो कि मोबाइल पर अटैंड की जाती थी। गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते हैं इसलिए कुछ दिन तो उन्होंने अपने पड़ोसियों के पास उनके मोबाइल पर क्लास अटैंड कर ली लेकिन बाद में पड़ौसी ने भी यह कह कर मोबाइल देना बंद कर दिया कि आपका तो रोज का काम हो गया है। इन सभी बातों को देखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त

मोबाइल प्रदान किये जायें, ताकि वे भी ऑनलाइन क्लासिज अटैंड कर सकें। सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त टैबलेट मुहैया करवाने का निर्णय लिया है लेकिन अभी तक उनको मुहैया नहीं करवाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द गरीब बच्चों को टैबलेट मुहैया करवाये जायें क्योंकि आज कल ऑनलाइन क्लासिज होती हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं तथा परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती हैं। इसी प्रकार से जो स्टाइपैंड की पॉलिसी है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब स्टाइपैंड की राशि बच्चे के अकाउंट में सीधी जाती है, स्कूल या कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाती है। बच्चे उस राशि को निकलवा कर खर्च कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल या कॉलेज छोड़ जाते हैं। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्टाइपैंड की राशि बच्चे के अकाउंट की बजाय संस्थान के अकाउंट में जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग की पॉलिसी सबसे खतरनाक है। आउटसोर्सिंग की पॉलिसी हमारी आरक्षण नीति को खा गई। आउटसोर्सिंग की पोलिसी में क्या होता है कि ठेकेदार बच्चों को डायरैक्ट भर्ती करता है। पांच साल के बाद सरकार उन्हीं बच्चों को रैगुलर करने की पॉलिसी में ला देती है। इससे आरक्षण तो खत्म हो गया लेकिन इस आउटसोर्सिंग की पॉलिसी से आरक्षण तो बाई पास कर दिया गया। यह बहुत गम्भीर विषय है और एक गरीब आदमी के लिए चिन्तनीय विषय है इसलिए आउटसोर्सिंग की पॉलिसी को खत्म किया जाए। यह ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल फेल हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इम्प्लॉइमैंट एक्सचेंज का क्या फायदा, इम्प्लॉइमैंट एक्सचेंज विभाग खोलने के क्या मायने? जैसे किसी आदमी ने इम्प्लॉइमैंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाया उसको तो वेटिंग करते–करते सात साल लग गये और ठेकेदार ने एक आदमी को आउटसोर्सिंग की पॉलिसी से डायरैक्ट भर्ती किया और वह अगले ही दिन नौकरी पर चला गया। अध्यक्ष महोदय, आपने इतनी जल्दी घंटी बजा दी। मैंने तो अभी तक तीन प्वायंट भी टच नहीं किये। फिर तो बोलने वाले या अकड़ने वाले सदस्य अच्छे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, यह घंटी मैंने नहीं बजाई है। यह घंटी तो और कहीं बज रही है। वैसे आपका टाईम हो गया है।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह घंटी आपने नहीं बजाई तो किसने बजाई है?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मैंने यह घंटी नहीं बजाई है। वैसे आपका टाइम हो गया है। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई बात निरर्थक नहीं है। सरकार द्वारा वर्ष 2008 में गरीब आदमियों को जो 100–100 गज के प्लॉट दिये गये थे। आज उनको वह प्लॉट दिये हुए 13 साल हो गये हैं, क्या इस 13 साल में उनके परिवार नहीं बढ़े, आबादी नहीं बढ़ी? एक–एक घर के अन्दर वह इतनी मुश्किल से रह रहे हैं कि यहां वह बात सुनाई भी नहीं जा सकती आप उन घरों में जाकर देखिये कि वे कैसे पशुओं जैसी जिन्दगी जी रहे हैं। मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो वे 100–100 गज के प्लॉट दिये गये थे उनमें भी 54 प्रतिशत प्लॉट दिये गये थे। मैं जब फाईनैंस कमीशन में था उस समय मैंने इन सभी का दौरा किया था। उसमें से 46 प्रतिशत को यह कह कर इग्नौर कर दिया गया कि पंचायत के पास जमीन ही नहीं है। अगर उन 54 प्रतिशत में भी देखा जाए तो जिन प्लॉट्स का पोजैशन मिला था उन प्लॉट्स पर दबंग लोग दोबारा से कब्जा कर गये। अगर आप चाहें तो इस बात के लिए मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पॉलिसी लागू की जाए और उसमें गरीब आदमियों को 100–100 गज के प्लॉट अलॉट किये जाएं। दूसरा एक प्वॉयंट जो जरूरी है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए उसमें कंविक्शन रेट बहुत चिन्तनीय विषय है। आज गरीब व दलित आदमियों के लिए कंविक्शन रेट घटने की बजाए बढ़ता जा रहा है। अब कंविक्शन रेट तो है नहीं इसलिए या तो लोग समझौता कर लेते हैं या समझौता करवा दिया जाता है या सरकारी वकील उनकी पैरवी नहीं करता है जिससे वह गरीब आदमी केस हार जाते हैं। इसमें मेरा यही कहना है कि इसकी एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो इस पर निगरानी करे क्योंकि सजाएं कम होती जा रही हैं और एट्रौसिटी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : ईश्वर सिंह जी, आप सरकार से कहकर शैड्यूल कास्ट कमीशन का गठन करवाइए।

श्री ईश्वर सिंह : बहन जी, उसमें तो सभी का फायदा है इसलिए शैड्यूल कास्ट कमीशन का गठन कराने में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, काफी समय हो गया है, आप वाईंडअप कीजिए।

श्री ईश्वर सिंह : सर, मुझे एक सैंकेंड में अपनी बात तो कह लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, काफी समय हो गया है, आप वाइंडअप कीजिए। अभी सी.एम. साहब ने भी जवाब देना है। इस तरह तो बाकी मैंबर बोले बिना रह जाएंगे।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर एक बाईपास पैंडिंग है उस बाईपास को बनाया जाए, एक हमारे वहां बस अड्डा नहीं है जिसका मैंने आज सवाल भी उठाया था और मंत्री जी ने उसके लिए हां की है। उसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। एक मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी पंचायत के पास जमीन बहुत है इसलिए वहां पर या तो मिल्क प्लांट लगाया जाए या फिर कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोली जाए। पंचायत उनके लिए जमीन भी देने के लिए तैयार है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि घग्गर नदी का पानी दूषित हो रहा है क्योंकि पंजाब की फैक्ट्रियों का सारा दूषित पानी उस घग्गर नदी में आता है और जहां–जहां से जिस एरिया में घग्गर नदी गुजर रही है उसमें चाहे गुहला चीका हो, चाहे रतिया हो, चाहे डबवाली हो वहां घग्गर नदी के पानी ने वहां के वातावरण को इतना दूषित कर दिया कि मेरे हल्के के एक गांव के अन्दर 8 लोग गले के कैंसर से मर गये हैं और उसका यही नतीजा है कि वहां का पानी बहुत दूषित हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, अतः अब आप वाइडअप कीजिए।

श्री ईश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, हांसी बुटाना नहर बनाई गई थी। इसको बनाने में सारे हरियाणा की ईंटे खप गईं, बजरी खप गई और पता नहीं क्या–क्या खप गया लेकिन फिर भी कोई परिणाम सामने निकलकर नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह नहर क्यों बनाई गई थी और किस परपज के लिए बनाई गई थी? क्या इसको बनाने के लिए किसी से कोई एप्रूवल ली गई थी? यह सभी जवाब सरकार की तरफ से दिए जायें । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैं पार्लियामैंट में राज्य सभा का सदस्य भी रहा हूँ और इस सदन का बहुत ही सीनियर सदस्य भी हूँ। मै देखता हूँ कि बिल इंट्रोड्यूज भी हो जाता है, उसके बाद क्लॉज, इनेक्टिंग फार्मूला व टाइटल यानि बिल को पास करने वाली सभी प्रक्रिया को औपचारिकता के तौर पर एडॉप्ट करते हुए बिल पास कर दिया जाता है जबकि नियम यह है कि कम से कम पांच दिन पहले सदस्य के पास बिल आये ताकि वह

उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके और चर्चा कर सके और इसके बाद ही बिल पास किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः ईश्वर जी, अबकी बार बिल पास करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले दिन बिल को इंट्रोड्यूज किया जायेगा, उसके बाद उस पर चर्चा की जायेगी और चर्चा करने के उपरांत ही हां–ना की मैजोरिटी के आधार पर बिल को पास या रिजेक्ट किया जायेगा? अब आप प्लीज बैठिए और सुभाष गांगोली को सदन में अपनी बात रखने दें?

श्री सुभाष गांगोली (सफीदों): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी शुरूआत अपने अन्नदाता किसान व कृषि क्षेत्र के विषय के साथ करना चाहूंगा। आज किसान और किसानी के अस्तित्व को बचाने का एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। हमारे किसान भाई आज आंदोलनरत हैं और पिछले 106 दिन से दिल्ली बार्डर पर बैठे हुए हैं। बजट के माध्यम से मुझे भी तथा हरियाणा की समस्त जनता को भी सरकार से यह आशा थी कि जो यह गतिरोध बना हुआ है, वह गतिरोध अवश्य दूर हो जायेगा। हम सब इस आशा के साथ इंतजार में बैठे थे कि सरकार कृषि पर अच्छा बजट देगी और अच्छी घोषणायें करने का काम करेगी और जिसकी वजह से दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठे किसान के दिमाग में कुछ ठंडक आयेगी और यह ठंडक गतिरोध को दूर करते हुए सामान्य माहौल बनाने का काम करेगी और बातचीत का रास्ता दोबारा से शुरू हो जायेगा और समस्या का हल निकल जायेगा लेकिन सरकार ने जिस तरह का यह बजट पेश किया है, ऐसा करके सरकार ने इस मौके को एक तरह से गंवाने का ही काम किया है। सरकार ने पिछले वर्ष यानि 2020–21 के बजट को भी 10.33 प्रतिशत कम करके पेश करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के एक मंत्री द्वारा बार बार पूछा गया था कि आखिरकार इन कृषि कानूनों में काला क्या है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा हमारे यहां किसी ने किसी के पास कोई बिहार का मजदूर जरूर लगा होगा। अगर उस बिहार के मजदूर से पूछोगे कि वह हरियाणा में मजदूरी करने के लिए क्यों आया है तो जवाब मिलता है कि उनके पास वैसे तो किसी के पास 7 एकड़, किसी के पास 5 एकड़ या 6 एकड़ जमीन है परन्तु उनके यहां वर्ष 2006 में ही यह कृषि कानून लागू हो गए थे जिसके कारण किसान होने के बावजूद आज उनको हरियाणा में आकर मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन कृषि कानूनों के अन्दर काला यह है

कि यह कानून किसान को मजदूर बना देने वाले कानून हैं, इसीलिए इनको काले कानून की संज्ञा दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, इन कानूनों में तो बाकायदा तौर पर किसानों को अलग–अलग प्रकार की छूट दी गई है और जो बात माननीय सदस्य बता रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा करके यह सदन को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अमरजीत ढांडा: उपाध्यक्ष महोदय, जींद शुगर मिल 17000 डेली कैपेसिटी की क्षमता रखता है उसको 40000 डेली कैपेसिटी की क्षमता करवाने की बात माननीय सदस्य सुभाष गांगोली ने नहीं कही। अगर किसान हित की बात करनी है तो यह बात कैसे इन्होंने छोड़ दी?

श्री सुभाष गांगोली: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री अपने बजट में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला एक नया एक्सप्रेस–वे प्रस्तावित किया है जो पानीपत–सफीदों–नगूरां–उचाना–प्रभुवाला–भूना–रतिया व सरदूलगढ़–कालांवाली व मंडी डबवाली को जोड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्सप्रेस–वे से जुलाना, जीन्द और सफीदों के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह ग्रीन फील्ड चारमार्गीय ऐसे क्षेत्र से ऊपर होकर जायेगा जहां सफीदों के स्थानीय लोगों को उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि सरकार जो स्टेट हाई–वे है, उसको ही चारमार्गीय करने का काम करे। हमारे क्षेत्र के लोगों ने उस रोड पर पिछले 40–50 वर्षों से काफी धूल खाई है और वहां पर दुर्घटनाओं को भी झेला है, इस प्रकार से इस एक्सप्रेस–वे के बनने से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे हल्के से संबंध रखने वाले दो पुलिस वाले शहीद हुए थे। एक श्री कप्तान सिंह, कलावती गांव का एस.पी.ओ. था और एक श्री रविन्द्र बुढ़ा खेड़ी गांव का था। दोनों की ड्यटी एक ही जगह थी। श्री रविन्द्र के पारिवारिक सदस्य के नाते उसके भाई को तो सरकारी नौकरी मिल गई लेकिन जो श्री कप्तान सिंह था जो पहले औद्योगिक सुरक्षा बल में से हटा दिया था और वह अब श्री रविन्द्र के साथ ही ड्यूटी कर रहा था, अब तक उसके पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि उसके बेटे को भी सरकारी नौकरी दे दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित हैं

और श्री कप्तान सिंह उन्हीं की इनैलो सरकार में औद्योगिक सुरक्षा बल में लगा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। मेरे क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की स्थिति सदन को बताना चाहता हूँ। मेरे सफीदों क्षेत्र के नागरिक अस्पताल में एम.ओ., एस.एम.ओ., डैंटल अस्सिटैंट, रेडियोग्राफर, एम.पी.एच.डब्लू. (फीमेल) आदि पद रिक्त पड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा का सारा नागरिक अस्पताल रिक्त पदों से भरा पड़ा हुआ है। यह हमारे क्षेत्र की समस्या आज से नहीं है बल्कि 4–5 वर्षों से जारी है। इस भारी समस्या को देखते हुए मैंने अपने क्षेत्र में एक बस पिल्लू खेड़ा ब्लॉक से दूसरी बस सफीदों ब्लॉक से गांव–गांव से जो गरीब बीमार व्यक्ति है उसको भगत फूल सिंह मैडिकल कॉलेज खानपुर कलां में फ्री में भेजने का काम किया हुआ है। सरकार को जब पता लगा कि सफीदों हल्के के जो बीमार लोग हैं उन्होंने अपना इलाज मैडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में करवाना शुरू कर दिया है तो सरकारी अस्पताल सफीदों के डॉक्टर्ज और मशीनों को मैडिकल कॉलेज, करनाल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बर्ताव सफीदों हल्के के लोगों के साथ क्यों होता है, इस बात का जवाब भी सदन में जरूर चाहिए। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बहुत से सवालों के जवाब सदन से लेने बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्षः गांगोली जी, आप अपनी बाकी रिटन स्पीच सदन के पटल पर रख दे, उसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जायेगा।

श्री सुभाष गांगोलीः उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्थिति एक बहू जैसी है। जैसे नई बहू घर में आती है और अपनी सास से घर का हिसाब–किताब मांगना शुरू करती है तो उसकी सास उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी धरैया ढकैया तो छेड़ीये नां बाकी घर–बार सारा तेरा। यह सरकार भी हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। धन्यवाद।

***श्री सुभाष गांगोलीः** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीदों में एक मांग यह है कि सफीदों शहर में अंबेडकर भवन का अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। दूसरी मांग यह है कि गांव गांगोली से भिड़ताना–धडौली रोड तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाये। इस रास्ते पर

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

किसनों की बड़ी आबादी बसती है। दूसरी तरफ देवी माता मंदिर है। यह आसपास के लोगों की श्रद्धा का केन्द्र है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी आबादी के आवाजाही के लिये इस्तेमाल होने वाला यह रास्ता बरसात के दिनों में दलदल में तब्दील हो जाता है। वहां पर श्रद्धालुओं और आमजन को आने–जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें डबवाली से पानीपत नैशनल हाइवे बनाने के लिए कहा है जोकि रतिया और भूना से होते हुए जाएगा । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है । इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही किसी तरह की कटौती की गई है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में 'अन्त्योदय उत्थान योजना' के तहत घोषणा की है कि एक लाख सबसे ज्यादा गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान, शिक्षा तथा रोजगार का प्रबंध किया जाएगा । इससे हमारे शिड्युल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और घुमन्तू जाति के लोगों को काफी फायदा मिलेगा । मैं एक संवेदनशील विषय को भी सदन में रखना चाहूंगा । घुमन्तू जाति के 7 लाख परिवार हैं और इनकी कुल जनसंख्या 20 लाख है । ये लोग झुग्गी–झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन इन लोगों के पास अपने पूरे डॉक्यूमैंट्स नहीं हैं । इनमें किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन परिवारों का सर्वे करवाया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सैंट्रल गवर्नमैंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमैंट के सैक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम अय्यर की सभी विभागों को लिखी गई चिट्ठी है । मैं उस चिट्ठी का एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं । इसमें लिखा है कि –

"Government of India is committed to providing these basic rights to these deprived communities and also to conduct a survey of such households in your State, through the State Government. The survey is proposed to be a household survey of the DNTs identified in your

State, covering demographic profile, socio-economic status. The formats of this survey and the modalities would be finalized in consultation with the State Governments."

उन्होंने यह चिट्ठी हमारे प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी को भी लिखी है । इस समय चीफ सैक्रेटरी भी हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं । मैं उनको यह चिट्ठी दे दूंगा । श्री सुब्रमण्यम अय्यर जी ने कहा है कि इनके लिए जो सर्वे किया जाएगा उसका सारा खर्च भी केन्द्रीय सरकार ही वहन करेगी । अतः यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी भी एक संवेदनशील इंसान हैं और वे हमेशा इन घुमन्तू जाति के लोगों की चिन्ता करते रहते हैं । इस समय सदन में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब भी बैठे हुए हैं । जब हुड्डा साहब सी.एम. थे तो रैलियों में कहा करते थे कि अगर मैं भी थारा भला न कर सका तो कोई कर भी नहीं सकेगा । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन घुमन्तू जाति के लोगों के लिए डी.एन.टी. बोर्ड का गठन किया है । इस बोर्ड के गठन होने से पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी लेकिन अब स्वयं मैं और माननीय सदस्य श्री रामकरण काला जी डी.एन.टी. बोर्ड से चुनकर विधान सभा में आये हैं । अब सरकार ने आयुष्मान योजना में डी.एन.टी. बोर्ड को भी शामिल किया है । इसके तहत अब डी.एन.टी. बोर्ड का 5 लाख रूपये तक की राशि का इलाज फ्री में हो जाएगा । मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रतिया की कुछ मांगें सदन में रखना चाहूंगा । अभी माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी कह रहे थे कि घग्गर नदी रतिया और चीका के एरिया से होकर गुजरती है । इसमें फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहता है । इससे वहां के लोगों में कैंसर और हैपेटाइटिस–सी बीमारी बहुत ज्यादा पनप रही है । नगर पालिका, रतिया ने रतिया में नहरी पानी के वाटर वर्क्स के लिए 25 एकड़ जमीन दी है । अतः मेरी मांग है कि वहां के निवासियों को इन बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए वहां पर नहरी पानी का वाटर वर्क्स बनाया जाए । इसके अलावा हमारी मांग है कि हमारे नागपुर ब्लॉक को सब–तहसील बनाया जाए । इसके साथ ही मेरे हल्के के सबसे बड़े गांव बिरड़ाणा को महाग्राम योजना में लेकर उसको ब्लॉक का दर्जा दिया जाए । अभी माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी कह रही थी कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एस.सी. कमीशन का

गठन किया जाए। यह पिछले 5 सालों से पैंडिंग है। इस एस.सी. कमीशन का गठन होने से एस.सी. कैटेगरी के लिए जो योजनाएं बनायी जाती हैं, उनकी मॉनीटरिंग की जा सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूंगा। उन्होंने घुमन्तू जाति के 3–4 प्रोग्राम्ज में शिरकत की थी और उस दौरान उन्होंने इसको बनाने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त पंचकुला में डी.एन.टी. भवन और छात्रावास का निर्माण करवाने की घोषणा की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि इन घोषणाओं को पूरा करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फतेहाबाद में भागीरथ जयंती के प्रोग्राम के दौरान कुरूक्षेत्र में 500 गज का प्लॉट ओल्ड धर्मशाला के लिए देने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस कार्य को करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी कुछ और मांगे भी हैं। अगर आपकी सहमति हो तो इनको भी प्रौसीडिंग का पार्ट बना लिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। अगर आपकी इसके अतिरिक्त कुछ और मांगे हैं तो उनको रिटन में दे दे, उनको प्रौसीडिंग का पार्ट बना दिया जाएगा।

***श्री लक्ष्मण नापाः** अध्यक्ष महोदयः रतिया शहर में नहरी पानी के लिए जल घर बनवाया जाए। रतिया शहर में एक पार्क का निर्माण करवाया जाए। रतिया में मिनी सचिवालय का निर्माण हो रहा है, उसे जल्दी पूरा किया जाए। रतिया विधान सभा में स्थित गांव भिरड़ाना को ब्लॉक घोषित किया जाए और उसे महा ग्राम योजना में शामिल किया जाए। नागपुर ब्लॉक बना हुआ है, उसे सब तहसील बनाया जाए। घुमन्तू जाति विकास बोर्ड को घुमन्तू जाति विकास निगम बनाया जाए ताकि केन्द्र की योजनाओं का लाभ मिल सके। घुमन्तू जातियों का सर्वे घुमन्तू जाति विकास बोर्ड के सहयोग से करवाया जाए।

***श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) (एस.सी):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2020 में

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

प्रदेश में कोविड–19 की वजह से लगे लॉकडाउन से करोड़ों रूपये के घाटे की चपेट में आने के बावजूद भी बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है। यानी प्रदेश की इन्कम के सारे साधन बन्द होते हुए भी जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की बात है कि इस बजट की विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी तारीफ की है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्सान की शक्ल से तारीफ नहीं की जाती है। इन्सान की विकास और उसके कामों के कारण तारीफ की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 सालों के प्लान में जो विकास कार्य किये हैं, उन कार्यों को देखते हुए हमने बिना किसी डिमांड के खुद जाकर सरकार का समर्थन किया है। हमारे हल्के के कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में करनाल जिला धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और धान की खेती को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। करनाल से होकर काफी नहरें गुजरती हैं, फिर भी वहां के किसानों की भूमि सिंचित होने से वंचित रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी है और करनाल उनका चहेता जिला भी है। वहां के किसान उनसे बहुत प्यार करते हैं और यह उनका विधान सभा क्षेत्र भी है। वहां के किसानों को धान की खेती की सिंचाई के लिए नहरों का पानी दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि नहरों का पानी किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल और की है। जैसे किसी भी मुर्दे को शमशान घाट में लेकर जाते हैं और उसके दाह संस्कार के लिए दाग लगाया जाता है तो उसी समय कई बार तूफान आने की वजह से वहां पर आसपास के खेतों में आग लग जाती थी। जिससे उन खेतों की फसलें जलकर नष्ट हो जाती थी। इसके लिए हर हल्के के गांवों के शमशान घाटों/कब्रिस्तान को पक्का करवाने, चार दीवारी बनवाने, गेट लगवाने, नल और शैड लगवाने की पहल की है। इसके अतिरिक्त अगर किसी शमशान घाट का रास्ता मेन रोड से 10 फुट का है या 10 किलोमीटर का रास्ता है, उसको भी पक्का करवाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन और है। मैंने परसों निगदू में एक कॉलेज बनवाने की बात रखी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध

करना चाहूंगा कि जो निगदू में कॉलेज बनाने की डिमांड की थी, वह सिर्फ गर्ल्ज कॉलेज बनाने के लिए ही नही थी। बल्कि वहां के सभी बच्चे दु:खी हैं क्योंकि वहां पर कॉलेज बहुत दूर है, इसलिए निगदू में कॉलेज को शिक्षा के अधिकार के आधार पर दिया जाए। सरकार पंचायत की जमीन पर बी.पी.एल. परिवारों के लिए जो कॉलोनी काटी जाती है, वहां पहले से ही 11 हजार हाइटेंशन वोल्टेज की तारें गुजरती है। जब बी.पी.एल. के परिवार वाले उस कॉलोनी में मकान वगैरह बनाते हैं तो कई बार मकान बनाते समय हादसे हो जाते हैं, जिससे जान माल का नुकसान बना रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से निवेदन है कि सरकारी खाते से स्पेशल ऐस्टीमेट बनाकर इस 11 हजार हाइटेंशन वोल्टेज तारों को हटाने का काम किया जाये। जैसा कि आपको पता ही है कि जहां पर सेम की जमीन होती है वहां पर अक्सर आये दिन झगड़े होते रहते हैं। हमारे एक माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा था, मैं उनकी बात पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज की संख्या ज्यादा होने के कारण लोगों के विचार बदल जाते हैं। मैं इस पर सदन में एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सदन में बी.पी.एल. परिवारों के बारे में कहा है कि इनके मकानों के ऊपर 11 हजार वोल्टेज की हाइटेंशन तारें गुजर रही हैं तो मैं इनको इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि उन तारों को सरकारी खाते से हटवा दिया जायेगा।

श्री धर्मपाल गोंदर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस सदन में डॉक्टर के विषय पर पुराने जमाने की बात सुनाना चाहता हूं कि एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव की जनसंख्या बहुत कम थी। उसमें दो डॉक्टर काम करते थे। एक पशुओं का डॉक्टर था और दूसरा इन्सानों का डॉक्टर था। उन दोनों डॉक्टर्ज का आपस में बड़ा प्यार था। जो इंसानों का डॉक्टर था उसके पास फ्रिज नहीं था और दूसरे के पास फ्रिज था। इन दोनों डॉक्टर्ज की दवाइयां उस फ्रिज में रखी होती थी। एक बार गांव में एक बुजुर्ग को काफी दिनों से भूख नहीं लग रही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर्ज की संख्या ज्यादा होने के कारण लोगों के विचार बदल जाते हैं। किसी कारणवश उस दिन इंसानों का डॉक्टर गांव में नहीं था तो दूसरे पशुओं वाले डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा कि जो फ्रिज में पेट दर्द वाला इंजेक्शन पड़ा हुआ है, उसको ले आओ तो वह कंपाउंडर भागा–भागा पशुओं वाला इंजेक्शन ले आया। उस डॉक्टर ने भी उस

इंजेक्शन को नहीं देखा और थोड़ी देर बाद उस पशुओं वाले डॉक्टर को भी उस इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई तो उसने कंपाउंडर से पूछा कि इंजेक्शन कहां गया अभी तो फ्रिज में पड़ा हुआ था तो उस कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब गलती से वह इंजेक्शन तो उस बुजुर्ग को लगाने के लिए दे दिया गया है तो उसने जल्दी से उसको फोन किया तो उस बुजुर्ग ने वह फोन उठा लिया तो उसको कहा आपको अभी इंजेक्शन लगाया तो नहीं है। उसने कहा कि इंजेक्शन लगा दिया है। पशुओं वाले डॉक्टर के पेरों तले जमीन खिसक गई तो उस डॉक्टर ने अपने मन में सोचा कि यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? उस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है परन्तु मेरा घास खाने का मन कर रहा है। (हंसी)

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट के अंदर लाल डोरे का जिक्र किया गया है यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार लाल डोरा खत्म करने जा रही है और यह जनता की डिमांड भी थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह कहा है कि 400 गांवों का लाल डोरा समाप्त करके वहां के जो निवासी हैं। जिनके पास अपने घर के टाइटल डीड नहीं थी उनकी टाइटल डीड बनवा दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है इसलिए अच्छे काम की सराहना की जानी चाहिए। मैंने सरकार को दो–चार चिट्ठियां लिखी थी कि मेरे हल्का रादौर में एक ओल्ड कॉलोनी बनी हुई है। इस कॉलोनी में 150 घर हैं। कोई 100 गज में बना हुआ है, कोई 50 गज में बना हुआ है और कोई 75 गज में बना हुआ है। मैंने सरकार को कई बार लिखा है कि इनको बिजली और पानी के कनेक्शन दिये जायें। बिजली मंत्री जी का जवाब मेरे पास आया उन्होंने लिखा कि जब पंचायत थी उस समय इस ओल्ड कालोनी को बिजली के 108 कनैक्शंज दिये गये थे। उनकी यह बात ठीक है लेकिन जब से यह नगरपालिका बनी तब से वहां पर एक भी बिजली या पानी का कनैक्शन नहीं दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि नगरपालिका बनने से उनको तो उल्टा नुक्सान हो गया। वहां पर जो गरीब लोग बस रहे हैं उनको भी टाइटल डीड, यानि स्वामित्व जोकि सरकार की स्कीम है, मिलनी चाहिए ताकि सारे अधिकार उनको भी मिल सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

जो हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी उसने धौलीदारों के लिए एक स्कीम शुरू की थी कि जिनके पास गांवों की जमीनें हैं उनकी रजिस्ट्रियां बननी शुरू हुई थी ताकि उनको उन जमीनों का स्वामित्व मिल जाये और उनकी टाइटल डीड बन जाये। उस समय 60 से 65 परसैंट धौलीदारों की टाईटल डीड बनी भी थी। उसके बाद जो 35 से 40 परसैंट रह गये थे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वह काम बंद हो गया। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रदेश के जो धौलीदार जमीनों की टाइटल डीड से वंचित है उनकी जमीनों की भी टाइटल डीड जल्दी से जल्दी बनानी शुरू की जाये ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बजट के पेज नम्बर 46 और पैरा नम्बर 186 के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास का जिक्र है। इस बाबत मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने अल्फाज में कहा है कि कुछ एजेंसियां हमारी ऐसी हैं जोकि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि विधायक आदर्श ग्राम योजना अपनी तरह की एक अनूठी योजना है। वह भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री जी ने विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। यह मुझे मालूम नहीं है कि वह कितने सालों तक चली है। हम तो जब से विधायक बने हैं हमारे पास उसी समय एक पत्र आ गया था कि उस योजना को अभी होल्ड पर रख लिया गया है। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जब वह योजना अनूठी और अच्छी है तो उसको जल्दी से जल्दी शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस योजना में गांवों के विकास के कार्यों में विधायकों और ग्राम के लोगों की सीधे–सीधे बराबर की हिस्सेदारी है। अगर यह योजना जल्दी से जल्दी शुरू की जाती है तो इससे प्रदेश में सत्ता और शक्ति का भी विकेन्द्रीकरण हो जायेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस योजना का होल्ड का समय समाप्त किया जाये। इसके साथ ही साथ उसकी राशि को भी 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया जाये। यह मेरा सरकार से अनुरोध है। डिप्टी स्पीकर सर, बजट में इसी प्रकार से पेज नम्बर 51 और पैरा नम्बर 198 में प्रदेश में सड़कों के बारे में जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो 6 करम और इससे ज्यादा चौड़ाई के कच्चे रास्ते हैं उन सभी को पक्का किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से आग्रह है कि 6 करम के कच्चे रास्ते इस

समय प्रदेश में ज्यादा नहीं है इसलिए जो 5 करम के कच्चे रास्ते हैं उन 5 करम के कच्चे रास्तों को बनवाना शुरू किया जाये ताकि लोगों को कहीं पर भी आने जाने में सुगमता हो सके। मेरे हल्के की 15–20 सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। अगर संसदीय कार्य मंत्री की सहमति हो तो मैं उन्हें एक दिन उन तमाम सड़कों पर ले जाना चाहूंगा। अगर ये मेरे साथ उन सड़कों पर चलने के लिए तैयार हो गये तो उन सड़कों पर चलने के बाद इनके ऊपर इतनी मात्रा में धूल जम जायेगी कि इनको कोई भी पहचान नहीं पायेगा। इसलिए सड़कों की तरफ भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जिन सड़कों की जर्जर हालत के बारे में हम सदन में प्रश्न लगाते हैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब में कहा जाता है कि इस सड़क की हालत ठीक है इसलिए इसकी रिपेयर की कोई जरूरत नहीं है। एक हमारे हल्के से सड़क गुजरती है जो कुरूक्षेत्र से यमुनानगर तक जाती है। यह एक स्टेट हाईवे है और उसको फोरलेन करके नैशनल हाईवे करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार घोषणा कर चुके हैं, अगर तारीख पूछनी हो तो मैं वह भी बता दूंगा, लेकिन अभी तक यह सड़क फोरलेन नहीं बनी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी फोरलेन बनाया जाये। इसी प्रकार से कलानौर से पंचकुला तक जो सड़क बनाई गई है उसमें केवल एक बाई पास हमारे जिले में है। उसके बाद इसमें न ही तो कोई अंडरपास बनाया गया है और न ही कोई ओवरब्रिज बनाया गया है जिसके कारण हर रोज वहां पर एक्सीडैंट्स होते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्षः सैनी साहब, आपकी जो डिमांड्ज हैं वे आप लिखित में दे दीजिए उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

***डॉ. बिशन लाल सैनीः** उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं अपनी डिमांड्ज लिखित में दे देता हूं उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाये।

1. रादौर का क्षेत्र सब्जी उगाने में अग्रणी है इसलिए रादौर में सब्जी मण्डी की स्थापना की जाये ताकि किसानों को सब्जी बिक्री में दिक्कत न आये।

2. यमुनानगर से करनाल वाया जठलाना, गुमथला रोड पर एक ट्रॉमा सैन्टर बनाया जाये ताकि उस रोड पर एक्सीडैंट्स होने पर तत्काल मदद मिल सके।

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया।**

3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को रादौर विकास रैली में कुरूक्षेत्र–यमुनानगर रोड को फोरलेन बनाने की घोषणा की थी। इसी प्रकार से 28 अक्तूबर, 2018 को दोबारा गांव दामला की जनसभा में इसी सड़क को बनाने की घोषणा की थी, अतः इस सड़क को फोनलेन बनाया जाये।

4. रादौर के सरकारी अस्पताल को 25 बैड से 50 बैड का बनाने की घोषणा की हुई है अतः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसे जल्दी से जल्दी बनवाया जाये।

5. विधायक आदर्श ग्राम योजना को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाये क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस योजना को अनूठी योजना माना है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसे लागू भी किया जाये और इसकी राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5 करोड़ किया जाये।

6. मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यमुनानगर के कस्बा मुस्तफाबाद में किसानों की एक सोसायटी है जिसका नाम दी मुस्तफाबाद फार्मर्स सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी है। इस सोसायटी में लगभग 4000 किसानों के खाते हैं और ये किसान यहां से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। इस ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जबकि दूसरी सोसायटीज में सरकार किसान से कोई ब्याज नहीं ले रही है। अगर लेती है तो 2 स 4 प्रतिशत तक सालाना ब्याज लिया जाता है। यह सोसायटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है और इस बैंक का सोसायटी पर कर्जा है। बैंक चाहता है कि उसे लम्प–सम 50 लाख रुपये अगर सहकारी/सरकारी बैंक अदा कर दें तो इस सोसायटी के किसान भी सरकार की योजना का लाभ उठा सकेंगे, अतः इस पर विचार किया जाये।

7. मेरे हल्के रादौर की टूटी सड़कों को मजबूत व चौड़ा किया जाये। धन्यवाद।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। यह जो वर्ष 2021–2022 का बजट पेश किया गया है उसे हर वर्ग का ध्यान रख कर बनाया गया है इसलिए मैं इस बजट की सराहना करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। इस बजट में जो प्रावधान दिये गये हैं सबसे पहले मैं उनमें से एक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस बजट में प्रावधान है कि किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जायेगी। पानी कई बार किसानों के लिए वरदान साबित होता है तो कई बार वह नुकसानदायक भी साबित होता है। उसी कड़ी में हमारी सरकार द्वारा वाटर रीचार्ज के लिए बोर वैल लगाये गये हैं। जिस जमीन में नीचे का पानी

खारा है वहां का पानी निकल नहीं पाता है और उस एरिया में सेम की समस्या खड़ी हो जाती है। उन एरिया में जीरी या और कोई दूसरी फसल लगाई जाती हैं। कई बार उस एरिया में वे दोनों ही फसल खराब हो जाती हैं। हरियाणा सरकार ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रीचार्ज बोर लगाये हैं और उसके लिए बजट में प्रावधान किया है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि पानी इस प्रदेश और देश के किसानों के लिए कितना अहम है यह आप सभी जानते हैं। आज प्रदेश में सिंचाई पानी की तो कमी है ही लेकिन पीने का पानी भी बहुत कम है। सिंचाई के पानी का समुचित प्रबंध हो, वह उचित तरीके से खेत में लगे उसके लिए मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जो खाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पक्का किया जाए। यहां तक कि किसानों के लाल रंग के खाले भी कच्चे पड़े हैं जिसके कारण सिंचाई में ज्यादा पानी लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पानी के अधिक से अधिक उपयोग के लिए खालों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पक्का किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी डॉ. बिशन लाल जी कच्चे रास्तों का जिक्र कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने पिछले बजट में भी और उससे पहले भी जब सरकार थी उस समय भी कहा था कि इस प्रदेश के अन्दर 6 करम या इससे ऊपर के रास्तों को बी. एण्ड आर. विभाग बनाएगा और वे सारे रास्ते पक्के किये जाएंगे। मैं यह मानता हूं कि 6 करम व उससे ऊपर के रास्ते हरियाणा प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी विधान सभा होगी जिसमें एक–एक, दो–दो रास्ते मुश्किल से पक्के होने बचे हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हरियाणा प्रदेश में जो 4 और 5 करम के रास्ते हैं उनको बी. एण्ड आर. विभाग नहीं बनाता है। उनको मार्किटिंग बोर्ड बनाता है और आज मार्किटिंग बोर्ड की क्या हालत है वह हम सभी को पता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 4 और 5 करम के रास्तों को भी बी. एण्ड. आर. विभाग के अण्डर करके उनको भी पक्का करवाने का काम किया जाए क्योंकि मार्किटिंग बोर्ड के पास जो टैक्स के रूप में पैसा आता था वह धीरे–धीरे कम करके खत्म कर दिया गया जिससे आज मार्किटिंग बोर्ड के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं इसलिए यह मेरा सरकार से अनुरोध है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके लिए सभी माननीय सदस्य हौस्पीटल्ज के बारे में बात करते हैं। इंसानों के हौस्पीटल्ज की बात तो सभी करते हैं लेकिन पशुओं के लिए

हौस्पीटल्ज की बात कोई–कोई सदस्य करता है। हरियाणा प्रदेश की सरकार बार–बार यह कहती है कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने में किसान के लिए पशु अह्म है और हमारे पशु हौस्पीटल्ज बहुत–बहुत दूरी पर हैं। मैं यह नहीं कहता कि वैटरनरी सर्जन हर गांव में बैठे लेकिन ऐसा प्रबंध जरूर होना चाहिए कि हर गांव में वी.एल.डी.ए. जरूर बैठे, क्योंकि व्यक्ति तो किसी दूसरे गांव व शहर में जाकर भी अपना इलाज करवा सकता है लेकिन पशुओं को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक और खास बात है कि मनुष्य के हौस्पीटल्ज के लिए तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्ज बनानी पड़ती हैं लेकिन पशुओं के हौस्पीटल के लिए तो एक कमरा, एक खटकड़ा और एक वी.एल.डी.ए. इन तीन चीजों की जरूरत है और हौस्पीटल बन जाता है। अगर सबसे कम खर्चे में कोई चीज चल सकती है तो वह पशु हौस्पीटल है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अब बैठे नहीं हैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे जो नये हौस्पीटल्ज खोलने की बात करते हैं उस संबंध में मैं मेरे हल्के के दो गांवों के बारे में कहना चाहूंगा जिनके बारे में मैंने पिछले सैशन में भी बात उठाई थी। उनमें से एक लाडवा गांव था जिसके हौस्पीटल की बिल्डिंग न होने की वजह से पंचायत घर के अन्दर उस हौस्पीटल को चलाया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा सातवड़ गांव है उसके हौस्पीटल को भी मजबूरी में एक चौपाल के अन्दर चलाना पड़ रहा है इसलिए मेरे हल्के के इन दोनों गांवों में हौस्पीटल की बिल्डिंग बनाने का काम किया जाए। यह मेरे हल्के की बहुत ही जरूरी मांग है। बाकी मांगे तो मैं पहले भी बार–बार उठाता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं दो बात और कहना चाहूंगा जोकि कहीं न कहीं दोनों पक्षों पर जाकर लगेंगी। आज ही के दिन सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने थोड़ी ही देर पहले किसी विशेष समुदाय का जिक्र करके उस समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी करने का कार्य किया है। उस समुदाय के ऊपर जब–जब भी समय रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : जोगी राम जी, उस माननीय सदस्य ने अपनी क्लीयरेंस दे दी है। अब बार–बार उस बात को दोबारा कहकर के सदन का समय जाया न करें।

श्री जोगी राम सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं एक समुदाय की बात कर रहा हूं। मैं उस समुदाय विशेष की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जोगी राम जी, उस माननीय सदस्य की विडीयो–ऑडियो भी आ गई हैं। उनको देख लिया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।

श्री जोगी राम सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा या ठीक कहा है। मैं तो समय की बात कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि समुदाय विशेष के ऊपर जब–जब भी समय बीतता गया और उस समय के जो–जो भी शासक रहे उस समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की गई लेकिन मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस समुदाय विशेष ने जब कभी भी इस देश के ऊपर, इस समाज के ऊपर, किसी वर्ग के ऊपर ज्यादत्तियां हुई वहीं समुदाय सबसे आगे सबसे पहले खड़ा हुआ। इसका ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं के अंग्रेजी शासन के अंदर जब किसान और किसानी बिल्कुल खतरे में थी तो इसी समुदाय के एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी और किसान और किसानी को बचाने का काम किया था। जिस समाज को कोई लुटेरा बताता है, आतंकवादी बताता है, आंदोलनकारी बताता है और यह भी कहते हैं इस समुदाय ने लोगों को घरों के अंदर रोकने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समुदाय के बगैर बताओ कब काम चला है? चाहे 1962 का युद्ध हो चाहे 1971 युद्ध हो, इसी विशेष समुदाय ने सबसे आगे आकर इस देश और प्रदेश की हर संभव मदद करने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे समुदाय के उपर कभी भी टिप्पणी करने की कोशिश मत करना क्योंकि जिसके अंदर भलाई करने का मादा होता है केवल वही व्यक्ति किसी दूसरे की मदद कर सकता है। सदन में बार बार कहा जा रहा है कि हम किसान हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा व्यक्ति किसान नहीं है या किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आगे आकर किसानों के लिए काम करता है? आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है क्या किसी ने उनके साथ वहां पर जाकर बात करने की कोशश की? अपनी किसानी को बचाने के लिए किसान आज मरने को मजबूर हो रहे है, के दृष्टिगत मेरा अनुरोध है कि हरियाणा सरकार के साथ साथ हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम वहां पर जाकर किसानों को मनाने का काम करते हुए किसान को बचाने का काम करे। 12 तारीख को एक मुद्दा यह भी आया कि किसानों की भलाई के विषय के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन करने का काम किया था कि आखिरकार किसानों के लिए किस तरह से क्या अच्छा किया जा सकता है। उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन सदस्यों के नाम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दिए थे, वे दोनों सदस्य उन कमेटी से रिजाइन कर गए बजाय यह सुझाव देने के

कि किसानों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। अतः अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा विपक्ष को भी इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि समस्या का हल निकालने पर जोर देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, श्री भारत भूषण बतरा और श्रीमती किरण चौधरी ने इस कमेटी से इसलिए अपने नाम वापिस लिए क्योंकि सरकार किसानों के विषय पर गम्भीर नहीं थी और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है तो ऐसी अवस्था में कमेटी का क्या औचित्य रह जाता है?

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, माननीय सदस्य ने कोई गलत बात तो नहीं कही बल्कि जिन सदस्यों ने इस कमेटी से नाम वापस लिए थे, उन्होंने तो केवल उन लोगों के बारे में सदन को बताने की ही कोशिश की है।

श्री जोगी राम सिहागः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच यह थी कि किसी प्रकार से भी हो पर किसानों का भला हो जाये लेकिन यह लोग सदन में चिल्लाने लग जाते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे विकट समय में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए? जिस कमेटी में इनके सुझावों की जरूरत थी उस कमेटी से तो यह लोग पीछे भाग गए है? इस कमेटी के माध्यम से यह लोग अपने विचार रख सकते थे कि किसानों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है लेकिन इन लोगों ने ऐसा करने की बिल्कुल नहीं सोची। चलो कोई बात नहीं इस तरह के कामों के लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन लाल बडौली (राई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के हित के लिये जो बजट सदन के पटल पर रखा है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई भी देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व वाली सरकार ने सभी योजनाओं का पिछले साल की तुलना में बजट बढ़ाकर वर्ष 2021–22 के लिए 155645 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस बजट से प्रदेश में सड़कों, स्कूलों, अस्पतलों आदि के निर्माण कार्यों में तेजी आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, 'सक्षम युवा योजना' के तहत अगले साल एक वर्ष के अंदर 1.5 लाख सक्षम युवाओं को लाभ दिया जायेगा। सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश हित में होगा, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय

की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य श्री जोगी राम सिहाग ने भी अपने विचार सदन में व्यक्त किये थे। जब किसानों की भलाई के लिये केन्द्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई उसी दिन से उस कमेटी को लेकर तरह–तरह की बयानबाजी शुरू हो गई थी। कुछ लोग तो किसानों की आड़ में राजनीति की दिशा देने का काम कर रहे हैं। सभी को पता है कि आज हमारा किसान आंदोलनरत है और दिल्ली के बॉर्डर्ज पर पिछले तीन महीने से बैठा हुआ है। राई विधान सभा क्षेत्र में जो किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं और उस आंदोलन को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, यह हमारे लिये बड़ा चिंता का विषय है। वहां राजनीति पार्टी के नेता अपने–अपने लाभ के लिये अपने विचार वहां पर रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सभी सदस्यों को मिलकर प्रदेश हित के लिये और किसानों की भलाई के लिये ही बातें सदन में रखनी चाहिए। आज इस किसान आंदोलन के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो गये हैं। उद्योग और फैक्ट्रीज बंद होने के कारण हमारे मजदूर भाई बेरोजगार हो गये हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है। किसान आंदोलन के कारण आज लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गये हैं। इस आंदोलन के कारण जिन व्यापारियों के काम धंधे बंद हो गये हैं अर्थात् पिछले तीन महीने से जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनकी सहायता करने के लिये भी सरकार को आगे आना चाहिए। किसान आंदोलन के कारण दुकानदार तो बेरोजगार हुए हैं, साथ में जो उनकी दुकानों पर लोग काम करते थे, दुकान बंद होने के कारण वे भी बेरोजगार हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की चिंता सरकार को बराबर करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहता हूँ कि वाटर रीचार्ज टयूबवैल्ज कनैक्शन बरसात के दिनों से पहले लग जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग एक लाख रुपये का कर्जा है। फिर भी सरकार लोगों के मकान नहीं बना रही है और उनको कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है। शहरों के एंट्री प्वॉयंट्स पर बड़े–बड़े गेट बना रही है। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि कर्ज लेकर लाखों रुपये के बड़े–बड़े गेट बनाने की क्या जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सुनकर मैं बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं सरकार कैसे चल रही है। इस सरकार में इतने बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं, यदि सरकार उन सभी घोटालों की रिकवरी कर ले तो मेरे ख्याल से प्रदेश के ऊपर से आधा कर्ज तो वैसे ही उतर जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के से संबंधित विषय सदन में रखना चाहूंगा नहीं तो आप घंटी बजा दोगे और मेरे हल्के की बात रह जाएगी । मैंने बजट की अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छपी हुई कॉपी पढ़ ली लेकिन मुझे इसमें अपने हल्के असंध का कहीं पर भी जिक्र नहीं दिखाई दिया । असंध करनाल जिले में होते हुए भी एक बैकवर्ड इलाका है । वहां से अगर किसी को हॉस्पिटल में भी जाना हो तो वह भी 45 किलोमीटर दूर पड़ता है । इसके अलावा मेरे हल्के का आखिरी छोर करनाल शहर से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है । अभी माननीय सदस्य श्री धर्मपाल गोंदर जी मुझसे कह रहे थे कि आप डॉक्टरों की बात मत करना । मेरा कहना है कि हमें कोई एक डॉक्टर तो दे दो जो मरीज को झूठा–मूठा ही इंजैक्शन लगा दे चाहे केवल पानी का ही लगा दे । इससे उसको कम से कम करनाल तक जाने का हौंसला तो बन ही जाएगा । अभी सदन में माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी बैठे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इनसे कहना है कि असंध में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने के लिए पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं । वहां पर भी बड़े तगड़े–तगड़े जवान लड़के हैं और मौका मिलने पर वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सकते हैं । अतः उनके लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए । इसके अलावा मेरा कहना है कि असंध भी हरियाणा प्रदेश का ही एक हिस्सा है । इसके साथ ही मेरी मांग है कि मेरे हल्के के गांव बला में गर्ल्स पॉलीटैक्निक कॉलेज बनवाया जाए । मेरे हल्के में एक एजूकेशन की बहुत कमी है । वहां पर एक कॉलेज बनने लग रहा है । उसके बनने की तारीख जून, 2019 थी लेकिन वह कॉलेज आज तक भी कम्पलीट नहीं हुआ है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि उस कॉलेज को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि मुझे इसके बारे में अगले सत्र में प्रश्न न पूछना पड़े । अब मैं सफाई कर्मचारियों की बात करना चाहूंगा । सरकार ने सफाई कर्मचारी लगाने का एक नया तरीका निकाला है । अब सरकार एम.सी. में इनको लगाने के लिए टैण्डर कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि इनको तनख्वाह कितनी दी जा रही है ? इनको तनख्वाह सिर्फ 7,000 रूपये प्रतिमाह दी जा रही है । यह बहुत ही शर्म की बात है । हम अपने हरियाणा को नंबर वन

बनाने की ओर अग्रसर हैं । क्या उन गरीब आदमियों के लिए सरकार के मन में कोई इंसानियत नहीं है ? उनको कम से कम डेली वेजिज तो देनी ही चाहिए । यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मेरे असंध में ठेके पर 7,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं । मेरा कहना है कि सरकार जब भी कोई काम करे तो उसे इंसानियत को सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए । इंसान बचेगा तभी तो राजनीति होगी । इसी तरह से ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज का मामला है । किसानों ने इसके लिए पैसे तो जमा करवाये हुए हैं लेकिन कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम्ज की वजह से अभी तक उनको बिजली के कनैक्शंज नहीं दिए गए हैं । अगर किसान को अपनी फसल के लिए पानी की जरूरत आज है और उसे बिजली का कनैक्शन 3 साल बाद मिलेगा तो किसान अपनी फसल कैसे पैदा करेगा ? अतः मेरा निवेदन है कि इस काम को भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए । मैंने कहीं पढ़ा था कि हरियाणा सरकार सीनियर रिपोर्टर्ज को 10 हजार रूपये प्रतिमाह देगी । राजस्थान सरकार रिपोर्टर्ज को 15 हजार रूपये प्रतिमाह देती है । इससे मैंने अंदाजा लगाया कि हमारी सरकार तो राजस्थान सरकार से अमीर है और यहां पर रिपोर्टर्ज को वहां से ज्यादा पैसे दिए जाते होंगे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि रिपोर्टर्ज को 10 हजार रूपये प्रतिमाह अवश्य दिए जायें । बजट में सबसे पहले पेज पर ही सरकार ने कोरोना वायरस का जिक्र किया हुआ है । उस दौरान सरकार ने जो किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं और मैं उस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता लेकिन उस समय जिन सामाजिक संस्थाओं ने जनता की मदद की और लंगर छकाया क्या सरकार को उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए था ? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : शमशेर सिंह जी, अब आप वाइंड अप कीजिए ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है सरकार को सामाजिक संस्थाओं की और उनके लंगर की इज्जत करनी चाहिए । कोरोना काल में तो सरकार को उनका लंगर अच्छा लग रहा था और जब उन्हीं लोगों ने किसान आन्दोलन के समय में लंगर लगाया तो सरकार ने उनके बर्तनों को उठाकर फेंक दिया । मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिसने गुरू नानक देव जी के लंगर की बेइज्जती की है, उसका सत्यनाश तय है ।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार ने सभी संस्थाओं का बार–बार धन्यवाद किया है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सिर्फ 2 बातें कृषि पर कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शमशेर जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि सरकार का फैसला प्राईवेट मंडियां बनाने का है। पहले व्यापारी मंडी में लगभग 164 रुपये के हिसाब से मार्केट फीस देता था। सरकार ने व्यापारी का यह टैक्स माफ कर दिया है। वह दूसरी मंडी में जाकर क्या करेगा क्योंकि उसको 164 रुपये फ्री में मिल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: शमशेर जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। ये बातें पहले ही हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में इन सभी बातों का रिप्लाई दे देंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखूंगा तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे। मेरी दूसरी बात कृषि कानूनों के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष: शमशेर जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: शमशेर जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री राजेश नागर (तिगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार, योग, रोजगार, पैंशन, उद्योग और एजूकेशन को ध्यान में रखते हुए टैक्स फ्री बजट पेश किया है। इस बजट में सबका साथ–सबका विकास और सबका विश्वास की बात चरितार्थ होती है। हमारे फैमिली कार्ड बनाये जा रहे हैं, महिलाओं के लिए महाविद्यालय खोले गये हैं और कई जगहों पर खोले जा रहे हैं। हमारे फरीदाबाद में एक नर्सिंग स्कूल खोलने की बात की गयी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और बाकी गांवों को भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसी तरह से गुरूग्राम और अन्य क्षेत्रों को मैट्रो नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में केवल हमारे प्रदेश में ही कौशल विकास विद्यालय खोलने का कार्य किया है, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिला है। हर खेत–स्वस्थ खेत का अभियान चलाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल्ज में 200 बैड्स तक करने और बीमारी को आने से रोकने के लिए 100

हैल्थ वैलनैस सैंटर खोले जाएंगे। इस बजट को बनाने के लिए सभी माननीय विधायकों और लोगों से भी बात की है। इसके अलावा अब मैं अपने हल्के की कुछ मांग रखना चाहूंगा। हमारे वहां पर एक नया फरीदाबाद शहर बसाने जा रहे हैं। जिसको नहर पार कहा जाता है। जैसे नोएडा एक शहर था और नये नोएडा शहर का नाम ग्रेटर नोएडा रखा गया है। इसमें मेरा यही कहना है कि इसी तरह से हमारे नये फरीदाबाद का नाम भी ग्रेटर फरीदाबाद रख दिया जाए। इसके लिए नगर निगम और एच.एस.वी.पी. मिलकर काम करते हैं, परन्तु दोनों विभागों के पास फंड्ज की कमी है। जिसके कारण वहां पर रोड्ज की मरम्मत, पानी की प्रॉब्लम और सीवरेज की प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए एक स्पैशल फंड हमारे नगर निगम और एच.एस.वी.पी. को दिया जाए। जिससे वहां पर रोड्ज, पानी और सीवरेज की दिक्कतें दूर हो जाएं। यह एक नया शहर बनने जा रहा है। हमारे वहां पर 55,000 के करीब फ्लैट्स हैं और वहां पर लगभग 40 सैक्टर्ज नये बनाए जा रहे रहे हैं। वहां पर 1 सब स्टेशन बनने जा रहा है तथा 2 सब स्टेशन और बनाए जाएं ताकि वहां पर आने वाले समय में बिजली की दिक्कत न आए। एक सब स्टेशन को बनाने में करीब डेढ –2 साल का समय लगता है। इसलिए हम उसको अभी से शुरू करेंगे तो ही वह डेढ़–2 साल में बनकर तैयार होगा। इसके अतिरिक्त हमारे वहां पर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है क्योंकि हमारे एरिया में हाई राईज बिल्डिंग तथा हाई राईज सोसायटीज बनी हुई हैं जो कि 20 से 25 मंजिल तक बनी हुई हैं। वहां पर कोई ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जो 20 से 25 मंजिल तक पानी पहुंचा सके। इस प्रकार की फायर ब्रिगेड केवल गुरूग्राम में ही है। अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको गुरूग्राम से ही मंगवाना पड़ता है। हमारे लिए ऐसी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना हो तो उसका समाधान हो सके। हमारे नये फरीदाबाद में एक अलग से नगर निगम बनाया जाए क्योंकि वहां पर 40–50 वार्ड बन चुके हैं तथा आने वाले समय में और भी वार्ड बनेंगे। जिस प्रकार गुरूग्राम को अलग से नगर निगम दिया गया है, उसी प्रकार हमारे फरीदाबाद को भी दिया जाए। इसके अलावा हमारे 22 गांवों के किसानों का मुआवजा रुका पड़ा है, वह मुआवजा देने का काम किया जाये। हमारा गांव तिगांव बहुत बड़ा गांव है जिसकी आबादी लगभग 50 हजार है। उपाध्यक्ष महोदय, एक नया पुल मंझावली से नोएडा और उत्तर प्रदेश से जुड़ने जा रहा है। यह पुल मई–जून तक बनकर तैयार हो जायेगा इसलिए मेरी मांग है कि बल्लभगढ़

से मंझावली तक फोर लेनिंग रोड बनाने का काम किया जाये। गांव तिगांव के लिए एक बाई पास बनाया जाये। जब यहां पर काफी ट्रैफिक हो जाता है तब घंटों तक जाम लगा रहता है। इसी तरह से हमारे यहां पर काफी कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनको रैगुलर किया जाये ताकि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को रोड, सीवर, पानी और बिजली की सुविधा मिल सके। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर ठेकेदारों के एच.एस.वी.पी. और नगर निगम की तरफ 4–4 साल से बिल पैंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार काम नहीं करते हैं और न ही कोई नया ठेकेदार काम करने को तैयार होता है। हमारे नये फरीदाबाद में कई रोड कोर्ट केसिज के कारण पैंडिंग पड़े हुए हैं। उनके कारण रोड बनाने का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के मामलों को आपस में बैठकर ही सुलझाया जा सकता है और वे ठेकेदार इस बात के लिए तैयार भी हैं। मैं समझता हूं कि वे कोर्ट से अपना केस वापिस ले लेंगे। जो रोड का काम पैंडिंग पड़ा हुआ है वह बनाया जा सकता है। हमारे यहां पर दो स्कूल है एक गाव बडौली में और दूसरा गांव घरोंडा में है। इन दोनों स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा? मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट पेश किया है। इस बीच में कोरोना काल भी चला गया। इस बजट को पेश करने के लिए काफी कुछ सोचा गया होगा। हम भी इस बजट की तैयारियों को देखकर यह सोचते थे कि सरकार प्रदेश की जनता के लिए अच्छी–अच्छी योजनाएं लागू करने का काम करेगी। सरकार ने बजट शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पेश किया। मेरे ख्याल से इस दिन बजट पेश करने के लिए कोई खास रीजन था क्योंकि ज्योतिष विद्या भी दिखाई गई होगी क्योंकि आम तौर पर 10 बजे सैशन शुरू होता है। उस दिन कोई खास दिन था कि सरकार ने 12 बजे विधान सभा का सेशन शुरू किया। मुझे लगता है कि सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक राहू काल चल रहा था और सरकार ने सोचा होगा कि राहू काल के बाद कुछ अच्छा हो जाये। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात का खास ध्यान रखा क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी उस दिन

12 बजकर 2 मिनट पर इस सदन में पहुंचे थे। हमें भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें थी और हमें यह लग रहा था कि इस बजट से कुछ न कुछ मिलेगा परन्तु हमें निराशा ही हाथ लगी। (विघ्न)

श्री बिशम्बर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य ने ज्योतिष विद्या का काम भी सीख लिया है। (विघ्न)

श्री जयवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भगवान वाल्मीकि जी ने हजारों साल पहले जब श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब उन्होंने भगवान श्री राम जी के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। आज हम क्यों नहीं भविष्यवाणी कर सकते है? इस बात का माननीय सदस्य को भी गर्व होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बजट से बहुत कुछ उम्मीदें थी। मैं लम्बी–चौड़ी बात न करता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा विषय बना हुआ है और वह सरकार के लिए सोचने लायक है। हमारे आज इस सदन में 88 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। उन सब की जिम्मेवारी बनती है कि किसान जो कि एक बिरादरी का न होकर 36 बिरादरी का होता है। इनको दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। किसानों से बात करने का सरकार का फर्ज बनता है लेकिन सी.एम. साहब ने यह घोषणा की कि ये तीनों कानून तो किसी भी हालत में वापिस नहीं हो सकते। ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं कि यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है और स्टेट गवर्नमैंट इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सी.एम. साहब को किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए यह कहना चाहिए था कि हरियाणा के 90 के 90 एम.एल.ए. माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें इन तीनों बिलों के पास होने के बाद किसानों को पेश आने वाली समस्याओं से अवगत करवायेंगे लेकिन सी.एम. साहब ने ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझी। यह भी हो सकता था कि हरियाणा विधान सभा में किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव लाया जाता और यह कहा जाता कि इस संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार को यह भी कहना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी किसानों की बात को सुना जाये और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए किसानों का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इस बार के बजट में बहुत

बड़ी–बड़ी बातें कही गई लेकिन किसान को कुछ भी नहीं दिया गया। न सरकार ने स्पैशल सब्सिडी की घोषणा करके किसानों के लिए डीजल सस्ता किया और न ही किसानों को पैट्रोल सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाया है। न ही सरकार ने खाद, बीज और पैस्टीसाईड्स के रेट ही कम किये हैं। इसके अलावा भी सरकार द्वारा कोई सुविधा प्रदेश के किसानों को नहीं दी गई है। इस प्रकार से वर्तमान बजट में किसानों के लिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, बजट में स्वास्थ्य के बारे में भी बढ़ा–चढ़ाकर बातें की गई हैं। सरकार ने यह भी कहा कि प्रदेश में बहुत से नये हॉस्पिटल्ज खोले जायेंगे। अगर सरकार वास्तव में ऐसा करती है तो यह बहुत ही अच्छी और स्वागतयोग्य बात होगी। हमारी पार्टी की चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार में हुड्डा साहब ने मेरे खरखौदा में 100 बैड के अस्पताल की स्थापना की थी लेकिन आज उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी प्रकार से अगर हम खानपुर कलां में जाकर देखें तो वहां पर स्थापित अस्पताल के भी हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। इतना ही नहीं मेरे खरखौदा के सरकारी अस्पताल में तो वॉचमैन भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि सरकार नये हॉस्पिटल्ज बनायें किसी को कोई परेशानी नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को वर्तमान में जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी दशा को सुधारने की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्ज की नियुक्ति अविलम्ब की जानी चाहिए ताकि प्रदेश के गरीब वर्ग को सस्ता इलाज सहजता से उपलब्ध हो पाये। खरखौदा में ओ.पी.डी. की संख्या 650 है लेकिन वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में गरीब व्यक्ति कहां से ईलाज करवायेगा? इसी प्रकार से बजट में इण्डस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं पिछले 6 साल से लगातार बजट में यह देख रहा हूं कि प्रदेश में इण्डस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी–बड़ी बातें होती हैं। हम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के बहुत आभारी हैं जिन्होंने खरखौदा में आई.एम.टी. की स्थापना की बाकायदा घोषणा की थी और जमीनों का पैसा भी दिया गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल के 6 सालों में हर साल के बजट में तो आई.एम.टी. खरखौदा का जिक्र किया जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आई.एम.टी., खरखौदा में एक ईंट तक नहीं लगाई है। मेरे हल्के खरखौदा की दिल्ली से दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। जब

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री थे तो उस समय हुड्डा साहब ने यह सोचा था कि अगर खरखौदा में आई.एम.टी. की स्थापना हो जाती है तो दिल्ली एन.सी.आर. और आस–पास के हजारों बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो जायेगा लेकिन इस सरकार ने आई.एम.टी., खरखौदा का भी भट्ठा बिठा दिया। अभी तक उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश में इण्डस्ट्री के मामले में इस तरह के बदतर हालात हैं। इस प्रकार के बदतर हालातों में प्रदेश में कहां से उद्योगों की स्थापना होगी और कैसे प्रदेश की तरक्की हो पायेगी? इसी प्रकार से मौजूदा बजट में एस.सी. व बी.सी. वर्ग के लिए भी कुछ नहीं किया गया। एस.सी. व बी.सी. वर्ग को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में एस.सी. व बी.सी. वर्ग के लोगों का जीवन एक संघर्ष बनकर रह गया है। प्रदेश के एस.सी. व बी.सी. वर्ग को हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के अत्याचार का डर सताता रहता है इसलिए डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एस.सी. व बी.सी. वर्ग के कल्याण के लिए एस.सी. व बी.सी. आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। ऐसे ही सरकार द्वारा कोरोना के बारे में बड़ी–बड़ी बातें कह कर अपनी प्रशंसा करने का काम किया गया है। मेरे विचार में कोरोना काल में अगर कोई असली योद्धा है तो वह सफाई कर्मचारी है न कि कोई दूसरा क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर्ज भी तभी एंट्री करते थे जब सफाई कर्मचारी द्वारा अच्छे से सफाई कर दी जाती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने सफाई कर्मचारी के लिए कुछ करना तो दूर की बात उसका जिक्र तक बजट में नहीं किया। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत शर्मनाक बात है। हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली हमारी सरकार के समय में सफाई कर्मचारियों के लिए ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया गया था। उस समय सरकार के स्तर पर यह फैसला लिया गया था कि जो भी सफाई कर्मचारी भर्ती होगा वह रेगुलर तौर पर ही भर्ती होगा। उसको कलैक्टर रेट के हिसाब से तनख्वाह देने की भी हमारी पार्टी की सरकार के समय में घोषणा की गई थी। हमारी सरकार ने ही प्रदेश के ग्रामीण अंचल में 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की थी ताकि गांवों की सफाई भी हो और प्रदेश के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो लेकिन दुर्भाग्य की बात वर्तमान सरकार ने उनमें से काफी सफाई कर्मचारियों को हटा भी दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : जयवीर जी, आप कृपया करके वाइंड–अप करें।

श्री जयवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा मानना यह है कि पिछले 6 साल में जनसंख्या भी बढ़ी है, सफाई का एरिया भी बढ़ा है तथा नये मकान भी बने हैं इसलिए गांवों में और शहरों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये तथा समय पर उनका वेतन भी सुनिश्चित किया जाये, चाहे इसके लिए बजट में प्रावधान ही क्यों न करना पड़े।

श्री उपाध्यक्षः जयवीर जी, आपकी जो भी डिमांड हैं वे आप लिख कर दे दें उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

*__श्री जयवीर सिंहः__ ठीक है, सर मैं अपने हल्के कही कुछ मांगें लिख कर दे रहा हूं।
मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिसाना माईनर पर 6 साल से टेल पर पानी नहीं पहुंचा है वहां पर पानी पहुंचाया जाये। इसी तरह से सेहरी माईनर, सिलाना माईनर, रोहणा माईनर, जटौला माईनर व सोहटी माईनर में भी टेल तक पानी पहुंचाया जाये। हमारी सरकार के समय में इन माईनर्स में 25 दिन में पानी आता था और एक हफ्ता चलता था अब भाजपा सरकार में 42 दिन में पानी आता है ओर एक हफ्ता चलता है। इसलिए इन टेल्स तक पानी पहुंचाया जाये। खरखौदा शहर में सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा है उसको ठीक करवाया जाये। खरखौदा से कंवाली मोड़ वाया थाना कलां रोड़ टूटा पड़ा है इसलिए उसको बनाया जाये। खरखैदा में मुख्यमंत्री जी ने 2016 में एक पार्क व स्टेडियन बनाने की घोषणा की गई थी उसको पूरा किया जाये। इसके अतिरिक्त गांव फिरोजपुर बांगर, झिंझौली, जटौला, सैदपुर, सोंहटी, रामपुर कुण्डल तथा गढ़ी गांव में वाटर वर्क्स की मांग है उसको पूरा किया जाये। इन गांवों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना)ः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हमारी सरकार को बने लगभग डेढ़ साल होने जा रहा है। यहां पर सभी को पता है कि पिछले पूरे एक साल कोरोना महामारी की लड़ाई हम सभी ने मिल कर लड़ी है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। समय का अभाव है इसलिए मैं अपने हल्के के विकास की बात करना चाहूंगा। मेरे जुलाना हल्के में 14–15 गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी खड़ा रहने के कारण सेम की समस्या हो गई है और फसल नहीं हो पाती हैं। सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। पिछले सत्र में मैंने जब यह बात हाउस में उठाई थी तो 8 गांवों में पाईपलाईन डाल कर पानी को ड्रेन में

डाल कर इस सेम की समस्या का समाधान किया गया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के कुछ गांव सामलोकलां, खरैंटी, डिघाना, भैरूखेड़ा, नन्दगढ़ तथा फतेहगढ़ हैं जिनमें अभी भी सेम की समस्या है तथा फसल खराब होती है इसलिए यहां पर भी इसी प्रकार की स्कीम चला कर सेम की समस्या का समाधान किया जाये। इसके अतिरिक्त 12–13 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की तथा सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश नहीं होती है तथा अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है। वहां पर सिंचाई का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि किसान किसी भी प्रकार की फसल पैदा कर सके इसलिए वहां पर सिंचाई का कोई इंतजाम करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की कई माइनर्स जिनमें करेला माइनर, निजामपुर, भैरूखेड़ा, निडाना, पडाना तथा सामलोकलां के ऐस्टीमेट्स बने थे, लेकिन वे अभी तक एप्रूव नहीं हुए हैं। इनमें से कई माइनर्स तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमैंट में भी शामिल हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन माइनर्स के ऐस्टीमेट्स दोबारा से एप्रूव किये जाये ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके तथा किसान की आमदनी बढ़ सके। सरकार की तरफ से बार–बार कहा जाता है कि हम किसान की आमदनी बढ़ायेंगे। अगर किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाये तथा जहां पर सेम की समस्या है वहां से पानी निकासी का प्रबंध हो जाये तो किसान की आमदनी अपने आप बढ़ जायेगी। किसान की फसल के रेट बढ़ाने से आमदनी नहीं बढ़ेगी बल्कि किसान के खेत में पैदावार बढ़ा कर ही किसान की आमदनी बढ़ पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जीन्द की शुगर मिल के बारे में बात करना चाहूंगा। जीन्द की शुगर मिल बहुत पुरानी हो गई है और उसमें वही पुरानी मशीनरी लगी हुई है। उस मिल की कैपेसिटी 17000 हजार क्विंटल प्रतिदिन है जिसको बढ़ा कर 34000 हजार क्विंटल प्रतिदिन किया जाये। पिराई क्षमता कम होने के कारण किसानों को कभी धुरी, कभी कैथल तथा कभी पानीपत जाना पड़ता है। हमारे जीन्द जिले में ज्यादा गन्ना पैदा होता है जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले लोग गन्ना उगाना बंद कर गये थे और फिर सरकार के आह्वान पर दोबारा से उगाना शुरू किया है इसलिए अगले सत्र से जीन्द शुगर मिल की पिराई क्षमता डबल की जाये। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के 55 गांवों को म्हारा गांव–जगमग गांव में शामिल करके 40 करोड़ रुपये के ऐस्टीमेट्स एप्रूव किये हैं जिसके लिए मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के करेला झमोला गांव के 10वीं तक का स्कूल है, उसको अपग्रेड करके 10+2 तक किया जाये। वह स्कूल सभी नॉर्म्स पूरे करता है तथा फाइल भी शिक्षा विभाग में आई हुई है। इसी तरह गतौली गांव से उप–मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक प्रस्ताव भी मांगा गया था कि वहां कॉलेज के लिए जमीन दी जाए। गतौली गांव की पंचायत कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दे चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उस कॉलेज का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र से जीन्द 25 किलोमीटर दूर है और रोहतक भी 35–40 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां पर हमारी बहन–बेटियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हमारे वहां से बहुत दूरी होने के कारण उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां कोई स्पैशल बस नहीं लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां बहन–बेटियों के लिए एक स्पैशल बस लगाई जाए और वह बस स्पैशल लड़कियों के लिए ही हो उसमें कोई लड़का न बैठे क्योंकि लड़के तो अलग से भी चले जाएंगे। अतः लड़कियों के लिए अलग से कुछ किया जाए। हमारी बहन–बेटियां बहुत दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। अगर यहां कॉलेज बन जाएगा तो बहन–बेटियां को बहुत सुविधा हो जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : ढ़ांडा जी, धन्यवाद।

श्री अमरजीत ढ़ांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भाषण देने कम ही आते हैं। मैं केवल काम की बात करूंगा क्योंकि भाषण देने वाले यहां बहुत बैठे हुए हैं जो किसी के भी बीच में खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ढ़ांडा जी, आप कॉन्टीन्यू कीजिए।

श्री अमरजीत ढ़ांडा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रूधाना गांव में एक जैड डी फॉर (रजबाहा) के रैनोवेशन के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि के लिए फाइल आई थी। वह फाइल यहां से सी.एम. कोड लग कर वापिस चली गई शायद सी.एम. कोड में कोई कमी रह गई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रूधाना गांव में जो यह जैड डी फॉर (रजबाहा) है वह 5–6 गांवों को कवर करता है और उसकी

फाइल अभी पैंडिंग पड़ी हुई है। उस संबंध में मैं श्री देवेन्द्र सिंह ए.सी.एस. से भी मिला था। उसमें भी कुछ डाउट था । अतः वह फाइल मंगवाकर उसका काम पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरी एक बिजली की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे वहां कई गांव ऐसे हैं जहां तालाब के ऊपर से बिजली की लाईन गई हुई है। बिजली मंत्री अभी बाहर चले गये हैं। वहां पर उस बिजली की लाईन से कई बार पशुओं को नुकसान हो जाता है। इसी के साथ मैं बिजली मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार अपने क्षेत्र में दो पावर हाऊस देने के लिए प्रस्ताव दिया था। उनमें से एक पावर हाऊस का प्रपोजल तो चालू हो रहा है और दूसरे का अभी अधूरा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस दूसरे पावर हाऊस का काम भी जल्दी से शुरू करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष :ढ़ांडा जी, धन्यवाद। आप अपनी बाकी डिमांड लिखकर दे दीजिए। माननीय सदस्यगण, जो भी विधायक बजट पर बोलने से रह गये हैं अगर वे अपने हल्के की मांगों को इतना लम्बा न करके सीधा लिखकर दे देंगे तो ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट वास्तव में ही बहुत शानदार और संतुलित बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पिछले वर्ष यहां पर वर्ष 2020–21 का बजट पेश कर रहे थे तो शायद किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि वर्ष 2020 खुद को इतिहास का सबसे कठिन सालों में से एक साल साबित करके जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोरोना ने पूरी दुनिया की गति को रोका वहां पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। ऐसे मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाते इन कठिन परिस्थितियों में प्रदेश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए व्यवस्थित तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं उन्होंने वित्त मंत्री के नाते भी एक अच्छे वित्त प्रबंधन का उदाहरण देते हुए आज तक का हरियाणा

17:00 बजे

प्रदेश का सबसे बड़ा बजट जोकि 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये का है और वह किसी भी नये कर से मुक्त है पेश किया है। स्पीकर सर, मैं सरकार की एक और उपलब्धि मानता हूं कि ऐसे खराब हालात के अन्दर प्रदेश की कर व्यवस्था पूरे तरीके से मजबूत रही है। जिसके लिए मैं प्रदेशवासियों की भी सराहना करता हूँ क्योंकि अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूं तो पिछले साल 15 मार्च तक की

जी.एस.टी. की एक्साइज और वैट के तहत जो कलेक्शन थी वह 37 हजार 923 करोड़ रुपये थी जो इस साल जबकि कोरोना की मार भी प्रदेश ने झेली है यह आंकड़ा 41 हजार 912 करोड़ रूपये है जोकि मैं समझता हूँ कि इससे कहीं न कहीं सरकार की गम्भीरता ही दिखाई देती है और कहीं न कहीं वे अधिकारी जिन्होंने इसके लिए मेहनत की होगी वे भी इसके लिए तारीफ के पात्र हैं। अगर बजट का मोटे रूप से मैं आंकलन करूं तो यह बजट इस सरकार की या यू कहें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूर– दृष्टि का ही परिणाम हैं जिसके कारण आज बड़े–बड़े नैशनल हाइवे, रेलवे व सिविल एविएशन के नए प्रोजैक्ट आज इस प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार किसान की आमदनी को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तथा कृषि जगत को मजबूती देने के लिए भी अनेकों योजनायें प्रदेश में चलाई जा रही हैं और इसके लिए क्रॉप डायवर्सिफिकेशन अर्थात फसल विविधिकरण के साथ–साथ हार्टिकल्चर, डेयरी फिशरीज तथा पौल्ट्री क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यही नहीं जल प्रबंधन पर भी सरकार फोकस के साथ काम कर रही है। इसी प्रकार धान के विकल्प के रूप में अन्य फसल उगाने पर सात हजार रूपये की सब्सिडी दिए जाने का जो प्रावधान किया गया है वह भी निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय व प्रशंसनीय कदम है। इसके अलावा मेरी फसल–मेरा ब्यौरा योजना, म्हारा गांव–जगमग गांव योजना, उचित मुआवजा, फसल बीमा को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन पर बल, एफ.पी.ओज. का गठन तथा जीरो बजट खेती खरीफ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना आदि ऐसे कुछ ठोस कदम हैं जोकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की गम्भीर सोच का ही परिणाम हैं और किसान वर्ग जो हमारे देश व प्रदेश का एक सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी मजबूती के बिना अर्थव्यवस्था मजबूत होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती और यह सच्चाई जानते हुए कि किसान की असली बरकत तभी हो सकती है जबकि उससे जुड़ी हुई हर व्यवस्था को सुचारू रूप से सृदृढ़ व मजबूत किया जाये, की अवधारणा पर काम करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से एक प्राथमिकता रही है। बात चाहे ग्रामीण विकास की हो या शहरों के सुनियोजित विकास की हो, पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन की बात हो, हर नागरिक के लिए शिक्षा–स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात हो, उद्योगों को बढावा देने की ही बात हो या फिर चाहे युवाओं को सक्षम बनाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का लक्ष्य ही क्यों न हो,

अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो ऐसी सभी व्यवस्थाओं या इनसे संबंधित सिस्टम को ठीक करने का आज काम किया जा रहा है। सदन में बजट के बारे में बहुत तरीके की टिप्पणियां सुनने को मिली, जिनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक महानुभाव ने ठीक ही कहा था कि बजट वह पकवान है जिसे सरकार रूपी बहू कितने भी मन से बनाये फिर भी विपक्ष रूपी सास उसमें मीन–मेख निकाल ही देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नारी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? बहु और सास का बहुत गहरा और पवित्र रिश्ता होता है और जिस तरह की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, ऐसा करके वे क्यों सास बहू के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। इन्हें केवल बजट पर बात करनी चाहिए। इस तरह के अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए?

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, माननीय सदस्य ने तो केवल एक कहावत की है, उन्होंने किसी प्रकार के अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं कहे हैं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या नारी को कमजोर न समझे उन्हें पता होना चाहिए कि सैंटर में बजट बनाने का काम एक महिला मंत्री ने ही किया है। इसलिए किसी कहावत पर इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करना ठीक नहीं है।

श्री हरविन्द्र कल्याणः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल एक कहावत ही कही है। माननीय सदस्या एक बहुत विद्वान सदस्या हैं, मेरे दिल में इनके प्रति बहुत सम्मान है और निश्चित रूप से यह सम्मान इसी तरह आगे भी बना रहेगा लेकिन अब विषय पर आते हुए मेरे मन में एक विचार यह भी आया है कि जिन्होंने भी इस बजट को बनाया होगा तो बजट बनाते वक्त उनके मन में जो विचार आए होंगे, उन विचारों को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा किः–

कुछ तो फूल खिलाये हमने और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल है कि बाग में, अब तक कांटे बहुत पुराने हैं।।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में बहुत विकास हुआ है लेकिन अब दो तीन बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां करनाल के हवाई अड्डे का विस्तार करने का काम किया जायेगा जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है इसी प्रकार करनाल से दिल्ली के लिए रैपिड रेल और करनाल का ईस्टर्न बाईपास बनने के बाद पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैडिकल यूनिवर्सिटी को भी बहुत अच्छी

कनैक्टिविटी मिल जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021–22 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। वर्ष 2021–22 के लिये 155645 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2020–21 के 137738 करोड़ रुपये से यानी 13 प्रतिशत ज्यादा है। यह सदन स्वयं अंदाजा लगा सकता है कि इतने बड़े स्टेट में पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 13 प्रतिशत ज्यादा बजट रखने से प्रदेश में क्या–क्या विकास के काम होंगे? यह बिल्कुल ही दिशाहीन, निराशाजनक और बेरोजगारी को बढ़ाने वालो बजट है। इस बजट से गरीब आदमी, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी इत्यादि सभी प्रभावित होंगे। पैट्रोल–डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी पर महँगाई की मार भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह बात हम सभी जानते हैं क्योंकि इस महँगाई का असर हम सभी पर पड़ता है। मेवात क्षेत्र के लिये बजट में वही चार लाइनें रिपीट कर दी जो पिछली बार के बजट में रखी थी। बजट का मतलब यह होना चाहिए कि वह काम एक वर्ष के दौरान पूरा होना चाहिए। लेकिन मेवात के लिये उन्हीं चार लाइनों को हर साल रिपीट कर दी जाती है। मेवात के लिये इस बार के बजट के क्रमांक नं0 89 में वही बातें लिखी है जो पिछली बार के बजट के क्रमांक नं0 170 में लिखी हुई थी। मेवात में पानी के बारे में यह कहा जाता है कि सरकार ने 100 क्यूसिक्स की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से मेवात को पानी के नाम का लॉलीपॉप दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पानी हमारे क्षेत्र के लिये बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है, उसके लिये यह हाउस ऐसा अहसान दिखाता है जैसे मानो इस प्रदेश में हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है। बजट में कहा गया है कि नागरिक अस्पतालों में कैथ लैब, एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन और डायलिसिस की सेवाएं दी जायेगी। यह बात भी पिछली बार के बजट में से उठाई गई है। जिस तरह से बजट पूरे हरियाणा का होता है उस तरह से मेवात के लिये अलग से एक रुपया का भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। (विघ्न)

श्री कंवर पाल: उपाध्यक्ष महोदय, बजट पूरे प्रदेश के लिये होता है।

श्री मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, नीति आयोग के अनुसार 101 पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ा जिला हरियाणा का मेवात है। इसके लिये सरकार को अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए तभी मेवात जिले को भी बाकी 21 जिलों को विकास के नाम पर बराबर लाया जा सकता है। बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्री–बजट के लिये माननीय सदस्यों से अपने–अपने सुझाव बजट में रखने को कहा था। मैंने स्वयं मेवात में यूनिवर्सिटी की बात कही थी और मैंने पूरा बजट ध्यान से सुना और पढ़ा, लेकिन मेवात को यूनिवर्सिटी की सौगात नहीं मिली। मेवात के लोगों को इससे बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी। मेवात के लोग पहले से रेलवे लाइन की भी मांग कर रहे थे। जब मानेसर, सोहना, खरखौदा, दिल्ली आदि को जोड़ने की बात होती है तो गुरूग्राम, सोहना, वाया नूंह अलवर को जोड़ने की बात क्यों नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल अन्य शहरों को तो जोड़ने की बात करते रहते हैं लेकिन मेवात को छोड़ देते हैं। मैं बार–बार कहता हूँ कि मेवात में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है और न ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मेवात के सेक्टरों को डिवैल्प किया है। मेवात जिला वर्ष 2005 में बना था, मेवात में विकास के कार्य नहीं होंगे तो मेवात किस प्रकार से उन्नति करेगा। वहां पर कोई सिंथैटिक ट्रैक नहीं है जिस पर प्रैक्टिस करके वहां के बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सिज और पुलिस में भर्ती हो पाते । वहां पर कोई खेल स्टेडियम भी नहीं है जहां पर बच्चे प्रैक्टिस कर पाएं । मैं सोच रहा था कि बजट में मेवात के लिए इन सब चीजों के लिए अवश्य प्रावधान किया जाएगा लेकिन मेवात इससे वंचित ही रहा । मेरे हल्के के नगीना ब्लॉक के 54 गांव टेल पर लगते हैं । वहां के लोग 1000 लीटर के टैंकर मंगवाकर पानी पीते हैं । हमें उम्मीद थी कि बजट से हमें पानी खरीदकर पीने की दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन हमें उस समस्या से भी छुटकारा नहीं मिला । हमारे हल्के के गांवों में पंचायतों के पास 2–2 हजार एकड़ लैण्ड है । हमारा अनुरोध है कि वहां पर कोई इण्डस्ट्रियल एरिया विकसित कर दिया जाए । इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी । इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे नूँह से राजस्थान बॉर्डर तक 51 किलोमीटर का फॉर लेन रोड है । उस पर कई बार गम्भीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं । आज सुबह 8:30 बजे भी वहां पर एक दुर्घटना में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई । अतः मेरी प्रार्थना है कि वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रबंध किये जाएं । (घंटी) इसके

अलावा मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में एक जिमखाना क्लब खोला जाए । हमारे क्षेत्र में ड्राइवर्स की संख्या बहुत ज्यादा है । अतः वहां पर एक ट्रांसपोर्ट नगर अवश्य खोला जाए । इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा । इसके साथ ही साथ मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में 2 बस स्टैण्ड बनाए जाएं । हमारे क्षेत्र में बड़खली नाम का एक क्षेत्र है जोकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी आपस में जोड़ता है । मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में न तो रेडियोलौजिस्ट हैं, न गायनोकौलौजिस्ट हैं, न अल्ट्रासाउंड करने की मशीन है । अतः वहां पर इन सबका प्रबंध किया जाए । हमारा क्षेत्र एक बहुत ही गरीब क्षेत्र है । वहां पर न तो कैंसर के डॉक्ट्र्स हैं और न ही न्यूरो सर्जन्स हैं । अतः हमारी प्रार्थना है कि शहीद हसन खां मेवाती मैडिकल कॉलेज में इनकी व्यवस्था की जाए । इस तरह की मेरी बहुत–सी मांगे थी लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया । हमने बड़ोदा एक्सप्रैस–वे पर बड़खली के नजदीक खानपुर घाटी पर एक कट की मांग की थी जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलता लेकिन हमारी उस मांग को नहीं माना गया । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मामन खान जी, प्लीज आप बैठ जाइये ।

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन से उठकर चले गए । मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र के 80 परसैंट स्कूल्ज में अध्यापक नहीं हैं । मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि सरकार द्वारा 1,057 प्राइमरी स्कूल्ज को बंद कर दिया जाएगा और मेवात में जो 56 मॉडल स्कूल्ज अपग्रेड किये गए थे उनको भी बंद कर दिया जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह बजट किसको सूट करेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट दिशाहीन है । (विघ्न) मुझे उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र के लिए एक पी.एच.सी. का प्रावधान कर दिया जाएगा लेकिन हमें पी.एच.सी. भी नहीं दी गई । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मामन खान जी, अब आप बैठ जाइये । अगर आपकी कोई बात कहे बिना रह गई हो तो उसे आप लिखित रूप में दे दीजिए ।

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा पहलवान लड़का है और वह बहुत अच्छी रैसलिंग करता है । उसका रैसलिंग में पूरे हिन्दुस्तान में नाम है । अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस लड़के को पुलिस की नौकरी दी जाए । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री नयनपाल रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के मैम्बर्स को बोलने का बहुत कम समय दिया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के मैम्बर्स ज्यादा हैं और बोलने का बहुत कम टाइम ले रहे हैं । हमारा कोई भी मैम्बर 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता और विपक्ष का कोई भी मैम्बर 15 मिनट से कम नहीं बोलता है । (शोर एवं व्यवधान) यह बात तो ऑन रिकार्ड है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइये और माननीय सदस्य श्री नयनपाल रावत जी को बोलने दीजिए ।

श्री नयनपाल रावत (पृथला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2021–22 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं और उसका समर्थन भी करता हूं । कोरोना काल के बावजूद भी प्रदेश का 1,55,645 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है। जनता पर कोई नया टैक्स लगाए बिना यह बजट पेश किया गया है। यह बजट इस प्रदेश के 2.75 करोड़ लोगों के हर वर्ग के हित में है। वैसे तो इस बजट को विपक्ष के माननीय सदस्य भी ठीक मान रहे होंगे क्योंकि उनके मन की बात नहीं हुई है। विपक्ष के माननीय सदस्य सोच रहे थे कि कोविड–19 के कारण प्रदेश को बहुत आर्थिक नुक्सान हुआ है जिसके कारण सरकार जनता पर टैक्स लगाएगी और इनको हो –हल्ला करने का मौका मिलेगा। सरकार ने यह टैक्स फ्री बजट पेश किया है। विपक्ष के माननीय सदस्य अन्दर खाने से इस बजट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में खबर छपवाने के लिए और बाहर अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इसका थोड़ा बहुत विरोध जरूर करते हैं। मान्यवर, अब मैं आई.टी. सैल यानी सूचना प्रोद्योगिकी के बारे में बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमैंट्स की चीजों को ऑनलाईन करने का कार्य किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 139 करोड़ रुपये का बजट केवल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तय किया गया है। जो पिछले वर्ष से 31 करोड़ रुपये ज्यादा है। मान्यवर, 500 तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको करवाने के लिए प्रदेश के लोग इधर–उधर तहसीलों और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते थे। फिर चाहे उसमें डौमिसाईल बनवाने की बात हो, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बात हो, बिजली के बिल भरने की बात हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें इस ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से की जा रही हैं। इस ऑनलाईन सिस्टम से प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो

गया है। आज किसानों की फसलों का पैसा ऑनलाईन उनके खाते में सीधा ही जाता है। पंचायतों के लिए विकास कार्य करवाने का पैसा भी ऑनलाईन सीधे उनके खाते में जाता है। कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो वह नीचे पहुंचते –पहुंचते ब्लॉक लेवल पर केवल 15 पैसे ही रह जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास किया है। वह अपने आप में बहुत ही कुशल काम है। मान्यवर, मैं एक बात अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हर किसी ने किसानों का किसी न किसी रूप में नाम लिया है। आजादी ले लेकर अब तक इतने लम्बे समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राज किया है। साढ़े 6 साल पहले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार के समय में बाजरे को 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बता दें कि उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के 10 सालों के शासनकाल में किसानों के लिए फ्लां काम किया था। अबकी बार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि किसानों की फसलों की खरीद का पैसा 48 घंटों में सीधा उनके खातों मे चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने 10 साल का कोई ऐसा काम गिनवा दें तो मैं मान लूंगा कि ये किसान हितैषी हैं। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य केवल और केवल किसानों के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। इनके पल्ले अब भी कुछ नहीं है और न ही पहले था। मान्यवर, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री बिशन लाल सैनीः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः बिशन लाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री नयन पाल रावतः मान्यवर, इनके पास केवल 3–4 बातें ही हैं। बजट निराश करने वाला है और दिशाहीन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह विपक्ष दिशाहीन हो गया है, इसलिए इनको सब कुछ दिशाहीन दिखाई देता है और आगे भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे ये कितना मर्जी जोर लगा दें और चाहे कुछ भी ढोंग कर लें। इनको देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। इनकी बातों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुभाष सुधा (थानेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस सदन में

यह कहना चाहूंगा कि 89 म्युनिसिपल कमेटीज हैं। 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद् और 56 नगर पालिकाएं हैं। सरकार ने वर्ष 2019–20 में 3546.56 करोड़ रुपये और वर्ष 2020–21 में 6982.53 करोड़ रुपये का बजट रिलीज किया। अमृत योजना के तहत सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से 1491.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जिसके अंदर 1492 किलोमीटर पानी की पाइप, 1219 किलोमीटर सीवर लाइन और 104 किलामीटर बरसाती नाली का कार्य किया गया। इन कामों पर लगभग 1398.79 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। मैं इसी के साथ यह भी कहूंगा कि पहली बार कुरूक्षेत्र में 27 करोड़ रुपये अमृत योजना के तहत दिये गये थे। जिसके अंदर बहुत बड़ा नाला जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाया उस नाले को हमारी सरकार ने बनाया। मैं इसके लिए सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फरीदाबाद में कुल 46 परियोजनाओं पर 1505.61 करोड़ रुपये व करनाल में 85 योजनाओं पर 1524.57 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। प्रदेश में स्वच्छ भारत योजना के तहत 363.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसके तहत 65870 घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया था, 4057 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया था, गरीब बस्तियों में 6870 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि मार्केट या सार्वजनिक स्थानों पर इस योजना के तहत हरियाणा को खुले में शौच मुक्त करने का काम किया गया था। हमारी सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत घर–घर से कूड़ा उठाने के लिए गुरुग्राम–फरीदबाद और सोनीपत–पानीपत क्लस्टर में प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सोनीपत–पानीपत क्लस्टर का कार्य अप्रैल 2021 तक सम्पन्न हो जायेगा। इस प्लांट से कचरे से बिजली बनाने का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री द्वारा एक नई समग्र शहरी विकास योजना के तहत 172. 95 करोड़ रुपये नगरपालिकाओं को दिया गया। इस योजना के तहत विकास कार्यों के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए, पब्लिक टॉयलेट के लिए, सड़कें और गलियों के विकास कार्य के लिए दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री ने 896 घोषणाएं की थी और इसमें से 431 घोषणाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 318 घोषणाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 2020–21 में जगमग शहर योजना के तहत 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत थानेसर में 15 हजार एल.ई.डी. लाइट्स लगाई

गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का पंजीकरण प्रोपर्टी टैक्स वाटर व सीवरेज बिल जैसे 154 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हमारे प्रदेश के अंदर वर्ष 2014 में 98 फायर स्टेशन थे अब 16 नये फायर स्टेशन और खोले गये हैं। पिछले वर्ष 60 करोड़ रुपये अग्निशमन सेवाओं के लिए दिये गये थे। प्रदेश में 114 फायर स्टेशनों पर 332 दमकल गाड़ियां, 102 मोटर साइकिल, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों सहित 7 टाटा जोन वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 2779 अलग–अलग पदों पर भर्तियां भी की है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के समय में भी नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को सैलरी देने का कोई प्रोविजन नहीं था फिर भी इस कोविड–19 में हमारी सरकार ने इन कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार का धन्यवाद करूंगा। हमारी सरकार ने पूरे शहर के अंदर गैस लाइन बिछाने का भी काम किया है। जो 20 साल से दुकानें बंद पड़ी थी, हमारी सरकार ने उनको डी. सी. रेट पर देने का कार्य किया है। इसी के साथ में यह भी कहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स है। मैं यह भी कहूंगा कि प्रदेश के अंदर नगरपालिकाओं में, नगर परिषद्ों में और कारपोरेशंज में जितना काम हमारी सरकार ने किया इससे पहले कभी किसी भी सरकार के समय में नहीं हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य शहरों में देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि किस प्रकार से शहरों में डिवैल्पमैंट के कार्य किए जा रहे हैं। मैं लगभग 5 साल पहले चेयरमैन रहा था, उसके बाद फिर रहा और लगातार मेरी पत्नी 20 सालों से चेयरपर्सन है। मुझे यह बात ध्यान है कि पहले की सरकारों के समय में अगर सीवरेज की 100 फुट पाइप का काम करवाना होता था तो यह काम नहीं होता है। आज हमारी सरकार ने शहरों में सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का कार्य 76 परसैंट तक पूरा कर लिया है। हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने का कार्य भी किया है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने एक नहीं अनेकों कार्य किये हैं अगर मैं इन कार्यों को गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि एक विधायक होने के नाते आपको भी पता है कि जनता का हम पर कितना प्रैशर होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कुरूक्षेत्र शहर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 225 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले एलीवेटिड रेल ट्रक

बनाने का काम शुरू करवा दिया है इसके लिए मैं अपनी सरकार का तहे दिल से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे कुरूक्षेत्र शहर की एक वर्षों पुरानी और बहुत बड़ी डिमाण्ड है जिसको मैं विधान सभा के प्रत्येक सैशन में उठाता रहा हूं और वह डिमाण्ड है कुरूक्षेत्र बाई–पास बनाने की। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से विधान सभा के इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार से यह पुरजोर मांग करता हूं कि कुरूक्षेत्र में पेहवा रोड के लिए जल्दी से जल्दी बाई–पास का निर्माण करवाया जाये। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि मेरे कुरूक्षेत्र शहर में दो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट्स का अतिशीघ्र निर्माण करवाया जाये। मेरी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी राज्य की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जहां पर आज आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर साहब ने 220 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की सरकार आने से पहले की सरकार ने मेरे हल्के के गांव मिर्जापुर की 131 एकड़ जमीन के लिए सैक्शन–4 का नोटिस जारी किया था मेरी अपनी सरकार से रिक्वैस्ट है कि उस जमीन को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाये। इस प्रकार के गलत डिसीजन लेकर विपक्ष के साथियों की सरकार ने किसानों को बिना किसी वजह के परेशान करने का काम किया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि ये किस आधार पर अपने आपको किसानों का हितैषी बताने की बातें करते हैं। हमारे यहां पर कृष्णा आयुर्वैदिक कॉलेज एक बहुत ही पुराना कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी के अंदर मर्ज किया जा रहा है। मेरी स्पीकर साहब के माध्यम से सरकार से यही रिक्वैस्ट है कि उस कॉलेज के सम्बन्ध में गवर्नमैंट की जो टर्म्ज एण्ड कंडीशंज हैं उस कॉलेज के मामले में उन्हीं टर्म्ज एण्ड कंडीशंज को बरकरार रखा जाये। डिप्टी स्पीकर सर, हमारी सरकार द्वारा पिपली के अंदर नया बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए भी मेरा अपनी सरकार से यही कहना है कि पिपली के नये बस स्टैण्ड का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाये। मेरे कुरूक्षेत्र शहर के 100 बैड के सिविल हॉस्पिटल को माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब ने 200 बैड का बनाने की घोषणा की है मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, हैल्थ मिनिस्टर साहब और अपनी पूरी की पूरी सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह रिक्वैस्ट भी करना चाहूंगा कि मेरे कुरूक्षेत्र शहर में जितने भी बाहर के शहरों से

एंट्री करने वाले रोड हैं, उन सभी के ऊपर महाभारत की थीम को दर्शाने वाले एंट्री गेट्स का निर्माण करवाया जाये। मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाबी सभा के हमारे युवा साथियों ने हिसार के अंदर बुलाया था वहां पर मुख्यमंत्री जी चीफ गैस्ट थे वहां पर पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाबी मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मैं पहले मैं एक देशभक्त हूं और उसके बाद पंजाबी हूं। डिप्टी स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथियों को किसानों के हितों से कोई लेना–देना नहीं है बल्कि इनका तो एक ही निशाना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे हथिया लिया जाये। इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। यह बात मैं इनको पूरी तरह से क्लीयर कर देना चाहता हूं कि भविष्य में इनका ऐसा टाईम कभी भी आने वाला नहीं है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे निस्वार्थ भाव से 24 घंटे पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरियों के चहुंमुखी विकास करने के कार्यक्रम व योजनाओं को बनाने में और उनको लागू करने के काम में पूरी सत्यनिष्ठा, निस्वार्थभाव और ईमानदारीपूर्वक लगे हुए हैं। मैं उनके जज्बे को बार–बार सैल्यूट करता हूं। डिप्टी स्पीकर सर, आपने मेरी बात को सुना इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद) (एन.आई.टी.) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ हमारे नेता ने बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया। जब मैंने अपने फरीदाबाद का हिस्सा देखा तो मुझे इस बजट में चुहिया भी नहीं मिली। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज सभी को पता है कि आज टैक्स की कलैक्शन जी.एस.टी. के रूप में होती है और जी.एस.टी. उत्पादन पर नहीं लगता अपितु जी.एस.टी. उपभोग पर लगता है। मेरे फरीदाबाद की आबादी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है और खाना खाने से लेकर के पकाने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरे फरीदाबाद का हर आदमी प्रत्येक चीज पर सरकार को टैक्स के रूप में अपने खून पसीने की कमाई दे रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मेरे फरीदाबाद को बजट में सरकार कुछ भी नहीं देती है। उपाध्यक्ष जी, इस बजट पर पंजाबी की एक कहावत पूरी तरह से सटीक बैठती

है और वह कहावत यह है कि – रावी विच वगियां तिन नहरां, दो सुखियां ते इक वगे ही ना, जेड़ी वगे ही ना ओदे विच नहावण आये तिन बामण, दो डुब गये ते इक लबे ई ना, जेड़ा लबे ई ना ओ नू लबियां तिन गांवां, दो फण्डरां ते इक सुवे ई ना, जेड़ी सुवे ई ना ओ नू जम्मे तिन बच्चे, दो लंगड़े ते इक उठ्ठे ई ना, जेड़ा उठ्ठे ई ना, ओ दी कीमत लाई तिन रूपइये, दो खोटे ते इक चल्ले ई ना, जेड़ा चल्ले ई ना, ओ नू वेखण आये तिन सुनारे, दो अन्ने ते इक नू दिसे ई ना। वर्तमान सरकार का यह बजट पूरी तरह से इस कहावत जैसा ही है। नहर आ भी गई, चली भी गई और दूसरे भी सभी काम हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने रामचरित मानस का उदाहरण देते हुए बताया था कि कर संग्रह कैसा होता है परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि महाकवि कालीदास ने रघुवंशम् महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में लिखा है कि प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत। सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः।। रघुकुल में कर कैसे लेना चाहिए। जैसे सूर्य अर्ध्य लेकर सहस्र गुणा बरसा कर वह हमें देता है। मैं मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहता हूं कि आप फरीदाबाद से क्या ले रहे हो और हमें कितना वापस कर रहे हो। आप 100 रुपये ले रहे हो तो 100 मत दो 50 रुपये दे दो, 25 रुपये दे दो या 10 रुपये दे दो। अगर आप इतना कर दोगे तो हमारे यहां सड़कों पर बच्चे नहीं मरेंगे। हमारे यहां पर गौंछी ड्रेन है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं अगर आप हमें हमारा हक दे देंगे तो गौंछी ड्रेन में पशु नहीं मरेंगे। हमारे शहर को सिर्फ प्रदूषण मिल रहा है जिस पर आज हमने चर्चा भी की है। उसके बाद चण्डीगढ़ में आ कर हम बात करते हैं चाहे शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, ये जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं या स्कूल हैं ये पैरलल गवर्नमैंट बन गई है। मैंने फरीदाबाद के क्यू.आर.जी. हॉस्पिटल को लेकर आवाज उठाई थी कि क्यू.आर. जी. हॉस्पिटल को जो जमीन दी गई है वह किसके लिए रखी गई थी। हमने जब इस बारे में विधान सभा में प्रश्न लगाया तो उसका गलत जवाब दे दिया गया। जब इस बारे में विवरण मांगा तो विवरण नहीं दिया गया। इस हॉस्पिटल को जो जमीन अलॉट की गई है वह हरिजन बच्चों के नाम पर संस्था के लिए जमीन आबंटित हुई थी। सौ करोड़ रुपये की उसकी एक्सटेंशन फीस के अभी–अभी माफ की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी विनती करना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को रोक लो इससे हम सभी का दिल रोता है। जब हम दिल्ली से गुरूग्राम में घुसते हैं तो धारूहेड़ा तक तो हमें जयपुर हाईवे पर क्या दिखाई देता है– सिग्नेचर टावर,

रैड बिल्डिंग, साइबर हब, डी.एल.एफ. सिटी इत्यादि। फरीदाबाद सबसे पुराना शहर है और आज फरीदाबाद में क्या है– अवैध प्लाटिंग के नाम पर कुकुरमुत्ते की तरह बिल्डिंग खड़ी हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैट्रो आई, मैट्रो का पैसा लगा और हुड्डा साहब ने हजारों करोड़ रुपये मैट्रो पर खर्च किये। उसके साथ ही टी.ओ.डी. पॉलिसी भी आई। यह पॉलिसी इसलिए आई थी कि मैट्रो का पैसा भी निकल जायेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिल जायेंगे। लेकिन फरीदाबाद में टी.ओ.डी. का एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान है इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक एकड़ पर टी.ओ.डी. लग जाये तो सरकार को ई.डी.सी., आई.डी.सी., आई.ए.सी., कन्वर्जन फीस, लाइसेंस फीस इत्यादि के रूप में 19 करोड़ 40 लाख रुपये मिलते हैं। होता क्या है, छोटी–छोटी फैक्ट्रियों में प्लाट काट दिये गये। मैं एक डूरेबल फैक्ट्री का उदाहरण दे रहा हूं। 4 एकड़ की फैक्ट्री में 80 करोड़ का फटका लगा दिया। यह पैसा कौन खा रहा है, यह पैसा नेता और ऑफिसर मिल कर खा रहे हैं। यह पैसा हरियाणा की आम जनता का जा रहा है। मैं पिंकी और प्रीती दो सगी गरीब बहनों की कहानी बता रहा हूं। दोनों ने 50 गज का एक प्लॉट ले लिया। उनको अढ़ाई साल में बार–बार बहुत सारे नोटिस दिए गए कि आपके प्लॉट का बंटवारा हुआ है इसलिए आप एक्सट्रा पैसे भरो। दूसरी तरफ डूरेबल जैसी अनेक फैक्ट्रियों में कमर्शियल बन गए मगर उनको कोई नहीं पूछता है। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के बाईपास से दिल्ली–मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेस–वे जा रहा है। इस एक्सप्रेस–वे के लिए गरीबों के आशियाने को तो उजाड़ा जा रहा है मगर सरकारी जमीन पर जो शो रूम बना कर लाखों रुपये का मोटा किराया वसूल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके लिए तो इस एक्सप्रेस–वे का रूट डाइवर्ट कर दिया और ग्रीन बैल्ट में से निकाल दिया। आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहुत बहस हुई थी और उस समय यह बात स्पष्ट हुई थी कि ग्रीन बैल्ट तो हुड्डा के प्लाट वालों की है क्योंकि उन लोगों ने उसकी कीमत दी है मगर इन नाजायज कब्जों पर कोई नहीं बोल रहा है। अगर इस बारे में कोई ऑफिसर्ज आवाज उठाएं तो रातों–रात उन ऑफिसर्ज के तबादले कर दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में गये थे और उन्होंने सफाई कर्मियों के पांव धोकर सम्मान दिया था। मेरी एन.आई.टी.–86 वहां के लोगों एवं पूरे फरीदाबाद की सीवरेज धोती है। हमारे यहां पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है मगर उसकी सुध

कोई नहीं ले रहा है। आज एन.आई.टी. की स्थिति ऐसी है कि कल फरीदाबाद की एक लड़की ने मेहंदी लगे हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया था कि मेरी गली में सीवरेज का पानी भरा है तो मेरी शादी कैसे होगी? एक दिन की सफाई तो हो गई मगर बाद में फिर वही स्थिति है। मैं उस गली की कल की फोटोज साथ में लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद भी आप सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो आप बजट में फरीदाबाद को क्या देंगे यह भी सोचने वाली बात है? इसी प्रकार से अगर पी.डी.एस. सिस्टम की बात की जाये तो आई.टी. के नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर देती है। मैंने माननीय मंत्री जी को एक वीडियो भेजा था जिसमें आज के समय में भी बाल्टी से गेहूं मापा जा रहा है। इस प्रकार आप गरीबों को कैसे राशन दे पायेंगे। अंत में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे मुख्यमंत्री जी भावुक हुए। आप मेरी स्थिति के बारे में सोचिये कि मेरी क्या स्थिति होती होगी। मेरी विधान सभा में मेरी मां, बहन, बेटी पेटीकोट उठा–उठा कर जाती हैं। लोग सोचते होंगे कि हम लोगों को उन्होंने किस लिए चुना है। क्या एन.आई.टी. –86 के लोगों ने अपने देवता स्वरूप पंडित शिवचरण लाल शर्मा के पुत्र को चुनाव जिता कर गलती कर दी । आप यहां कहते हो कि 'सबका साथ, सबका विकास' क्या यही 'सबका साथ, सबका विकास' है। मैंने पिछली बार भी सदन में आवाज उठाई थी कि स्कूलों तक पक्के रास्ते बनाए जाएंगे। क्या आपने माना? एक स्कूल का रास्ता भी अब तक पक्का नहीं बना।

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, धन्यवाद। समअप कीजिए।

श्री नीरज शर्मा : सर, मैं बिल्कुल समअप में आ गया हूं। मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। ऐसी बात नहीं है लेकिन गिला भी है कि गुरूग्राम और फरीदाबाद में मेट्रो की बात की गई और मैंने उसके लिए विशेष आग्रह भी किया लेकिन मुख्यमंत्री जी एन.आई.टी. 86 की तरफ से इसका रूट चेंज कर रहे हैं परंतु बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, आप अपनी बाकी मांगों को रिटन में दे दीजिए। वह रिकॉर्ड पर आ जाएगा।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में श्री मनोहर सरकार को एक ही बात कहना चाहूंगा कि एन.आई.टी. 86 के प्रत्येक वार्ड के लिए 10–10 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक गांव को एक–एक करोड़ रुपये का अनुदान

दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो ऐसे नहीं थे परंतु संगति का बड़ा असर होता है।

''कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन
जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन।।''

सी.एम. साहब यह बच्चा–बच्चा जानता है कि फरीदाबाद को फकीराबाद किसने बनाया। इस फरीदाबाद को वापिस फकीरबाद न बनने दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी कुछ और मांगे भी हैं। अगर आपकी सहमति हो तो इनको भी प्रौसीडिंग का पार्ट बना लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अगर आपकी इसके अतिरिक्त कुछ और मांगे हैं तो उनको रिटन में दे दें, उनको प्रौसीडिंग का पार्ट बना दिया जाएगा।

*** श्री नीरज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह मांग है और जिसके लिए मैं झोली पसार कर भीख मांग रहा हूं। मैं कोई फव्वारा नहीं मांग रहा, स्टेडियम नहीं मांग रहा। मैं कोई स्वीमिंग पुल नहीं मांग रहा, मैं कोई सैनिक स्कूल नहीं मांग रहा, यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहा। मैं तो बिल्कुल ना के बराबर अपने क्षेत्रवासियों के लिए जिंदगी जीने की राह मांग रहा हूं। मैं तो साल के 365 दिन सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी और गंदगी से निजात मांग रहा हूं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी, जय हिन्द, जय भारत।

श्री जगदीश नायर (होडल)(एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, बजट किसी सरकार का आईना व वित्तीय प्रबंधन होता है। आज बजट पर बहुत लम्बे समय से चर्चा चल रही है। बजट का मतलब यह है कि प्रदेश सरकार अपने प्रदेशवासियों के लिए किस तरीके से विकास की व्यवस्था करे। किस तरीके से हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करे। यह सरकार का एक प्रबंधन होता है, वित्तीय प्रबंधन होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2021–22 का जो बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय और प्रगतिशील बजट है। हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए यह 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जोकि वर्ष 2020–21 के बजट से 13 प्रतिशत अधिक

———————————————————

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

है। 38718 करोड़ रुपये की पूंजीगत खर्चे और 1 लाख 16 हजार 927 करोड़ रुपये के राजस्व खर्चे का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम शिक्षा की बात करें, बुढ़ापा पैंशन की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, गऊशालाओं व पर्यटक विभाग की बात करें, चाहे नगर ग्राम आयोजन की बात की जाए, पुलिस विभाग की बात की जाए, कृषि सुधार की बात की जाए और चाहे एस.सी.,बी.सी. कल्याण के सुधार की बात की जाए, इस बजट में हर वर्ग को, हर विभाग को ढेर सारा पैसा देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है। हमारे विपक्ष के साथी बजट में तरह–तरह की त्रुटियां लगा रहे थे। आज इतनी बड़ी आपत्ति काल के बाद जो कि बहुत बड़ा आपत्ति काल था जिस समय सारी दुनिया कोरोना काल से कांप रही थी। सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई थी। देश–विदेश के लोगों में एक विश्वास जाग चुका था कि किस तरीके से जीवन यापन होगा, कैसे ये अर्थव्यवस्था रास्ते पर आएगी? ऐसी कठिन परिस्थितियों में इतना प्रगतिशील व प्रदेश को चहुंमुखी विकास की तरफ ले जाने वाला बजट आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बार–बार बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बिन्दु शिक्षा पर बोलना चाहूंगा क्योंकि अगर सारे बजट पर बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा। शिक्षा मनुष्य जीवन का आधार है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने 18410 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। शिक्षा से आदि–अनादिकाल से ज्ञान का उदय हुआ। आज ज्ञान के उदय की वजह से हम सभ्य समाज के लोग, सारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए यहां इक्ट्ठे बैठकर एक अच्छी व्यवस्था के साथ लोगों की प्रगति और विकास की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के माध्यम से प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह बजट प्रगतिशील और तरक्कीशील बजट है। यह बजट हरियाणा की तकदीर बदलते हुए विकास की एक नई दिशा तय करने का काम करेगा। हरियाणा का हर गांव रोशन होगा, नई–नई सडकों का निर्माण होगा, स्वास्थ्य सेवायें बेहतर बनेंगी, बजट में जिस प्रकार से हर क्षेत्र के लिए 100 बैड के अस्पताल बनाने का जिक्र किया गया है वह भी काबिले तारीफ है। बजट के माध्यम से हर क्षेत्र के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। एजूकेशन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हमारे हरियाणा वासियों को देने का काम किया है। नोंवी से बारहवीं कक्षा तक के

बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब यमुनानगर, कैथल तथा सिरसा जिले में नए मैडिकल कालेज बनाये जायेंगे। महाराजा अग्रसेन के नाम से मैडिकल कालेज खोलने का काम भी किया जायेगा और अग्रोहा कैंसर विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किया जायेगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायक और 22 आयुष कोच की भर्ती की जायेगी, 21962 आंगनवाड़ियों में प्राथमिक शिक्षा देने का काम किया जायेगा, 1135 नए प्ले वे स्कूल मार्च, 2021 से शुरू हो जायेंगे। यहीं नहीं हरियाणा प्रदेश में 4000 प्ले वे स्कूलों का सृजन करने का भी काम किया जा रहा है जिससे हमारे नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी कारगर व्यवस्था कायम हो सकेगी। यही नहीं 2865 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जायेगा। बजट के माध्यम से उच्च वित्तीय सहायता के लिए 114 करोड़ रूपये का जैंडर इंकलुजन फंड बनाया जायेगा जोकि हरियाणा सरकार का एक नया कदम है। हिसार, करनाल में सुपर 100 कार्यक्रम के लिए दो केन्द्र बनाये जायेंगे। 10 करोड़ रूपये की लागत से सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ रूपये की लागत से डिजिटल क्लास रूम बनाने व टैबलेट्स का प्रावधान किया जायेगा। पहली से तीसरी तक के 84 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थियों को प्रारम्भिक भाषा व गणितीय कौशल प्रदान करने काम किया जायेगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 9वीं से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए एक फीडर स्कूल बनाने का काम किया जायेगा तथा विश्वकर्मा कौशल रथ के नाम से मोबाइल आई.टी. लैब विकसित की जायेगी। इस विश्वविद्यालय में पी.एच. डी. के लिए अनुसंधान डिग्री कालेज शुरू होंगे। उपाध्यक्ष महोदय वर्ष 2021–22 के दौरान स्कूलों/कालेजों/ तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के बाद अब मैं अपने हलके की कुछ मांगे रखना चाहता हूँ। हमारे यहां खाम्बी में कन्या महाविद्यालय बनाने की जरूरत है, हसनपुर में नए अस्पताल की बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, मिडुकी में 400 एकड़ में गउशाला बनाई जाये, गांव बन्चारी में ब्रिज फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, हमारे यहां बृज यात्रियों के रुकने के लिए 1000 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था एवं पार्क, स्नान गृह व सुलभ शौचालय बनाने की जरूरत है, गांव गढ़ी में यू.डी.डी. (उजीना ड्रेन) विजयगढ़ में रेगुलेटर लगाने की जरूरत है, वासवा शेखशाई में प्राचीन मंदिर/तालाब/पार्क व सुलभ शौचालय

बनाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के समय दिया इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.ज.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपकी बहुत–बहुत आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री` वर्ष 2021–22 का बजट सदन के पटल पर रखा है। हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, बजट ऐसा पेश किया गया है जैसे बीमारू स्टेट का होता है। यह आम बजट है और इस आम बजट को पढ़कर ऐसा लगा कि यह खास लोगों एवं पूंजीपतियों के लिये ही बना है। यह बजट बिल्कुल दिशाहीन, निराशाजनक और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है। हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस बजट के माध्यम से कमेरा वर्ग व किसान बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हमारे लिये कोई पैकेज की घोषणा करेगी लेकिन सरकार ने किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया। हरियाणा सरकार ने 'किसान मित्र योजना' के नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में किसानों को मित्र कहा गया है लेकिन सरकार किसानों से व्यवहार दुश्मनों जैस कर रही है। इस योजना के अनुसार राज्य में 1000 किसान ए.टी.एम. स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है और अपने हकों की मांगों के लिये आंदोलनरत है उसमें किसान ए.टी.एम. का क्या लाभ है। इस योजना का भी जन–धन योजना जैसा ही हाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सदन में कहना चाहती हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरस्वती दिवस मनाया जा रहा है लेकिन माँ सरस्वती के शिक्षा के मन्दिर जो हैं उनका क्या हाल हो गया है, यह बात हम सबको पता है। शिक्षा का अधिकार कानून आया और सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात हुई थी। लेकिन आज 1000 से ज्यादा स्कूल्ज को बंद किये जाने का काम किया जा रहा है। 136 मॉडल संस्कृति स्कूल्ज की चर्चा बहुत होती है, जिसकी सूची मेरे पास इस समय उपलब्ध है। सरकार ने 136 मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दिये हैं, मगर यह बात भी सदन को पता चलनी चाहिए कि जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल्ज थे उनको भिवानी बोर्ड की जगह सी.बी.एस.ई. में कंवर्ट कर दिया गया है क्योंकि सरकार को भिवानी बोर्ड की कार्य प्रणाली पर विश्वास नहीं रहा है। मेरे क्षेत्र में जो स्कूल खोले हैं उसमें केवल मॉडल संस्कृति स्कूल का बोर्ड लगाने का काम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में इस बात का भी पूरी तरह से विरोध

करती हूँ कि जो आरक्षित हल्के हैं क्या उनमें शिक्षा के क्षेत्र को लेकर ज्यादा कार्य हो रहे हैं? स्कूल के नाम के साथ हल्के के रिजर्व कैटेगरी का क्यों नाम लिख देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 तक आठवीं की बोर्ड की परीक्षाएं क्यों नहीं हुई। आज स्कूलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में डाईट है और उनको बंद करने का काम किया जाता है। जिसमें हमारे 2 वर्ष डी.एल.एड. के कोर्सिज होते थे। केवल सेल्फ फाइनेंस (प्राईवेट कॉलेज) में एडमिशन करवा रहे हैं और डाईट को बंद कर रहे हैं। जिसमें गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। सरकार ने कहा है कि 4 हजार प्ले–वे स्कूल खोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 1135 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले–वे में कंवर्ट कर दिया गया है। उसमें 0–3 साल के बच्चों के साथ स्तनपान करने वाली माताएं जायेंगी उनको कहां पर शिफ्ट करने का काम किया जायेगा, इस बात का जवाब भी सदन को देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे 36 आरोही मॉडल स्कूल्ज नेशनल स्तर पर आईडैंटिफाई हुए थे, उनके लिये भी इस बजट पर कोई प्रावधान नहीं किया है। सरकार ने आज तक न तो इन स्कूलों की संख्या बढ़ाई है और न ही नियमित रूप से स्टाफ की भर्ती करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रारंभ स्टेट इंस्टीच्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, झज्जर में वर्ष 2013 में क्लासिज शुरू हुई थी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी बजट में प्रावधान करने के बाद भी इसकी बिल्डिंग बनाने का काम नहीं हुआ है। सैनिक स्कूल के लिये भारत सरकार की तरफ से बजट आया हुआ है, इसमें 100 सैनिक स्कूल्ज खोलने की बात कही गई है। मातनहेल में सैनिक स्कूल की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बाद भी क्लॉस शुरू नहीं हुई है। के.जी. टू पी.जी. के बारे में कहा गया है कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र और महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक में पढ़ाई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था और उसमें स्कूल से लेकर मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था थी, इसके लिये सरकार ने बजट में केवल 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 20 करोड़ रुपये में तो यूनिवर्सिटी की चार दीवारी भी नहीं बनती है। सैंट्रल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो एक मात्र पूरे देश में हमारी यूनिवर्सिटी थी, उसके लिये न तो बजट

में जिक्र होता है और न ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र होता है। आज तक इस यूनिवर्सिटी के रूल्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। जब हमारे प्रदेश के बच्चे खेल कूद में आगे हैं तो हमारे प्रदेश के बच्चे सैनिक भी बहुत हैं, इस प्रकार से जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन सकती है तो हमें उनके बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। आज सरकार से सदन यह जानना चाहती है कि एक भी यूनिवर्सिटी का काम पूरी तरह से डिवैल्प किया है तो उसका नाम सदन में बताया जाये। डॉ.भीम राव अंबेडकर जी के नाम से डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राई (सोनीपत) का वर्ष 2012 में एक्ट पास हुआ था, वर्ष 2021 आ गया है लेकिन आज तक भी लॉ की क्लास नहीं लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, अब आप वाइंड अप कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर कर रही हूं । राई स्पॉर्ट्स स्कूल को हम भी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे लेकिन जब यह सरकार आई तो इसने उस स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाकर उसके रूल्ज को विड्रॉ करने का काम किया । मैं पूछना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है ? सरकार हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन कर रही है । इससे रिजर्व्ड कैटेगरीज की रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगी । आज बैंक के कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए दो दिन हो चुके हैं क्योंकि उनको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है । प्राइवेटाइजेशन के बहाने रिजर्व्ड कैटेगरीज की रिजर्वेशन पर डाका मारने का काम किया जा रहा है । रेल, जहाज और अनेक चीजों को प्राइवेट पार्टीज को बेचा जा रहा है । हैल्थ सैक्टर में केवल नामकरण किये जा रहे हैं । जो मैडिकल यूनिवर्सिटी पहले 'कल्पना चावला' के नाम से बननी थी उसका नाम बदलकर अब उसे 'दीन दयाल उपाध्याय' के नाम से खोला जा रहा है लेकिन उसकी भी आज तक केवल चारदीवारी ही हो पाई है । 'श्री कृष्णा आयुर्वेदा युनिवर्सिटी' की अभी माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी बात कर रहे थे लेकिन इसकी आज तक चारदीवारी भी नहीं बनी है और वाइस चांसलर के बैठने का कमरा भी आज तक नहीं बना है । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 100 बैडिड हॉस्पिटल को 200 बैडिड हॉस्पिटल किया जाएगा । मेरा प्रश्न है कि प्रदेश में जब डॉक्ट्र्स की शॉर्टेज है तब हॉस्पिटल्स में बैड की क्षमता बढ़ाने का क्या फायदा है ? मेरे हल्के में मात्तनहेल में एक 50 बैडिड हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन सरकार ने वहां पर अभी तक कोई भी स्टाफ डिप्यूट नहीं किया है । मेरा कहना है कि फूड एण्ड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट में एक स्टेट फूड लैबोरेट्री भी

अवश्य बनी होनी चाहिए ताकि प्रदेश में खाने में मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जा सके । इम्पलॉयमैंट के विषय पर मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश में युवाओं को जॉब्स तो देने की बात कही गई लेकिन उनको जॉब्स नहीं दी जा रही है । बेरोजगार युवाओं को 'सक्षम युवा' के नाम से छोटा–मोटा काम देकर केवल युवाओं को बहकाने का ही काम किया जा रहा है । 'मनरेगा' के तहत काम करने वाले मजदूरों को 100 दिन का काम मिलना उनका कानूनी हक है लेकिन उनके जॉब कार्ड ही नहीं बनाए जा रहे हैं । इसके अलावा जिन मजदूरों के जॉब कार्ड बने भी हुए हैं तो उनको काम की पेमेंट नहीं की गई है । अगर सरकार उन मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो सरकार को उनको अनइम्पलॉयमैंट अलाउंस देना चाहिए । जिन लोगों ने कुरूक्षेत्र में धरना दिया सरकार ने उन पर झूठे केस बनाने का काम किया है । मुझे बजट के बारे में बातें तो बहुत करनी थी लेकिन बोलने की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए मैं केवल अपने क्षेत्र की बात सदन में रखकर अपनी बात समाप्त करूंगी । मेरा हल्का आज पूरी तरह से सरकार की अनदेखी का शिकार है । (विघ्न) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपको बोलते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सड़कों पर आये दिन एक्सीडैंट्स होते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि झज्जर–बहू रोड को फॉरलेन किया जाए । वहां पर एन.टी.पी.सी., अल्ट्राटेक सीमेंट, जे.के. लक्ष्मी जैसी कम्पनियों के अनेक कारखाने खुल चुके हैं । सी.एस.आर. (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी) के तहत इंडस्ट्रीज इसके लिए पैसा भी देना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि वहां पर बहुत लम्बा जाम लगता है और एक्सीडैंट्स भी होते हैं, इसलिए वहां पर एक ओवरब्रिज बनाने का काम किया जाए । इसके अलावा मैंने सदन में एक सैनिक स्कूल बनाने का भी जिक्र किया था । मुझे सदन में छुछकवास बाइपास को बनाने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए कृपा करके उसको पूरा करने का काम किया जाए । (घंटी) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अब आप बैठ जाइये क्योंकि आपको बोलते हुए 9 मिनट हो चुके हैं । आपको बोलने के लिए 5 मिनट दिए गए थे लेकिन अब आपको बोलते हुए इससे लगभग डबल टाइम हो चुका है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारे झज्जर की भिंडावास लेक की वजह से मेरे क्षेत्र के 6–7 गांवों में पानी की बड़ी दिक्कत है । सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही नीरस बजट पेश किया है । यह बजट हमें तरक्की की राह पर ले जाने की बजाय पीछे की ओर ले जाने का काम करेगा ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अगर आपकी कोई बात कहे बगैर रह गई हो तो आप उसे लिखकर सदन के पटल पर रख दीजिए । हम उसे सदन की कार्यवाही में शामिल करवा देंगे ।

***श्रीमती गीता भुक्कल :** ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के से संबंधित मांगों को लिखित रूप में सदन के पटल पर रख देती हूं । आपसे अनुरोध है कि इसे सदन की कार्यवाही में शामिल करवा देना । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के झज्जर में नई सब्जी मण्डी के आढ़तियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । नई सब्जी मण्डी, झज्जर में लगी टीन शेड काफी पुरानी है और उसकी जीर्ण–शीर्ण हालत हो चुकी है । इस बारे में हमने विभाग को कई बार लिखित रूप में शिकायत भी की है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया । इसके अलावा सब्जी मण्डी में सीवरेज व्यवस्था तीन–चार दिन में फेल हो जाती है । इससे गंदा पानी सब्जी मण्डी परिसर में फैल जाता है । अतः इसका निवारण किया जाए । अध्यक्ष महोदय, जब नई सब्जी मण्डी, झज्जर में दुकानों को नीलाम किया गया था तब सब्जी मण्डी में बने प्लेटफॉर्म को किसानों का माल उतारकर नीलामी करने के लिए रखा गया था । वर्ष 2019 में मार्किट कमेटी विभाग ने इस प्लेटफॉर्म को रिटेलर को किराये पर देकर 1500 रूपये प्रति महीना किराया वसूलकर सरकार की आमदनी बढ़ाने का काम किया था । आज उस सब्जी मण्डी में किसानों के माल को उतारकर नीलामी करने के लिए जगह नहीं बची है । इस कारण किसानों को माल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है । इसके अलावा सब्जी मण्डी में दुकानों के सामने बने सर्विस रोड का निर्माण दो दशक से भी पहले किया गया था जिस पर आज बरसात में पानी भरा रहता है । विभाग द्वारा इस शेड पर मरम्मत का कोई कार्य नहीं करवाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सभी मण्डियों के मेन गेट पर ऊँचे–लम्बे सूचक गेट बने हुए हैं । अतः उस मण्डी के मेन गेट पर (झज्जर की नई सब्जी मण्डी के नाम पर) एक गेट बनवाया जाए । इससे शहर के

***चेयर के आदेशानुसार उपर्युक्त लिखित स्पीच कार्यवाही में शामिल की गई ।**

सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा । इसके अलावा झज्जर की नई सब्जी मण्डी में मांसाखोरों को सब्जी का कार्य करने के लिए जो जगह दी गई थी वह काफी कम है । वहां पर 70–80 मांसाखोर सब्जी का कार्य कर रहे हैं । वे उनका किराया भी नहीं दे रहे हैं । अतः इन खाली पड़े प्लॉटों को रद्द करके सब्जी का कार्य करने वालों की जगह को बढ़ाया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी इन मांगों को अवश्य पूरा किया जाए ।

श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । आज मुझे इस महान् सदन को यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हरियाणा के विकास पुरूष श्री मनोहर लाल जी ने समाज की आधी आबादी यानि नारी शक्ति के उत्थान, संरक्षण और उनके विचारों को सकारात्मक दिशा देने के लिए 6 वर्षों में हरियाणा में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं और उससे जो बदलाव हो रहे हैं उसे सभी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बात का जीता–जागता उदाहरण स्वयं मैं आपके सामने हूं । हमारी पार्टी ने राजनीति में परिवारवाद को खत्म किया है । अगर परिवारवाद को खत्म नहीं किया गया होता तो गन्नौर कांस्टीच्यूएंसी से एक ही परिवार के लोग एम.एल.ए. बनकर विधान सभा में आते रहते । अतः हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं । आज हरियाणा प्रदेश कैरोसिन मुक्त प्रदेश है और हमारे प्रदेश में 8,20,572 गरीब परिवारों को गैस के कनैक्शंज प्रदान किये गए हैं । महिला सुरक्षा को तवज्जो देते हुए हमारे प्रदेश में कुल 21 महिला थाने खोले गए हैं जबकि हरियाणा के बनने के बाद पिछले 48 सालों में केवल 2 महिला थाने ही खोले गए थे । इसी तरह महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 'दुर्गा शक्ति' ऐप्लीकेशन शुरू की गई है तथा 'दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फॉर्स' का गठन किया गया है । हमारी सरकार ने 12 वर्ष की बालिका के साथ जघन्य अपराध करने वालों को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान किया गया है । गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत राज्य में 9,358 बच्चों की पहचान करके 7,877 बच्चों को उनके मां–बाप/संरक्षकों से मिलवाया है । हमारी सरकार ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट तथा एम.टी.पी. एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जनवरी, 2021 तक 865 एफ.आई.आरज. दर्ज की हैं। लोकतंत्र की पहली सीढी पंचायती राज संस्थाओं और शहरों की सरकार में जन

प्रतिनिधि की परम्परा में बदलाव किया गया। यह इसी बात का नतीजा है कि उनमें हरियाणा प्रदेश के सभी जन प्रतिनिधि शिक्षित हैं। आमतौर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात उठती रही है, लेकिन हमारी सरकार के समय में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 42 प्रतिशत महिलाएं जन प्रतिनिधि चुनकर आयी हैं। हरियाणा प्रदेश के 333 गांवों की कमान बेटियों के हाथों में है। आज गुरूग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला में महापौर भी महिलाएं हैं। आज पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का संकल्प लिया गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। कोविड–19 महामारी के दौरान ड्यूटी करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्ज, आशा वर्कर्ज और सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। अब तक हरियाणा प्रदेश में 67 नये कॉलेजिज खोले गये हैं। इनमें से 42 कॉलेजिज लड़कियों के लिए हैं और 25 को–एड कॉलेजिज हैं। पिछले 48 सालों में लड़कियों के लिए 31 कॉलेजिज खोले गये हैं जबकि हमारी पार्टी की सरकार के समय में लड़कियों के लिए 42 नये कॉलेजिज खोले गये हैं। सरकार द्वारा 151 रूटों पर महिला बस सेवाएं शुरू की गयी हैं। छात्राओं के लिए अब बस पास 150 किलोमीटर तक की दूरी का कर दिया है। अब तक 400 बसों में सी.सी.टी.वी. कैमराज लगवाये जा चुके हैं। नौंवी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी गयी है तथा इसके लिए 6,000 वाहन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पी.पी.पी (परिवार पहचान पत्र) बनाने का काम शुरू किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि जब हम गांवों में जाकर देखते थे तो बी.पी.एल. का उचित पात्रों को लाभ नहीं मिलता था। पहले जब बी.पी.एल. बनवाने के लिए एप्लाई किया जाता था तो उसके बाद सर्वे किया जाता है। यदि कोई परिवार वाकई में उसका हकदार है और उसने उस सरपंच को वोट नहीं दिये थे तो वह उसका बी.पी.एल. कार्ड नहीं बनने देता था। अब पी.पी.पी. बन जाएगा जिससे बी.पी.एल. कार्ड जरूरतमंदों लोगों का ही बनेगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पैंशन बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी है। यह पूरे देश के राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में सबसे अधिक है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी खानपुर यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर की क्लासिज बन्द कर दी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध

करना चाहूंगी कि कम्प्यूटर की क्लासिज बन्द न की जाएं क्योंकि कुछ लड़कियों ने पढ़ने के लिए ऑनलाईन आवेदन भी किया था। चूंकि आज कम्प्यूटर का युग है तो उसमें कम्प्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कम्प्यूटर की क्लासिज बन्द होने से 6 प्रोफेसर्ज भी प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपा करके वहां पर कम्प्यूटर की क्लासिज शुरू करवायी जाएं। मुझे गर्व है कि कोविड–19 की बीमारी के दौरान महिलाओं ने फ्रंट लाईन वर्कर के तौर पर अपनी जिम्मेवारी को जान को जोखिम में डालकर निभाया है। उनकी दिन–रात की गयी मेहनत को मैं सलाम करती हूं और मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस उत्कृष्ट भूमिका के लिए नारी शक्ति के प्रति सम्मान दर्शाएं। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन महिलाओं को सभापति बनने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, यह काबिले तारीफ बात है। इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। अन्त में, मैं अपने संबोधन को स्वामी विवेकानन्द के कथन के साथ समाप्त करना चाहूंगी।

नारी का उत्थान स्वयं नारी करेगी,
कोई और उसे उठा नहीं सकता।
वह स्वयं उठेगी।

बस उठने में उसको सहयोग की आवश्यकता है जो आप कर रहे हैं। जब वह उठ खड़ी होगी तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। वह उठेगी और समस्त विश्व को अपने जादुई कौशलता से चमत्कृत करेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं साथ ही मैं इस बजट की बहुत सराहना करती हूं।

मोहम्मद इलियास (पुन्हाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं बजट पर कम ही बोलूंगा। मैं एक विशेष बात यह भी बताना चाहूंगा कि इस बजट पर कम ही बोलूंगा चाहे आप मुझे बोलने के लिए ज्यादा टाइम भी दे दें। आप मुझे ज्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे तो भी मैं कम ही बोलूंगा। मेरा पहले से ही यह फैसला है।

श्री अध्यक्ष: इलियास जी, आपके बोलने के लिए 5 मिनट का समय तय किया गया है। आप इस समय में ही अपनी बात कम्प्लीट करें।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे ईयरवाईज 2–2 मिनट जोड़कर समय देंगे तो भी मेरा बोलने के लिए 8 मिनट का समय बनता है। चूंकि मैं अब चौथी बार विधायक चुनकर आया हूं।

श्री अध्यक्षः इलियास जी, आपको बोलने के लिए 8 मिनट का समय दे देंगे।

18:00 बजे

मोहम्मद इलियास :अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रदेश के बजट का ताल्लुक है। इस बजट की बुनियाद ठीक उसी तरह से लागू होती है, जिस तरह से एक किसान अपने घर के लिए साल भर का बजट बनाता है। जब उसकी फसल तैयार होती है। उसके बाद उस पैसे का जब वह आदान प्रदान करता है तो वह किसान साल भर का बजट लेकर चलता है कि मुझे एक साल में क्या–क्या काम करने हैं? इसी तरीके से प्रदेश की सरकार जब बजट तैयार करती है तो इसमें सरकार की तरफ से यह बात दर्शाई जाती है कि सरकार ने वर्ष 2020–21 में क्या–क्या काम किए हैं और वर्ष 2021–22 में क्या–क्या काम किये जायेंगे? अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह बात कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट के माध्यम से सरकार ने जो काम किये थे वे काम इस बजट में नहीं दर्शाये गये हैं। उन्होंने इस बजट के माध्यम से यह बात कह दी कि सरकार ने ये काम करने हैं और इस प्रकार की योजनाएं बनानी हैं आदि। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बजट के बारे में यही कहना है कि यह बजट बिल्कुल दिशाहीन बजट है क्योंकि न तो इस बजट में व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली बात की गई है, न ही इस बजट में किसानों को कोई राहत देने वाली बात की गई है, न ही कर्मचारियों को कोई राहत देने वाली बात की गई है और न ही इस बजट में आम मजदूर को राहत देने वाली कोई बात की गई है। इस बजट में अगर कुछ दर्शाया गया है तो वह यह दर्शाया गया है कि हम इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए इतना बजट प्रस्तावित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बजट के माध्यम से इस बात का जिक्र किया है कि आज हरियाणा सरकार पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का भार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने वर्ष 2020–21 में क्या–क्या कार्य किए और कौन–कौन से कार्य इम्प्लीमैंट हुए? इस बारे में सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है लेकिन इस बजट में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि सरकार इस साल क्या–क्या कार्य करने जा रही है? मेरे हल्के पुन्हाना में पुन्हाना और पिनगंवा दो शहर पड़ते हैं। सरकार

ने पिछले वर्ष इनके लिए बजट में प्रावधान कर दिया था परन्तु उस बजट का आज तक कागजों में नाम नहीं आया है। उसकी आज के दिन क्या पोजीशन है? मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि आजकल फसल कटाई का सीजन आ रहा है। जिसके कारण हमारे यहां के दोनों कस्बों में पूर्ण रूप से ट्रैफिक जाम लग जाता है इसलिए वहां पर बाइपास बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की मांगों के बारे में इस सदन का दो मिनट का और समय लूंगा। मेरे यहां एक सिंगार गांव है, इसमें 20 हजार वोट है और इस गांव की 50 हजार आबादी है। आज तक इस गांव की प्यासी धरती की एक एकड़ भूमि को पानी नहीं मिला है। वहां पर करीब 2–3 साल पहले पम्प हाउस तो बनाया गया था लेकिन वहां पर अभी तक पम्प नहीं लगाया गया है इसलिए मेरी विनती है कि वहां पर पम्प लगाया जाये तो मैं समझता हूं कि इससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। यह मेरी सरकार से मांग और निवेदन भी है। इसी तरह से हमारे यहां पर एक बिछौर गांव है वह भी बहुत बड़ा गांव है। वहां पर भी पम्प हाउस बना हुआ है लेकिन अभी तक पम्प नहीं लगाया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर जल्द से जल्द पम्प हाउस लगाने का काम किया जाये। इसी पड़ोस में एक बड़ा गांव भी आता है, वहां पर पम्प हाउस का काम चालू हो गया है। मैं इसके लिए सरकार का आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर पम्प हाउस चालू नहीं हुआ है तो वहां पर पम्प हाउस चालू करवा दिया जाये क्योंकि जब इस बड़ा गांव में पानी जायेगा तो उसके साथ लगते हुए 10–15 गांवों की प्यासी भूमि को भी सिंचित करने का काम करेगा। जिससे वहां के किसानों के लिए यह बात फायदेमंद होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि शाहपुर के पास जो डिस्ट्रीब्यूट्री गुजरती है। वहां पर भी एक पम्प हाउस बना हुआ है लेकिन अभी तक वहां पर पम्प का प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि कृपया करके वहां पर पम्प लगवाया जाये ताकि वहां के किसान अपनी कृषि भूमि की सिंचाई कर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक बादली गांव है। जब बादली गांव से जाट गांव की तरफ जाते हैं तो उजीना डायवर्शन ड्रेन से क्रॉस करना पड़ता है और वहां पर लगभग 500–700 एकड़ भूमि है जो बगैर जुताई के और बगैर बुआई के रह जाती है क्योंकि वहां पर पुल नहीं है इसलिए वहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से

आना–जाना नहीं कर सकता। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह रिकवैस्ट है कि बादली के पास एक पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाये। गांव गुलेरका, नहरका व सुनेरा और और इनके साथ लगते लगभग 20 गांव और हैं इन सभी गांवों में जलभराव हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक डिप ड्रेन बनाई जाये ताकि जरूरत के समय पानी उस डेन में चला जाये और किसान अपने खेतों में बिजाई कर सकें। पिछली दफा भी मैंने बजट सैशन के दौरान कहा था कि मेरे हल्के में एक गंगवाड़ी माइनर है, उसके दो हिस्सों का काम पूरी तरह से कम्पलीट हो चुका है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उसकी टोटल सिर्फ 10 किलोमीटर की लम्बाई है उसमें से 7 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और इस समय केवल 3 किलोमीटर के हिस्से का ही काम बाकी है। मेरी सरकार से यह रिकवैस्ट है कि इस माईनर के 3 किलोमीटर के हिस्से को भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि जमीनदारों की फसल में पानी पहुंचाया जा सके। मेरी माननीय खेल मंत्री जी से भी रिक्वैस्ट है कि हल्का पुन्हाना के अंदर खेल का कोई भी स्टेडियम नहीं है इसलिए मेरे हल्के पुन्हाना में जल्दी से जल्दी एक राज्य स्तर के स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये और उसमें सभी खेलों से सम्बंधित तमाम प्रकार की सुविधायें तुरंत उपलब्ध करवाई जायें ताकि मेरे हल्के के नौजवान बच्चे और बच्चियों को वहां पर अपने मनमाफिक खेल की प्रैक्टिस करने की तालीम व सुविधा प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से मेरे हल्के में दो–तीन पम्प हाउसिज की मांग काफी समय से लम्बित चली आ रही है जिसकी पूरी की पूरी जानकारी इरीगेशन विभाग के पास है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि मेरे हल्के के जितने भी पम्प हाउसिज का कार्य पैंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि मेरे हल्के के जमीनदारों को उनकी फसल के लिए पानी प्राप्त हो सके। स्पीकर सर, मैं एक शे'र अर्ज़ करके अपनी बात समाप्त करना चाहूता हूं कि – जैसी करनी, वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है और दोजख भी है अर्थात् मरने के बाद स्वर्ग भी है और नरक भी है अगर कोई न माने तो मरके देख। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रवीण डागर (हथीन): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2021–22 के बजट पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं

आपका धन्यवाद करता हूं। वित्त वर्ष 2021–22 के बजट से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से बजट पूर्व चर्चा करके उनके विचार सांझा किये हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हम सभी को यह बजट तैयार करने में शामिल किया गया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश हित में एक सार्थक पहल है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,55,645/– करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2020–21 के 1,37,738/– के बजट से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। इसमें किसान, कमेरे, मजदूर व छोटे व्यापारी, युवा तथा शिक्षा सड़क स्वास्थ्य व उद्योग सभी को महत्व दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं 100 क्यूसिक मेवात फीडर नहर तथा सिंचाई के लिए लगभग 5 हजार 81 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से उन्होंने मेवात के लोगों की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस मेवात के लोगों को भरोसे में रख कर उनका वोट लेती रही लेकिन मेवात की प्यासी धरती की प्यास बुझाने की कभी कोशिश नहीं की। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मेवात के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने खुद किसानी का काम किया है। चाहे गेहूं की कटाई की बात हो या अन्य दूसरे कृषि कार्यों की बात हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इस बजट में एक नई पहल की है। कृषि एवं किसानों के आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2021–22 में बजट अनुमान 6110 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें लगभग 3 हजार करोड़ रुपये कृषि व किसान कल्याण के लिए 498 करोड़ रुपये बागवानी के लिए तथा 1225 करोड़ रुपये पशुपालन व डेयरी विभाग के लिए रखे है। 125 करोड़ रुपये मछली पालन के लिए व 1274 करोड़ रुपये बजट में सहकारिता विभाग के लिए निश्चित किये हैं जो कि वर्ष 2020–21 के 5052 करोड़ रुपये की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हल्के व समस्त प्रदेश के किसानों की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा, बागवानी को बढ़ावा दिया तथा सोनीपत के गन्नौर में लगभग 545 एकड़ जमीन पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी स्थापित करके एक नया इतिहास रचने का काम किया है। इसी प्रकार से आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16000

रुपये से बढ़ाकर 20,000/– रुपये प्रति एकड़ की गई है जो कि किसानों के लिए एक नई सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हरियाणा रबी की फसलों गेहूं, चना, सरसों और सूरजमुखी तथा खरीफ की फसलों धान, बाजरा, मक्का, मूंग और मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है। कोविड–19 महामारी के बावजूद भी सरकार ने रबी 2020–21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। इसी प्रकार से खरीफ की फसलों में 2020–21 के दौरान सरकार द्वारा 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई है जो कि अपने आप में एक इतिहास रचने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। विपक्षी पार्टियों के लोग कहते थे कि बाजरे की फसल की खरीद कहां पर हो रही है उनको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एम.एस.पी. पर हुई है और किसी भी किसान का एक भी दाना बगैर खरीद के नहीं रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बाजरे की 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद की जाती है उसे बढ़ा कर 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाये। आजकल नये–नये बीज आये हुए हैं और किसान भी ज्यादा उत्पादन लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, मजदूरी, दवाई व खाद सभी का इस्तेमाल करके एक अच्छी पैदावार लेना चाहता है। मेरी सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह किसानों की यह सबसे बड़ी मांग है कि बाजरे की एम.एस.पी. पर 8 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद को बढ़ा कर 12 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाये। इसी तरह से जो गेहूं की खरीद 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एम.एस.पी. पर की जाती है उसको भी बढ़ा कर 24 क्विंटल प्रति एकड़ करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रवीण जी, आप वाइंडअप कीजिए। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रवीण डागर : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सीनियर विधायक साथी तो सदन में बहुत सालों से लगातार बोलते आ रहे हैं लेकिन हमारे कम से कम 44–45 विधायक अभी पहली बार ही चुनकर आए हैं। मैं भी पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए मैं अपने सीनियर विधायकों से कहना चाहूंगा कि वे अपना बोलने का समय थोड़ा कम रख लिया करें और जो हमारे नये–नये विधायक साथी हैं, जिनको यहां सदन में बोलने का पहला मौका मिल रहा है। उनको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए जिससे वे सीनियर साथियों के अनुभव भी

प्राप्त कर सकें अपने हल्के की मांग भी रख सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी मोहम्मद इलियास जी ने कहा है कि मैं 20 साल से इस सदन में आ रहा हूं तो मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पिता जी भी इस सदन के मैंबर रहे थे और मुझे भी इस सदन का मैंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं इसलिए मुझे एक–दो मिनट का समय और दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : डागर जी, आप अपनी मांगों को रिटन में दे दीजिए उसको हम प्रौसीडिंग का पार्ट बना देंगे।

श्री प्रवीण डागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मुझे एक–दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं सारी जिन्दगी थोड़ी ही मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

श्री प्रवीण डागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पलवल वाया मंडकौला (नूंह) स्टेट हाई–वे नं. 13 इन दोनों जिलों को जोड़ने का मुख्य मार्ग है। वहां पर दो लेन रोड है और उस पर बहुत ज्यादा व्हीकल्ज हैं और वहां सवारी भी बहुत ज्यादा हैं इसलिए उस रोड को फोर लेन किया जाए तथा इसको दिल्ली–मुम्बई–बड़ौदरा–हाई–वे, के.एम.पी. जो इंटर चेंज मेरे गांव मंडकौला से होकर जा रहा है। उस दिल्ली–मुम्बई–बड़ौदरा–हाई–वे को इंटर चेंज से भी जोड़ने का काम करें। गांव मंडकौला और आस–पास के लगभग 30–40 गांवों के किसानों का केन्द्र बिन्दु है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि गांव मंडकौला में जोकि मेरा अपना पैतृक गांव भी है और वह बहुत बड़ा गांव है जिसमें लगभग 18 हजार की आबादी है। वहां पर एक अनाज मंडी का निर्माण करवाया जाए। गांव मंडकौला में लगभग 50 एकड़ जमीन अर्थात हमने लगभग 440 कनाल जमीन कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए दी थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर एक कृषि विज्ञान कॉलेज खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आखिरी निवेदन है जोकि किसानों से संबंधित है। सरकार हमारे किसानों को ए.पी. फीडर पर खेतों के ट्यूबवैल्ज के लिए जो 8 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। मेरा अनुरोध है कि उस बिजली को बढ़ाकर 10 घंटे किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रगतिशील बजट के लिए बहुत–बहुत तह दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री चिरंजीव राव (रिवाड़ी) : सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज बजट पर सबसे आखिर में बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : अभी तो आपसे पीछे और भी सदस्य हैं। यह मैंने नहीं दिया है यह लिस्ट तो आपके नेता ने ही दी है और मैं उसी क्रम से बुलवा रहा हूं।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष जी, मेरे दादा इस सदन में तीन बार विधायक रहे और मेरे पिता जी भी लगातार छः बार विधायक बनकर सदन के अन्दर आए और वे यहां पर वित्त मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने भी यहां तीन–चार बार बजट पेश किया। मैं जब ये बजट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि विपक्ष के जितने भी विधायक होते हैं वह यही कहते हैं कि यह बजट दिशाहीन है लेकिन सही मायने में अगर किसी बजट को दिशाहीन कहेंगे तो इस बजट को कहेंगे। आप ये देखिये कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि आपका जो बजट है वह 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये का बजट है और सरकार की जो देनदारी है वह 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इसमें आपके बजट का जो 30 प्रतिशत हिस्सा है वह तो इसका ब्याज देने में ही चला जाएगा और इस बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा सैलरी व और खर्चों में चला जाएगा तो 30 प्रतिशत ही बचा। उस 30 प्रतिशत में प्रदेश का क्या विकास हो पाएगा। यह आप भली–भांति जानते हैं। इसमें एक और बात देखने वाली है कि वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक तकरीबन 48 साल में हमारा जो कर्ज था वह 74 करोड़ रुपये था और पिछले छः साल में यह कर्ज दो लाख करोड़ रुपये पार हो गया है तो सोचने वाली बात यह है कि छः साल में 1 लाख 28 हजार 892 करोड़ रुपये कहां लगे हैं क्योंकि हमें तो कहीं कुछ विकास होता नजर नहीं आ रहा है। मैं जब बजट को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि देखता हूँ शायद इसमें रेवाडी के लिए भी कुछ बातें निकल आयें। मैंने पाया कि बजट भाषण में लिखा था कि रेवाड़ी में स्ट्रांग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि यह तो कह रहे हैं कि काम खत्म हो गया जबकि काम तो शुरू ही नहीं हुआ। सरासर झूठ बोलने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। मेरे शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कालोनियां हैं, माडल टाउन है तथा एक शिव कालोनी है वहां पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है लेकिन बजट में यह कहा जाना कि मेरे क्षेत्र में स्ट्रांग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का काम पूरा हो गया है बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इसकी इंक्वॉयरी करवाई जाये कि जिन अधिकारियों ने यह बजट बनाया है आखिरकार वे क्यों माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह से मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। बजट में रेवाड़ी के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई जबकि असलियत में रेवाडी में 24 घंटे बिजली नहीं आती है और रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में कही भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो सदन का कोई सदस्य मुझे टोक सकता है। बजट में फिसकल डेफिसिट के बारे में बताया गया है कि यह 3.83 परसेंट हो गया है, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर फिसकल डेफिसिट 4 परसेंट के पार चला गया तो प्रदेश का दिवालिया निकल जायेगा अतः इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और फिसकल डेफिसिट पर कंट्रोल करने की पूरी जरूरत है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष प्रदेश की पर कैपिटा इंकम 2 लाख 47 हजार बताई गई थी जोकि इस बार घटकर 2 लाख 39 हजार हो गई है, तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आखिर पर कैपिटा इंकम बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही है? अगर हम पर कैपिटा इंकम 2 लाख 40 हजार मानकर भी चलें तो भी मुश्किल से यह महीने के 18–19 हजार रूपये ही बनते हैं तो इतने कम पैसे में तो चार लोगों के परिवार तक का गुजारा नहीं होता। इसकी तरफ सरकार को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। बजट में टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गई है, के परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि हमारे रेवाड़ी के अंदर महीने में मात्र 7 दिन नहरी पानी आता है जबकि अखबार की हैडलाइन्ज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि रेवाडी के अंदर पानी की सप्लाई अल्टरनेट डेज के हिसाब से की जाती है, मेरा निवेदन है कि इस तरह की नाइंसाफी मेरे क्षेत्र के साथ न की जाये। इसके अलावा बजट में और भी बहुत सारी बातें कही गई है। पिछली बार कहा गया था कि मनेठी के अंदर एम्स बनाया जायेगा लेकिन अबकी बार बजट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहां मैडिकल कालेज बनना था उसके बारे में कुछ मैंशन नहीं है, हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई मेंशन नही है, सैनिक स्कूल का जो काम है वह भी आज तक अधूरा ही पड़ा है जबकि इस काम को शुरू हुए 7 साल का लंबा समय बीत चुका है। यहां के खिड़की दरवाजे तक भी चोरी हो गए हैं। बिल्डिंग तो पूरी बनी भी नहीं और खिड़की दरवाजे चोरी हो गए तो बताओ ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? मनेठी मे एम्स स्थापित करने के लिए सरकार ने एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। ईंट तो दूर की बात रही है

जमीन तक अधिग्रहित नहीं हुई है। आखिर हमें कब तक लोलीपॉप व झुनझुना देकर बहकाने की कोशिश की जायेगी। हर बार दक्षिण हरियाणा में विकास के नाम पर वोट ले जाकर सरकार बनाने का काम करते हैं लेकिन वहां के लिए करते कुछ नहीं है। अब मैं हमारे यहां के सिविल हस्पताल के बारे में बताना चाहूंगा। कोरोना काल में मैंने यहां का औचक निरीक्षण किया था तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां पर वेंटीलेटर तक की सुविधा नहीं थी इसके अतिरिक्त दैनिक जरूरत की मैडिकल से संबंधित मशीनें यहां पर उपलब्ध नहीं हैं और जहा तक डॉक्टर्ज की बात है, डॉक्टर्ज की खराब कंडीशंज के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ अब बार–बार बताने से क्या फायदा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के लिए एक प्रश्न लगाया था लेकिन उस वक्त माननीय मंत्री श्री अनिल विज ने गलत जानकारी सदन के अंदर दी थी कि हमारे यहां वर्ष 2018 में जो नगर पालिका के चुनाव हुए उस वक्त यहां पर जनसंख्या 1 लाख 87 हजार थी इसलिए इसको नगर निगम नहीं बनाया जा सकता जबकि सच्चाई यह है कि हमारे यहां नगर पालिका के आखिरी चुनाव वर्ष 2013 में हुए थे और जहां तक जनसंख्या की बात है तो आज हमारे यहां 4 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई है, अतः इसको ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाये। जहां तक बिजली और पानी के जो रेट की बात है आज यह बेतहाशा ढंग से बढ़ते जा रहे है। आज न तो गैस पर सब्सिडी मिल रही है, न ही बिजली के रेट कम किए जा रहे है। यही नहीं जहां तक बुढ़ापा पैंशन की बात है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 रुपये प्रति महीना करने की बात कही थी लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया और इसको 2500 रुपये करके वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। सदन में उप–मुख्यमंत्री महोदय मौजूद नहीं है, इन्होंने तो बुढ़ापा पैंशन को 5100 रुपये तक करने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपनी स्पीच महँगाई के ऊपर एक शेर के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ–

> 'क्या कहूं किस तरह से जीता हूँ, गम को खाता हूँ और आँसूओं को पीता हूँ।'

अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के आम आदमी की यह हालत हो गई। प्रदेश के आम आदमी को महँगाई के कारण कितनी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, इस बात की चिंता सदन को करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण

मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द।

श्री सत्य प्रकाश (पटौदी) (अ.ज.) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मेरे से पहले श्री चिरंजीव राव बोल रहे थे और काफी लम्बी–चौड़ी बातें सदन को बता रहे थे। देश और प्रदेश में दशकों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, अगर वे दक्षिण हरियाणा के बारे में सोचते तो आज दक्षिण हरियाणा की स्थिति कुछ और ही होती। जिन नहरों में कभी पानी नहीं आता था आज उन नहरों में पानी देने का काम श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती थी लेकिन दक्षिण हरियाणा के लिये कोई भी काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बजट एक ऐसा बजट है जो समाज के निचले पायदान में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम करेगी। यह बात ठीक है कि हमारे देश में दो सेक्टर हैं, एक सेक्टर कंस्ट्रशन का है और दूसरा एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने किसान हैं उनसे तीन गुना दलित समाज के लोग खेतों में काम करते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत तथा परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को 6 हजार वार्षिक की वित्तीय सहायता देने को काम श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वे सुविधाएं भूमिहीन मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कानूनी सहायता योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी का खर्च पूरा करने हेतु पहले 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसे 22 हजार रुपये का प्रावधान किया है, इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार बधाई की पात्र है। श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने गुरू रवि दास जी की जयंती पर दलित समाज को अपने मकान की मरम्मत के लिये 50 हजार रुपये से बढ़ा कर 80 हजार रुपये करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू भी हो

जायेगी। इसी प्रकार से डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। इस बारे में मेरा अनुरोध यह है कि वैसे तो हरियाणा प्रदेश में कन्याओं की शिक्षा फ्री है। कन्यादान राशि को शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाये, अभी कन्यादान राशि 51 हजार रुपय मिलती है लेकिन यदि हमारी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो यह राशि डब्ल यानी एक लाख रुपये कर दे। सरकार की ऐसी पॉलिसी बनने से हमारी बेटियां शिक्षा के लिये और ज्यादा जागृत होंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मानेसार में एक बहुत बड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान दिया है। यह संस्थान एन.आई.टी. और आई.आई.टी. के बराबर का हो, इसमें जो भी कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाये।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ) तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारंभ)

श्री सत्य प्रकाश जरावता (पटौदी) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मानेसर के पास एक नई ग्लोबल सिटी देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं । इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे दक्षिण हरियाणा में एक और नगर निगम देने का काम किया है जबकि पहले हमारे फरीदाबाद, मानेसर और गुरूग्राम आदि शहरों को सिर्फ लूट का अड्डा समझा जाता था । हमारे प्रदेश में 'सैल्फ हैल्प ग्रुप्स' बने हुए हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1200 'सैल्फ हैल्प ग्रुप्स' हैं । इनसे लगभग 15,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रदेश में 'महिला हुनर हब' भी बनाया जाए । जो महिलाएं हथकरघा के प्रॉडक्ट तैयार करने में सक्षम हैं उनके प्रॉडक्ट्स की एग्जिबिशन और सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार केन्द्र बनाया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में निर्णय लिया था कि हरियाणा में 85वां संशोधन किया जाए। इसके तहत एस.सी. कैटेगरी के क्लास–3 के सरकारी कर्मचारियों को

आरक्षण में पदोन्नति दी जाएगी । इसके लिए हरियाणा सरकार ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था और इस पर कहीं कोई स्टे भी नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार सरकार की इस संशोधन को लागू करने की मंशा भी है लेकिन कहीं पर कोई व्यक्ति किसी मामले में कोर्ट में चला जाता है और मामला लिटिगेशन की वजह से रोक दिया जाता है । अतः मेरा पुनः निवेदन है कि 85वां संविधान संशोधन लागू किया जाए, रोस्टर को दुरुस्त किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप बैठ जाइये ।

श्री सत्य प्रकाश जरावता : अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी बैठे नहीं हैं । मेरा कहना है कि मानेसर में एच.एस.आई.आई.डी.सी. की लगभग 150 एकड़ जमीन खाली पड़ी है । मेरा निवेदन है कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पॉर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाया जाए और मेरे क्षेत्र पटौदी में एक स्पॉर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः बजट का समर्थन करता हूं । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दिया है । आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि सरकार साथ को और जनता विकास को ढूंढ रही है लेकिन ये दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं । इस वर्ष 63 पेजों का बजट भाषण पढ़ा गया है और पिछले वर्ष 68 पेजों का बजट भाषण पढ़ा गया था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो विकास कार्य गिनाए गए थे उनका क्या हुआ ? पिछले बजट में 50 क्रैच बनने थे, वे इस बार भी बनने हैं । इसी तरह 77 मैगावॉट और 16 मैगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगने थे, वे इस बार भी लगने हैं, एम.आर. आई., सी.टी. स्कैन, कैथ लैब्स, कीमोथैरेपी जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं जिला अस्पतालों में पिछले बजट में भी देनी थी और इस बजट में भी देनी हैं । इस तरह की और भी बहुत–सी चीजें हैं जो पिछले बजट भाषण में करने की घोषणा हुई थी और इस बजट भाषण में पुनः करने के लिए कहा गया है । ऐसे में मेरा कहना है कि क्यों न एक श्वेत–पत्र जारी किया जाए कि आज विकास कार्यों की क्या स्थिति है । इस तरह से तो 'आगे दौड़ और पीछे छोड़' वाली कहावत चरितार्थ होती है और इस तरह से प्रदेश की जनता के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं । मेरा प्रश्न है कि जिन कार्यों को करने के लिए इस बजट भाषण में कहा गया है उसके लिए प्रदेश के

पास बजट ही कितना है ? सदन में बहुत–सी बातें हुई हैं कि इस बार पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक बजट है आदि । मैं पूछना चाहता हूं कि कैपिटल आउट ले कितना है ? प्रस्तुत 1,55,645 करोड़ रूपये के बजट में से 9,318 करोड़ रूपये कैपिटल आउट ले है जोकि केवल 5.9 प्रतिशत है । अगर सरकार 100 रुपये खर्च करेगी तो उसमें से मात्र 5.9 रुपये, जो विकास कार्य 63 पेजों में गिनवाये गये हैं, उन पर खर्च किये जाएंगे। क्या उम्मीद करें कि कितनी तरक्की होगी ? इस चीज के लिए एप बनाये गये हैं, उस चीज के लिए एप बनाये गये हैं और पता नहीं किन–किन चीजों के लिए एप बनाये गये हैं। सरकार ने इतने ज्यादा एप बना दिए कि आज उनको ढूंढने के लिए एप की जरूरत पड़ रही है। सरकार द्वारा एप के ऊपर एप बनाये गये हैं। एक हर पथ एप बनायी गयी जिसमें सरकार ने कहा कि अगर कहीं पर 95 घंटे किसी गड्ढे को बने हुए हो गये और उसकी जानकारी एप के माध्यम से मिली तो उसको 96 वें वे घंटे में भर दिया जाएगा। 96 घंटे तो दूर की बात रही, परन्तु 96 दिनों के बाद प्रदेश की जनता ने उस एप को भर दिया कि कोई गड्ढ़ा नहीं भरा गया। जितनी भी हमारी मार्किट कमेटीज की सड़के हैं, उनका बुरा हाल है। खासतौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले जो बहुत सी सड़कें मार्किट कमेटीज के अंडर थी, उनको पी.डब्ल्यू.डी. बी.एंड आर. के अंडर कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रदेश की हर सड़क को पी. डब्ल्यू.डी. बी.एंड आर. के अंडर कर दिया जाए। उनकी जल्दी से जल्दी मरम्मत का कार्य किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कट लगाकर उसको सैस में तबदील कर दिया है। इसका मतलब हरियाणावासियों की जेब में से पैसा तो निकलेगा, लेकिन वह हरियाणा के विकास में नहीं लगेगा। यह कितने दुःख की बात है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास सैंट्रल टैक्स में से 7225 करोड़ रुपये का हिस्सा आएगा। क्या हमने इस बात पर संज्ञान लिया है कि इसकी वजह से हमारा कितना पैसा घट जाएगा ? जी.एस.टी. कम्पन्शेसन ग्रान्ट 9200 करोड़ रुपये अगले साल से बन्द हो जाएगी। इसका क्या प्रावधान होगा ? अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 524 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। क्या उम्मीद की जाए कि ये पैसे खर्च होगें? मैंने पिछले 5 सालों की जानकारी आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी थी जिसके अनुसार एक साल भी ऐसा नहीं है कि जब पूरा पैसा खर्च हुआ हो। क्या इस साल उम्मीद की जाए कि पूरा पैसा खर्च हो जाएगा ? आर.टी.आई. में यह बताया गया है कि उद्योग

नीति, 2015 में 32,030 नौकरियां और 24,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है। (घंटी)

श्री अध्यक्षः वरुण जी, आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय पूरा हो गया है।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य ने बजट पर चर्चा नहीं की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्य को बोलने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सफलता है या असफलता है ? ये 32,030 नौकरियां तब मिली हैं जब सरकार का लक्ष्य 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का था। इसके अतिरिक्त 24,000 करोड़ रुपये का निवेश तब आया है जब लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का था । यह सफलता नहीं बल्कि असफलता है।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बहुत सी नीतियों के बारे में बात की गयी है। यह बताया गया कि सरकार ने कृषि नीति, ई–वाहन नीति, टैक्सटाईल नीति और खुदरा नीति बनायी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जब भी नीतियां बनती हैं तो विधान पालिका को भी उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। माननीय सदस्यों को ड्राफ्ट पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिएं, जिससे बेहतर पॉलिसीज बन सकें। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर माननीय सदस्यों से भी जानकारी ले ली जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आखिर में कहना चाहूंगा कि–

उम्मीद पर दुनिया कायम थी,
कम्बख्त ऐसा बजट आया कि
वो उम्मीद भी जाती रही।

स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिन्द। जय जवान, जय किसान।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत सिटी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया है मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया और इस वैश्विक संकट के दौरान ऐसा बजट तैयार करना, मैं समझता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कितना मुश्किल काम था लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी

ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा बजट तैयार किया। यह बजट सबका साथ–सबका विकास पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट का निर्माण करते हुए 4 स्तम्भों का ध्यान रखा गया है। मैंने इस बात को देखा है कि किसी भी माननीय सदस्य ने अभी तक इस सदन में इन 4 स्तम्भों के बारे में जिक्र नहीं किया है। इस बजट के 4 स्तम्भ है और ये चारों स्तम्भ प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं। सरकार ने एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेम वर्क रिजर्व फंड बनाया है। इसके अलावा result oriented growth है और focus on implementation है जो 8555 करोड़ रुपये की उधारी क्षमता का उपयोग न करके इस वर्ष के साथ हैल्थ एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर की विशेष योजनाएं जैसे प्रदेश के हर जिले में 200 बैड का अस्पताल खोलने की बात हो, चाहे मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का निर्माण करने की बात हो, इसके अलावा वैलनैस सैंटर, बायो लैब्स और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए गन्नौर में इन्टरनैशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, पिंजौर में एप्पल मार्किट और सोनीपत में सपाइसिज मार्किट का निर्माण करने की बात हो। इस प्रकार से इस बजट के माध्यम से खेती के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर का निर्माण करके इसका लाभ व्यापारियों और उद्योगपतियों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है जिससे इनको बहुत ही सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने High speed rail connectivity between Delhi, Panipat and Karnal का भी निर्माण किया जायेगा। मैं ज्यादा न कहते एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से प्रदेश में विकास की झड़ी लगेगी। इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों का, सभी उद्योगों का और सभी किसान भाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड–19 के दौरान एम.एस.एम.ई को 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया गया था, जिसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए बढ़ावा दिया है क्योंकि उद्योग एक बड़ा रोजगार देते हैं। जैसे खेती–बाड़ी रोजगार देती है, उसी प्रकार से उद्योग भी एक बड़ा रोजगार देते हैं। हमारे देश के उद्योगों में हमारे करोड़ों मजदूर भाई मजदूरी करते हैं। उद्योगों को एम.एस.एम.ई. के माध्यम से 2.4 परसैंट का लोन दिया गया था और सरकार ने इसमें एक और प्रावधान किया कि पहले जिस उद्योग की जितनी भी लिमिट होती थी, एक पर्टिकुलर डेट पर बिना

को–लैट्रल सिक्योरिटी के और बिना किसी गारंटी के उस उद्योग को 20 परसैंट तक लोन देने का काम किया गया। मान लो किसी उद्योगपति की लिमिट 50 करोड़ रुपये थी तो अगले दिन उसके साइन करने से 60 करोड़ रुपये की लिमिट हो गई थी। इसका फायदा यह हुआ है कि जो फैक्टरियों में मजदूर काम करते थे, कोविड–19 के दौरान फैक्टरी मालिक के पास सैलरी देने के पैसे कम थे क्योंकि फैक्टरी में जो मजदूर काम करते थे उनमें से कोई छोड़कर चला न जाये। इस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने इम्प्लॉयमैंट को भी मैंटेन रखने का भी काम किया और उन मजदूरों को पूरी सैलरी भी दी गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से एम.एस. एम.ई. को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने पानीपत क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। आज के दिन पानीपत बहुत ग्रोइंग सिटी है, इस सिटी का कैसे ध्यान रखा जाये? आपने भी कई बार देखा या सुना होगा कि आदमी अपने वजन से ही खत्म हो जाता है। ऐसा न हो कि जो आज पानीपत ग्रो कर रहा है वह आने वाले समय में ट्रैफिक जाम से या इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वहां के उद्योग धंधे पलायन करने को मजबूर हो जायें। इससे पहले ही प्रिकॉशनरी स्टैप्स लिए जाने चाहिए। मेरा कहना यही है कि वहां पर ऐसी मुसीबत न आ जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे लिए वहां पर अल्ट्रा मॉर्डन फायर स्टेशन बनाना बहुत ही जरूरी है और इसके अलावा वहां पर 5 रेलवे अंडर बाइपास बनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पानीपत के सलोनी रोड को नैशनल हाइवे से पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) विभाग को ट्रांसफर करके उसको भी फोर लेनिंग बनाया जाये। वहां पर ओल्ड इन्डस्ट्रियल एरिया से लेकर जी.टी. रोड तक एक आर.ओ.बी. कनेक्शन की बहुत जरूरत है। इसी तरह से असंध रोड को जो एल.एन. टी. का फ्लाई ओवर है, जिससे आप हर रोज निकलते है। उसको इसके साथ जोड़ दिया जाये। इसके अलावा सलोनी रोड को एल.एन.टी. के फ्लाई ओवर से कनेक्ट कर दिया जाये, जिसके कारण ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्याएं खत्म हो जायेंगी। इसी तरह से पानीपत में नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। वह शहर से लगभग 4–5 किलोमीटर दूर है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि शहर के अंदर इसी एल.एन. टी. फ्लाई ओवर के साथ एक कनैक्टिड ऐलिवेटिड बस स्टॉप बना दिया जाये। जिससे शहर के लाखों लोगों को बहुत दूर से नहीं आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी रिक्वैस्ट है कि पानीपत का जो पुराना शहर है उसके अंदर पानी की

पाइप लाइन 60 साल पुरानी डली हुई है और यह पाइप लाइन गल चुकी है। इनमें बहुत काम होने वाला है। हम इसकी डी.पी.आर. बनाकर दे चुके हैं और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें पानी की पाइप लाइन और सीवर लाइन सिस्टम का दोबारा से काम करवाया जाये। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से अपनी एक डिमाण्ड एक बार फिर से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। मैं इस सम्बन्ध में पिछले सैशन के दौरान भी सरकार से रिक्वैस्ट कर चुका हूं कि हमें हमारे पानीपत शहर के लिए जैड.एल.डी. (Zero Liquid Discharge) की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानीपत के अंदर अंडर ग्राउंड वॉटर का लैवल बहुत ज्यादा तेजी के नीचे जा रहा है अगर यही हाल रहा तो पानीपत के अंदर जमीन का पानी बहुत जल्दी ही खत्म हो जायेगा। जीवन के लिए और हमारी पानीपत की टैक्सटाईल इण्डस्ट्री के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रौजैक्ट की मैंने बात की है वह 1600 करोड़ रूपये का प्रौजैक्ट है। अगर हमें पानीपत की तमाम इण्डस्ट्री को बचाना है तो इस प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि पानीपत की डिवैल्पमैंट के लिए 500 करोड़ रुपये के एक स्पैशल फण्ड की तुरन्त अलॉटमैंट की जाये। अगर सरकार के स्तर पर ऐसा किया जाता है तो इससे पानीपत की तमाम इण्डस्ट्री बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगी। इसी प्रकार से जैड.एल.डी. (Zero Liquid Discharge) के प्रौजैक्ट के लिए भी 1600 करोड़ रूपये की राशि की तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल दी जाये। स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सदन में यह इंफर्मेशन देना चाहता हूं कि पानीपत ने इस साल तकरीबन सैंकड़ों करोड़ रुपये का इंकम टैक्स दिया है। इसका डाटा मैं सरकार को अलग से भिजवा दूंगा। इसी प्रकार से पानीपत ने बीते वर्ष के दौरान जी.एस.टी. और वैट में तकरीबन 4800 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह वायदा करता हूं कि सरकार मेरे पानीपत शहर में इण्डस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टालेशन में हमारी मद्द कर दे, सरकार इस मद में जितना भी खर्च करेगी मेरे पानीपत के समस्त इण्डस्ट्रियलिस्ट्स वर्ष 2024 तक सरकार को उसका ऑलमोस्ट डबल करके रिटर्न कर देंगे। मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि यह वायदा मैं अपने

समस्त इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ से अपनी सरकार को करता हूं। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती शकुंतला खटक (कलानौर) (एस.सी.) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया सर्वप्रथम तो इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। स्पीकर सर, जब मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने 63 पेज की बजट बुक अढाई घंटे में पढ़ी। मैंने यह सोचा कि इस बार के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को बहुत कुछ मिलेगा लेकिन वास्तव में तो इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। न तो एस.सी. व बी.सी. वर्ग के लिए कुछ मिला, न किसान–मजदूर वर्ग के लिए कुछ मिला, न महिलाओं के लिए मिला, न नौजवानों के लिए मिला और न ही कर्मचारियों व व्यापारियों के लिए ही कुछ मिला। जितना इस बजट बुक में वजन है अगर इस बजट बुक के अंदर लिखे शब्दों और आंकड़ों में भी उतना वजन होता तो मैं समझती कि उससे कुछ न कुछ प्रदेश को मिलता लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। स्पीकर सर, सदन में कोरोना काल की बात की जा रही है सरकार ने इस बजट बुक में कोरोना काल की बातों को बढ़ा–चढ़ाकर बताकर अपनी ही प्रशंसा करने का काम किया है। मैं यह कहना चाहती कि वास्तव में कोरोना काल में प्रदेश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जन साधारण व प्रदेश की जनता ने काम किया है और सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। मैं तो उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद करती हूं, उन सभी डॉक्टर्ज का धन्यवाद करती हूं, उन सभी स्टॉफ नर्सिज का धन्यवाद करती हूं और उन सभी स्वीपर्स का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर कोरोना की रोकथाम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रदेश की सरकार ने फण्ड रिलीज करने का काम तो जरूर कर दिया लेकिन साथ में अधिकारियों को यह फोन भी कर दिया कि इस फण्ड को कहीं भी यूज नहीं करोगे। मैं यहां पर यह बात गारण्टी के साथ कह रही हूं। स्पीकर सर, अगर हमारे एस.सी. व बी.सी. भाईयों की बात की जाये तो इस बजट में उनके उत्थान के लिए और उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा किसी भी नई योजना का प्रावधान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं हमारे एस. सी. व बी.सी. भाईयों के चहुंमुखी विकास के लिए जो योजनायें हमारी पार्टी की चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने उन सभी योजनाओं को भी बंद करने का काम किया

है। स्पीकर सर, अगर महिलाओं की बात की जाये तो मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां पर महिलाओं के लिए रोया जाता है लेकिन इस बजट बुक में महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अगर प्रदेश के किसानों की बात की जाये तो भी निराशा ही हाथ लगती है। सरकार कहती है कि किसानों की आय को दुगुना किया जायेगा। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि फिलहाल जो हमारे किसान भाइयों की आय है उसी को बची रहने दो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसानों के प्रति वर्तमान हरियाणा सरकार के रवैये और कारगुजारियों के चलते प्रदेश के किसानों की आय कभी दुगुनी हो जायेगी। यह सरकार तो अपनी नीतियों के चलते जो वर्तमान समय में किसानों की आय है उसको भी छीनने पर लगी हुई है। स्पीकर सर, अगर यहां पर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था और सभी नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने की बात की जाये उसमें भी सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगता। मुख्यमंत्री जी का गांव मेरे हल्के में है या यह समझ लें कि मुख्यमंत्री के हल्के से मैं विधायक हूं। ये दोनों बातें ही सही हैं। खेतों में पानी देने के मामले में मेरे हल्के के किसानों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। वहां पर दो महीने में सिर्फ एक बार ही मात्र अढाई दिनों के लिए ही नहरों में पानी आता है। इतने कम समय नहरों में पानी आने पर किस प्रकार से टेल पर पानी पहुंच पायेगा? इस प्रकार के हालात में टेल पर पानी पहुंचने की तो बात ही नहीं है वहां पर तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर शिक्षा के बारे में बात की जाये तो जहां पर स्कूल की बिल्डिंग है वहां पर टीचर्ज नहीं हैं और जहां पर टीचर्ज हैं वहां पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हम कैसे और किस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे पायेंगे? मैं शिक्षा मंत्री जी से बार–बार कह चुकी हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव खरावड़ में लड़कियों का स्कूल, तथा लड़कियों के स्कूल कलानौर की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में हैं और पिछले 5 साल हो गये लेकिन नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ऑनलाईन शिक्षा देने की बात की जा रही है। आप गांवों में ऑनलाईन शिक्षा कैसे देंगे, क्योंकि गांवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है? जहां तक वृद्धावस्था पैंशन की बात है तो सरकार की तरफ से मेजें थपथपाई गई। जजपा के मेनीफैस्टो में यह बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार आई तो वृद्धावस्था पैंशन 5100 रुपये महीना कर देंगे लेकिन आज उप–मुख्यमंत्री सदन में बैठे नहीं हैं।

उस समय यह नहीं कहा गया था कि हम हर साल अढाई सौ रुपये बढ़ायेंगे, यह तो लोगों के साथ विश्वासघात है।

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, आपका समय समाप्त हो रहा है इसलिए आप वाइंडअप कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के बिना काम भी नहीं चलता और आंकड़े ऊपर नीचे भी होते रहते हैं लेकिन धरातल पर लोग आंकड़े नहीं देखते, उनको काम चाहिए, उनको विकास चाहिए इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार काम करे, विकास करे। मैं आपके माध्यम से अपने भाई डॉ. अभय सिंह यादव व सरकार को चार पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कृपया ध्यान से सुनिये–

बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा,
नदियों के कुछ नाम रखे हैं, बहती धाराओं का क्या होगा,
शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है,
मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा।
इन फिराग फरिश्तों से पूछो क्या सूरज नया उगायेंगे,
एक हवा से लेते सांस सभी क्या हवा भी नई चलायेंगे।
नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का दोषी है,
क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है।

ये जात–पात भेदभाव सारा छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगों के बारे में भी बताना चाहती हूं। मेरे हल्के के गांव गरनावठी मोड़ से बालंद तक का रोड बहुत जर्जर हालत में है उसको तुरन्त बनाया जाए क्योंकि वहां पर एक्सीडैंट्स बहुत होते हैं। नहरी पानी के मामले में मेरे हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है। दो महीने में अढाई दिन के लिए नहर चलती है इसलिए मुझे मेरा हक प्रदान करने का काम करें। कलानौर को सब–डिवीजन बनाने का काम किया जाये। इसी प्रकार से कलानौर में एक महिला कॉलेज भी खोलने का काम करें। मेरे हल्के के स्कूलों की जो बिल्डिंग टूटी हुई हैं उनको दोबारा से बनाया जाये। कलानौर में सीवरेज और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है उसमें सुधार किया जाये। मेरे हल्के के गांवों में पीने के पानी 6–6 दिन में आता है और शहर में 3 दिन में आता है इसलिए मेरे हल्के के हिस्से का पानी मुझे उपलब्ध करवाया जाये। अध्यक्ष

महोदय, हल्केवार सभी विधायकों को जो 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई थी, वह अभी तक नहीं पहुंची है, वह भी शीघ्र जारी करवाने का काम करें।

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, आप अपने हल्के की मांगें लिखित में दे दीजिए उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

***श्रीमती शकुन्तला खटकः** ठीक है, सर। मैं अपने हल्के की मांग लिखित में दे देती हूं कृप्या आप उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दें।

1. गांव सैंपल की ढाणी से लेकर रेलवे स्टेशन कलानौर तक रास्ते का निर्माण करवाया जाए।

2. हमारे कलानौर कस्बे में और रोहतक शहर में जितनी भी हमारी आउटर कालोनियां लगती हैं, उनमें सीवरेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। पीने का पानी भी बहुत गंदा आता है। कृप्या करके सिस्टम को सुधारने और साफ पानी दिलवाने का काम करें।

3. कलानौर हल्के के गांवों में पीने का पानी 6–7 दिनों में एक बार वो भी सिर्फ 20 मिनट आता है। कृपया करके हर रोज पीने का पानी एक निर्धारित समय तक देने का काम करें ।

4. कलानौर हल्के में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए के ऐस्टिमेट भेज रखे हैं। इस राशि को भी जल्द से जल्द जारी करने का काम करें ताकि हल्के में विकास कार्य करवाए जा सकें।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दो वक्ताओं ने बोलते हुए मेरा नाम लिया है। श्री जोगी राम जी ने इंडायरैक्टली मेरा नाम लिया है और बहन शकुंतला जी ने भी मेरा नाम लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा की जो टेप है उसकी जीरो ऑवर की रिकॉर्डिंग निकलवा लें और उस टेप को प्ले करके यहां बता दें और फिर let the house decide who is at fault ऐसे नहीं कि किसी को वैसे ही डैमेज करते रहे और हर आदमी बिना बात का प्रचार करता रहे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने जो बोला है कल उसका जीरो ऑवर के बाद टेप प्ले करके let them see कि मैंने क्या गलत बोला?

श्री सुधीर कुमार सिंगला (गुरूग्राम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का समय दिया, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय बजट पेश करने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी प्रदेशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में हमारा हरियाणा दिन–रात तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक बजट रहा है। जब कोरोना काल की वजह से काम धंधे बन्द पड़े थे। बावजूद इसके हमारी सरकार का बजट 1 लाख 40 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये हुआ है जिसका उपयोग हरियाणा प्रदेश के हर कोने व हर इलाके के विकास में होगा और हमारा हरियाणा विकास की नई ऊंचाईयों को छुएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के सिद्धांत पर काम करके सभी जाति व वर्ग के समान विकास की दिशा में सदैव काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से गुरूग्राम की ग्लोबल सिटी में एन.सी.आर. का सैंट्रल हाऊस बनाने की कोशिश की जा रही है। गुरूग्राम में फिल्म सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है। सरकार का सिनेमा जगत को प्रोत्साहित करने और राज्य भर में फिल्म बनाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है क्योंकि हरियाणा में मनोरम और ऐतिहासिक स्थल है इसलिए इसे फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है । गुरूग्राम में एक महिला आई.एफ.टी. बटालियन और हिसार में एक महिला पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। हरियाणा में एक अप्रैल से बुढ़ापा पैंशन में बढ़ौतरी होकर 2500 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। अदालतों में केस लड़ने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली राशि 11000 रुपये से बढ़ाकर 22000 रुपये कर दी गई है। शिक्षा के लिए 18410 रुपये का और खेलों के लिए 7731 रुपये का प्रावधान किया गया है। गुरूग्राम के अन्दर फूल मार्किट भी दी गई और खेड़कीदौला टॉल प्लाजा को भी कुछ ही दिनों के अन्दर वहां से सरका दिया जाएगा। जहां पर हरियाणा में आर्थिक विकास की गति राज्य की प्रति व्यक्ति आय और खरीद क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए वह हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय तुलनात्मक रूप से अधिक रही है। हरियाणा में वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2 लाख 47 हजार 668 रुपये हो गई है। अभी मैं गुरूग्राम की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा कि गुरूग्राम में जलाशय का पुनर्रुद्धार किया जाए। जैसे गुरूग्राम के अन्दर चार जलाशय हैं। एक शीतला माता मन्दिर के अन्दर

धीरगढ़ खेड़ी के पास, एक कॉलेज के पास और एक सिरोकरा गांव के पास जलाशय है। पहले तो काफी जलाशय थे परंतु अब ये कुछ ही जलाशय मौजूद हैं। बाकी जलाशय पानी के कारण और बढ़ती जनसंख्या व उच्च देखभाल न रखने के कारण या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। गुरूग्राम को पहले ही डार्कजोन घोषित किया जा चुका है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि पानी की संचयन, पानी की बचत और ग्राउंड वाटर लैवल सही करने के अधिक प्रयास किये जाएं। मैं सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इससे जो भूमिगत जल का लैवल कम हो गया है वह भी समय के साथ ठीक हो सकेगा और क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने में आसानी होगी। दूसरी समस्या बस स्टैंड पर जाम रहता है उससे मुक्ति दिलाई जाए। हमारे गुरूग्राम में जो बस स्टैंड है वह काफी पुराना बस स्टैंड है, और वहां काफी बड़ी बसें आती हैं इसलिए इस बस स्टैंड को वहां से हटा दिया जाए और इंटर सिटी बस स्टैंड शहर के अन्दर बना दिया जाए तथा इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड शहर से बाहर ले जाया जाए। ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वजीराबाद में एक शमशान घाट की बात चल रही है जोकि बहुत ही ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा है। वर्ष 2004 में भी उसके पास एक शमशान घाट बनाया जा रहा था लेकिन वह काम फिर रुक गया था। उसके बाद वर्ष 2014–15 में भी उसी काम को शुरू किया गया और फिर काम रुक गया। अबकी बार भी यह काम शुरू हुआ था लेकिन अब रुक गया है। अध्यक्ष महोदय, लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि इस गांव में शमशान घाट बनेगा तो यह गांव शमशान घाट के नाम से मशहूर हो जायेगा। वजीराबाद गांव हमारे यहां का सबसे बड़ा गांव है जिसके साथ 12 गांव लगते है। मेरी प्रार्थना है कि इस गांव में यह शमशान घाट न बनाया जाये और गांव से 1–2 किलोमीटर दूर किसी अन्य जगह पर शमशान घाट के लिए जमीन दे दी जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे गुड़गांव में दौलताबाद–कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ व्यापारिक संगठन मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके दौलताबाद–कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काफी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और यह एरिया हरियाणा प्रदेश के बनने से पहले ही डिवैल्प हुआ था परन्तु बावजूद इसको यहां पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अतः मेरा अनुरोध है

कि दौलताबाद–कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधायें देने का काम किया जाये।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मेरी भी कुछ डिमांड्ज हैं, अतः मुझे भी अपनी बात रखनी दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ डिमांड्ज रखनी हैं अतः मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः ठीक है आप दोनों अपनी डिमांड्ज लिखित में दे दें इनको प्रोसिडिंग्ज का हिस्सा बना लिया जायेगा।

***श्री कुलदीप वत्स (बादली):** अध्यक्ष महोदय, बादली विधान सभा के गांव बादली में पी.एच.सी., लघु सचिवालय, बस अड्डा, स्कूल बनाने के कार्यों को जल्द से जल्द किया जाये, गांव पेलप व सोंधी के लिए बाई–पास का निर्माण कार्य किया जाये, गांव पाटोदा में मॉडल स्कूल एवं रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाये, तोई–दादरी से झज्जर तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जाये, जटवाड़ा, बाबेपुर, गिरधपुर, सुबाना, सरोला, खुड़न, समसपुर माजरा, कासनी, सुरहेती, सिलाना, सिलानी, बूपनिया शाहपुर, दसलपुर आदि गांवों में वर्षा के कारण होने वाले जलभराव की समस्या को दूर किया जाये। गांवद बादली एवं माछरौली में पुलिस थाना बनवाया जाये, कुलाना गांव में अंडर पास का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये, गांव माछरौली को उप–मंडल बनाया जाये, सुबाना गांव का बाई पास बनाया जाये, गांव किलडोद और गिजाडोद में करीबन 100–150 एकड़ पंचायत की भूमि पर कॉलेज या युनिवर्सिटी बनाई जाये, गांव लौहारी, पाटोदा, अम्दालपुर, असदपुर खेड़ा, कुलाना, कोका, बामडोला, चांदपुर, लाडपुर, पेलपा, वाजीदपुर, बापूनिया तथा देसलपुर आदि गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाये।

***श्री लीला राम (कैथल):** अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव उजाना में वीटा का मिल्क प्लांट का निर्माण करवाया जाये। गांव ने कैथल–अम्बाला रोड पर 6 एकड़ जमीन वीटा प्लांट के लिए दे रखी है, कैथल शहर में ग्योंग ड्रेन को पक्का किया जाये, गांव क्योड़क को सब तहसील बनाया जाये, कैथल शहर में नई सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाये जबकि नई अनाज मंडी के पास यह जमीन उपलब्ध

*** चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

है, खनौरी रोड से पटियाला रोड तक व खुराना रोड व मानस ड्रेन की पटरी पर सड़क का निर्माण करवाया जाये, कैथल शहर में लड़कियों के लिए सरकारी कालेज बनाया जाये, कैथल शहर में कार पार्किंग का निर्माण करवाया जाये और यहां पर जमीन भी अवेलेबल है, मंजूरशुदा मैडिकल कालेज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाये, यहां पर 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सिटी बैंक स्क्वेयर के अधूरे पड़े कार्य को पूरा किया जाये, गांव उजाना से गांव कुलतारण तक मार्किटिंग बोर्ड की सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाये, गांव मानस से गांव अटैला तक की सड़क का निर्माण कार्य पी.ड़ब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर) विभाग से करवाया जाये, गांव शेरगढ के पोलटैक्निक कालेज में बी.टैक कालेज बनाया जाये जबकि यहां पर बिल्डिंग भी उपलब्ध है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2021–22 के लिए 12 तारीख को बजट भाषण पढ़ा था जोकि अपेक्षा से लंबा भाषण था। इस बजट में हमने कुछ नए प्रावधानों को शामिल करते हुए कुछ नई चीजों को भी जोड़ने का काम किया। जब नए विषय शुरू किए जाते हैं तो उन पर विचार किया जाता है और अनुभव के आधार पर अच्छी चीजों को स्थाई तौर पर रख लिया जाता है और जो ठीक नहीं होती हैं उनमें इस आधार पर अदला–बदली कर दी जाती है कि इनसे भविष्य में कितना लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। अपेक्षा के अनुसार अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमने भी बजट के माध्यम से इस प्रकार का एक प्रयास किया है। पैसा कहां से आयेगा और कहां जायेगा, उसका क्या नियोजन होगा, किस चीज को प्राथमिकता दी जायेगी, किस चीज के लिए कम या ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जायेगा तथा किन विशेष क्षेत्रों में फोकस रखा जायेगा, इन सबका लेखा जोखा बजट में रखा जाता है। बजट बनाते समय हमने इन सब बातों के साथ–साथ **'तेरा तुझको अर्पण–क्या लागे मेरा'** की भावना के साथ काम करते हुए इस बजट को बनाने का काम किया है। हमने जो बजट पेश किया है यह किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि इसको पूरे प्रदेश के हित के लिए बनाया गया है। मेरा विचार है कि बजट बनाते समय संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी होता है अर्थात जिस वर्ग को ज्यादा आवश्यकता होती है, जो वास्तव में किसी लाभ लेने को

डिजर्व करता है, मैं मानता हूँ कि उसका ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि haves or haves not में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जिन पर प्रभु कृपा होती है, जो साधन संपन्न होते हैं और कुछ देने की क्षमता रखते हैं, उनसे लिया जाये और जिनकी स्थिति ऐसी है जोकि किसी कारण से पीछे रह गए हैं, उनके लिए काम करना मैं समझता हूँ कि इतनी बढ़िया सोच के आधार पर ही कोई बजट तैयार किया जाना चाहिए और हमने यह प्रयास किया भी है। बजट के माध्यम से सबको बराबर मिलेगा ऐसा भी संभव नहीं होता है, परन्तु बजट में हर क्षेत्र–वर्ग का ध्यान जरूर रखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए तथा बिना किसी अनुराग व द्वेष के यह बजट तैयार किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर काम होने चाहिए, चाहे वह क्षेत्र किसी भी पार्टी के विधायक का ही क्यों न हो, वहां पर किसी भी वर्ग के लोग क्यों न रहते हों, चाहे वह शहर है या गांव है इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यह बजट तैयार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि–

'कबीरा खड़ा बाजार में, माँगे सबकी खैर,
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।'

इस बार का बजट बनाने में कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण जो कठिनाइयां आई हैं वह हम सबको पता है। पिछला संशोधित बजट जो था उस समय हमें यह नहीं पता था कि इस प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी। इस अवधि के दौरान अप्रैल, 2020 से लेकर सितम्बर, 2020 तक जो राजस्व वसूली अपेक्षानुसार होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा कम हुई। आज मैं विपक्ष के सभी नेताओं का बहुत आभारी हूँ। इसमें चाहे एक विपक्ष के प्रमुख नेता जो इस समय किसी भी कारण से सदन के सदस्य न हों उन्होंने और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी सभी साथ मिलकर वी.सी. के माध्यम से मीटिंग करते थे। उस मीटिंग में एक–एक प्वॉयंट पर बारीकी से चर्चा करते थे और उसमें से परामर्श देते थे कि इस प्वायंट को हमें आगे बढ़ाना जरूरी है। कोविड–19 के कारण प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है तो इसके लिये अगर हमें लोन भी लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। हमारा मानना था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। हम चाहते थे कि किसी की भी पैंशन, सैलरी आदि न रुके। अध्यक्ष महोदय, री–पेमैंट ऑफ लोन वह तो स्वतः होता ही है और इन्ट्रस्ट अपने आप कटता है। ऐसे में जो वस्तुओं का खर्च है, वह तो हमें करना ही

है। कोविड–19 में बहुत से प्रदेशों ने सैलरी पर 30 प्रतिशत का कट लगाया किसी ने कुछ और किया लेकिन हमारे प्रदेश में यह बात सही है कि कर्मचारियों की सैलरी 15–20 दिन लेट जरूर हुई थी, वह भी 1–2 महीने के लिये लेकिन 3–4 महीने के बाद फिर वही लाइन पर आ गई थी अर्थात् मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने किसी भी प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में कोई कट नहीं लगाया। प्रदेश में कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से लगभग 275 करोड़ रुपये जमा हुये थे। इस फंड में कर्मचारियों, पैंशनर्ज, व्यापारियों आदि ने खुले तौर पर अपनी–अपनी भागीदारी दी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि ग्रुप–डी के कर्मचारी ने अपनी एक महीने की पूरी सैलरी कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाई थी। अध्यक्ष महोदय, 50 कर्मचारी ऐसे निकले थे, जिन्होंने अपने पूरे महीने की सैलरी कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाई थी। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा योगदान इसमें रहा था, छोटी–मोटी आलोचना जरूर होती रही लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। कोरोना के पीरियड में एक बार तो 15 हजार करोड़ रुपये की राजस्व की कमी हो गई थी। लेकिन अभी तक सारा का सारा हिसाब–किताब लगाने के बाद लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का एस्टीमेटेड बजट कम रहेगा। हमें सही रूप से 31 मार्च तक पता चल जायेगा लेकिन हमारा मानना है कि यह 5 हजार करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट में प्रमुख विषय कई हैं लेकिन सिंचाई और कृषि इन विषयों के ऊपर सरकार ने फोकस किया हुआ है। कई माननीय सदस्य बजट का आंकलन पिछले साल के बजट एस्टीमेट से उठाते हैं और आज के बजट एस्टीमेट से जोड़ते हैं। मेरा कहना है कि बजट के समय क्योंकि हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट रीसैंटली बना हुआ था और बजट एस्टीमेट कुछ और होता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट कभी बढ़ता है और कभी घटता है। स्वाभाविक है कि इस बार घटा भी है क्योंकि हमारी आमदन कम हुई है तो वैसे ही हमारे खर्चे भी कम हुए हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट पिछले महीने के लेटेस्ट बने हुए हैं तो एक्च्युअल के नजदीक रहेंगे, इसलिए अगले बजट एस्टीमेट की इससे तुलना करेंगे। जहां कहीं भी आंकड़ों का अंतर इसी कारण से आ रहा है, क्योंकि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बजट एस्टीमेट से तुलना इस बजट से की है। मैं तुलना रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट से करूँगा क्योंकि रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट और बजट एस्टीमेट में अंतर बहुत ज्यादा आता है और रिवाइज्ड बजट एक्च्युअल बजट के बहुत ही नजदीक होता है। इस प्रकार से कृषि का

रिवाइज्ड बजट 5022 करोड़ रुपये का था और अभी जो वर्ष 2021–22 का बजट एस्टीमेट दिया है वह 6111 करोड़ रुपये का दिया है। इस नाते से यह बढ़ोतरी 20. 9 प्रतिशत है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि के लिए बजट एलोकेशन की बात है तो पिछले वित्त वर्ष में बजट का कुल 4 प्रतिशत एलोकेशन कृषि के लिए किया गया था लेकिन इस बजट में कृषि के लिए केवल 3 प्रतिशत एलोकेशन किया गया है । इस प्रकार से सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए कृषि का बजट घटाया है और सरकार को इस बात को मानने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय का उल्लेख बाद में करूंगा । मैं फिलहाल इरीगेशन के विषय में बात करना चाहता हूं । इरीगेशन के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट 2,892 करोड़ रुपये था और नया बजट 5,081 करोड़ रूपये है । इस प्रकार से इसमें 75 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की गई है । मैं बजट में इरीगेशन के लिए बढ़ौत्तरी का उल्लेख करना चाहूंगा । इस वर्ष 'वेस्टर्न यमुना कैनाल' का हथनीकुंड–भालौड ब्रांच तक रेनोवेशन होना है । इसके अलावा हम प्रदेश में माइक्रो इरीगेशन का प्रौजैक्ट भी शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हमने इंट्रस्टिड लोगों से ऐप्लीकेशन भी मांगी हैं । इन दोनों कार्यों में सरकार का काफी पैसा लगना है जिस वजह से इस बार इरीगेशन के लिए बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है । इरीगेशन में भी अल्टीमेटली किसानों के भले के लिए ही ज्यादा राशि एलोकेट की गई है । हमारे लिए हर विभाग का अपना महत्व है लेकिन इस बजट में हमने किसान का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है, इसलिए मैं इस बजट को किसान को समर्पित करता हूं । इस तरह से अब मैं किसान कल्याण बजट का उल्लेख करता हूं । अब मैं सदन में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा । आंकड़ों का अपना महत्व होता है और आंकड़ों से ही कई चीजें ध्यान में आती हैं । हमारे पास कुछ स्थूल आंकड़े या कह लीजिए कि माइक्रो पैरामीटर्स हैं । इस वर्ष कोविड–19 के कारण पहली बार हमारे बजट में कंट्रैक्शन हुआ है । इसका अर्थ है कि इस बार हमारी ग्रॉथ नैगेटिव में हुई है । किसी भी वर्ष हमारी जी.एस.डी.पी. (*Gross State Domestic Product*) नैगेटिव में नहीं गई थी लेकिन इस बार वह भी नैगेटिव में रही है और उसका कारण भी कोविड–19 ही है । हालांकि हमने इसको भी कंट्रोल किया है । ऑल इण्डिया लैवल पर यह कंट्रैक्शन 8 परसैंट है और हमारे स्टेट का कंट्रैक्शन 5.65 परसैंट है । हमारे पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान का कंट्रैक्शन

क्रमशः 6.41 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत है । इन दोनों ही प्रदेशों से तुलना करने पर हमारा कंट्रैक्शन कम है और हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं । इसी तरह से दिल्ली की अगर बात की जाए तो उनका हम पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनके बजट की नेचर अलग है, हमारे बजट की नेचर अलग है । हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली का कंट्रैक्शन 5.7 प्रतिशत है । इस तरह से ऑल इण्डिया लैवल पर और अपने पड़ोसी प्रदेशों से तुलना करने पर हमारा कंट्रैक्शन कम है और हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं । हमने कोशिश की कि हमारा कंट्रैक्शन ज्यादा न बढ़े । वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 की हमारी बोरोइंग्स की अगर हम वर्ष 2020–21 से विदआउट 'उदय' तुलना करें तो यह 20.25 परसैंट है और विद उदय 23.27 परसैंट है । 'उदय' के कारण से ही इन 2 सालों में हमारा डैट ज्यादा बढ़ा है, इसलिए हमें इन दोनों सालों के आंकड़ों का साथ–साथ मिलान करना पड़ता है । यह फैक्ट है कि डैट विदआउट 'उदय' कम होता है और विद 'उदय' ज्यादा होता है । अगर इसकी हम पंजाब से तुलना करें तो पंजाब का डैट विदआउट 'उदय' 41.69 परसैंट है और हमारा 20.25 परसैंट है । इसी तरह से अगर इसकी हम राजस्थान से तुलना करें तो राजस्थान का डैट विदआउट 'उदय' 42.7 परसैंट है । इस तरह से अन्य प्रदेशों की तुलना में हम पर डैट बहुत कम है । इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमने अपने आपको बहुत ही संयम से आगे बढ़ाया है । वर्ष 2021–22 का जो प्रोजैक्शन है उसमें हमारा रिवैन्यू डैफिसिट 1.67 परसैंट है और हमारी कोशिश है कि यह 1 परसैंट से नीचे आ जाए । ऐसा माना जाता है कि अगर किसी प्रदेश का रिवैन्यू डैफिसिट 1 परसैंट से नीचे हो तो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होती है । फिलहाल हम इससे थोड़ा अपर साइड की तरफ हैं । हमारा रिवैन्यू डैफिसिट 1.67 परसैंट है और पंजाब का रिवैन्यू डैफिसिट 3.42 परसैंट है। यह जो वर्तमान साल चल रहा है। इसमें राजस्थान का रैवेन्यू डैफिसिट 4.36 प्रतिशत है। हमारा वर्ष 2021–22 में प्रोजैक्टिड रैवेन्यू डैफिसिट 2.39 प्रतिशत है। चूंकि पिछले वर्ष में चाहे रैवेन्यू प्राप्तियां हों या एक्सपैंडीचर हो, उसमें काफी अन्तर रहा है। इसलिए यह थोड़ा सा बढ़ रहा है, परन्तु हम कोशिश करेंगे कि यह 1 प्रतिशत से नीचे आए। इसी प्रकार फिस्कल डैफिसिट जो पिछले साल का चल रहा है, उसका 2.9 प्रतिशत है। पंजाब का फिस्कल डैफिसिट 4.69 प्रतिशत है और राजस्थान का फिस्कल डैफिसिट 6.12 प्रतिशत है। हमारा अगले साल का प्रोजैक्शन फिस्कल डैफिसिट के नाते से 3.8 प्रतिशत रहेगा। फिस्कल डैफिसिट भी

कम रहना चाहिए, लेकिन यह पिछले वर्ष के आधार पर अगले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। हम इस कमी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। रिकवरी के मामले में केन्द्र सरकार ने भी आहवान किया है कि हमारी रिकवरी फिर से ठीक होनी चाहिए। इसमें जो यह डिप आया है, हमारा उसको वी शेप रिकवरी के नाते से उपर बढ़ाने के लिए एक प्रयत्न रहेगा। हम इसमें वी शेप रिकवरी के नाते से विचार करेंगे। हमारा फिस्कल डैफिसिट 3 प्रतिशत से कम है। भारत सरकार ने इसकी सीमा बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक कर दी है। इसमें 5 प्रतिशत की सुविधा कुछ कंडीशंज के साथ दी गयी है। इसमें 4 प्रतिशत तक कोई कंडीशन नहीं है, परन्तु यह 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत पहुंचने पर कुछ कंडीशंज लगायी हैं। हम इन कंडीशंज में से 0.75 प्रतिशत अर्जित कर चुके हैं। अर्थात हम आज भी 4. 75 प्रतिशत लोन ले सकते हैं। फिर भी हम इसमें 3–4 प्रतिशत के बीच में रहेंगे और 4 प्रतिशत से ऊपर नहीं ले जाएंगे। ऐसी हमारी व्यवस्था रहेगी। जबकि अन्य राज्यों का इस समय का परसैंटेज देखें तो उसमें केरल का 4.3 प्रतिशत है, बिहार का 3.8 प्रतिशत है, छतीसगढ़ का 6.5 प्रतिशत है, उड़ीसा का 3.5 प्रतिशत है और पश्चिमी बंगाल का 3.9 प्रतिशत है। इस प्रकार इन सभी बड़े राज्यों से हमारी परसैंटेज ठीक है। इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूं। इसके अतिरिक्त हमारे बजट एस्टिमेट्स और एक्चुअल एक्सपैंसिज के बारे में हमने कहा है कि अपने बजट एस्टिमेट्स के बजाए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी जो बजट एस्टिमेट्स आएं हैं और एक्चुअल एक्सपैंस में इस बार कुछ ज्यादा अन्तर इसलिए आया है क्योंकि कोविड–19 के कारण हमारा एक्चुअल एक्सपैंस कम हुआ है। इसलिए मैं इस आंकडे पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि चाहे इस बार के बजट एस्टिमेट्स हों या आगे कभी बनाए जाएं और सरकार कोई भी आए, लेकिन प्रयत्न करें कि बजट एस्टिमेट्स और होने वाले एक्चुअल एक्सपैंसिज में ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए। अभी तक इसमें थोड़ा सा हायर साईड पर रखने का अभ्यास रहा है। फिर उसमें चाहे अर्थशास्त्रियों की सलाह हो या कोई मजबूरी रही हो। लेकिन 10–15 प्रतिशत बजट एस्टिमेट्स ज्यादा बनाए जाते रहे हैं। ये ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। हालांकि हम दो बार रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बना सकते हैं। हमें इसके लिए छूट है कि इनको बढ़ा भी सकते हैं, और घटा भी सकते हैं। शुरू में बजट एस्टिमेट्स ज्यादा रखने का कोई लाभ नहीं होता। जो पिछला रिवाइज्ड

एस्टिमेट्स है, उसके आसपास बजट एस्टिमेट्स बनाने चाहिएं। हम कोशिश करेंगे कि आगे से रियलिस्टिक फिग्गर्ज के हिसाब से बजट एस्टिमेट्स बनने चाहिए। जहां तक जी.एस.डी.पी. की बात है, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जी. एस.डी.पी. लगातार करैंट प्राईसिज से ऊपर बढ़ रही है। मेरे पास बहुत पुराना आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों का वर्ष 2011–12 से लेकर 2020–21 तक का बजट एस्टिमेट्स और वर्ष 2021–22 का प्रॉवीजनल एस्टिमेट्स का आंकड़ा है। यह वर्ष 2011–12 में 2,97,000 करोड़ रुपये से शुरू किया गया था। इसके बाद अगले वर्षों का क्रमशः 3,47,000 करोड़ रुपये, 3,99,000 करोड़ रुपये, 4,37,000 करोड़ रुपये, 4,95,000 करोड़ रुपये, 5,61,000 करोड़ रुपये, 6,44,000 करोड़ रुपये, 7,80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह लगातार बढ़ा है। यह कोविड–19 के वर्ष में थोड़ा सा कम हुआ है। वर्ष 2019–20 में 7,80,000 करोड़ रुपये के बाद वर्ष 2020–21 में 7,64,000 करोड़ रुपये पर मैंनटेन किया है। इसमें केवल 16,000 करोड़ रुपये करैंट प्राईसिज के कारण से कम हुआ है। हमारा अगला बजट अस्टिमेट्स 8,87,000 करोड़ रुपये का है। इसलिए इस कोविड के बाद अगले वर्ष इसकी क्षतिपूर्ति कर सकें, हमारी सरकार ऐसी योजनाएं बनाने का काम करेगी। हमारी जी.एस.डी.पी. की ग्रोथ लगातार 10 परसैंट, 6.5 परसैंट, 6 परसैंट और 8 परसैंट तक बढ़ रही है। जैसे मैंने बताया कि इस वर्ष 5.7 परसैंट कंट्रैक्शन है। हमारी सरकार इसको अगले वर्ष 11 परसैंट तक लेकर जायेगी यह मेरी सरकार का एक अनुमान है। सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे पास 15 साल के आंकड़े हैं। Trends in committed expenditure. ये 4 प्रकार के होते है। सैलरी, पैंशन, री–पेमैंटऔर इन्ट्रस्ट आदि। हम चाहे इधर से उधर हो जायें लेकिन हमें ये चार खर्चे करने ही पड़ेंगे। हम इन चार खर्चों के बाद विकास के बारे में सोच सकते है कि हमारे पास विकास करने के लिए कितना पैसा बचा है और कितना पैसा लगाना बाकी है। हम सैलरी को, पैंशन को, इन्ट्रस्ट को और री–पेमैंट को किसी भी कीमत पर कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रेंड्स अब तक चले आ रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा और किसी भी सूरत में इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मै समझता हूं कि इसमें किसी भी सदस्य को तकलीफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम इन आंकड़ों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसे कैसे करना चाहिए? अगर ट्रेंड्स ठीक रहेंगे तो प्रदेश का हित और विकास ठीक होता रहेगा। जहां तक स्टेट की सैलरी की बात

है तो हमारे स्टेट की सैलरी 3 हजार 600 करोड़ रुपये से शुरू होकर 26 हजार 400 करोड़ रुपये तक है। इसमें सारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बनता है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर नहीं बनता है। हमारे प्रदेश के जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, यह सारी सैलरी इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर ही खर्च होती है। इस सैलरी की year on year growth होती रहती है, वह बड़ी अलार्मिंग भी है। वर्ष 2008–09 में 41 परसैंट की ग्रोथ सैलरी में हुई थी और वर्ष 2009–10 में 32 परसैंट की ग्रोथ सैलरी में हुई थी। यह जो सैलरी में ग्रोथ हुई, मैं मान सकता हूं कि वर्ष 2006 के अंदर छठा वेतन आयोग लागू हुआ था और अभी सातवां वेतन आयोग लागू हुआ। छठा वेतन आयोग दिनांक 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2008–09 में छठे वेतन आयोग की सैलरी बढ़ाई थी या इस छठे वेतन आयोग के लागू होने के दो या तीन साल बाद सैलरी बढ़ाई थी। तब यह आंकड़ा बढ़कर 41 परसैंट हो गया था क्योंकि उससे पहले सैलरी में 13 परसैंट की ग्रोथ हुई थी और एक दम सैलरी में 41 परसैंट की ग्रोथ होना, मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात लगी। वर्ष 2010–11 में फिर 15 परसैंट सैलरी की ग्रोथ हुई। जो दो या तीन साल सैलरी की ग्रोथ बढ़ी है, उसकी सैलरी अधिकारियों/कर्मचारियों को दो या तीन साल बाद दी होगी। ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद वर्ष 2016–17 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था। हमारी सरकार ने इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद अगले साल से अधिकारियों/कर्मचारियों को सैलरी देनी शुरू कर दी थी। मैं सदन में वर्षवार ब्यौरा के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में वर्ष 2016–17 में 12 परसैंट, वर्ष 2017–18 में 9 परसैंट, वर्ष 2018–19 में 11 परसैंट, वर्ष 2019–20 में 9 परसैंट, वर्ष 2020–21 में 7 परसैंट के हिसाब से सैलरी का स्ट्रक्चर रखा गया और जहां तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 की बात है तो इसके लिए भी 18 परसैंट सैलरी स्ट्रक्चर का प्रावधान रखा गया है। जो सबके सामने भी है लेकिन किसी एक साल 41 परसैंट तक सैलरी का बढ़ना, क्या चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा होगा तो संभव सी बात है कि क्या स्थिति नहीं बिगड़ेगी? आखिर इतनी सैलरी क्यों बढ़ी, इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी इन आंकड़ों के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जो यह 41 परसैंट सैलरी में अचानक वृद्धि का काम किया गया, यह नहीं होना चाहिए था।

ऐसे ही पैंशन का विषय आता है। अचानक वर्ष 2009–10 में पैंशन भी 48 परसैंट तक बढ़ जाती है, जबकि पैंशन बढ़ने की एक निर्धारित रेगुलर प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया के हिसाब से साल दर साल कभी 16.9 परसैंट के हिसाब से,

कभी 19.2 परसैंट के हिसाब से तो कभी 15.5 परसैंट के हिसाब से निर्धारित मापदंडों के हिसाब से पैंशन बढ़ने की प्रक्रिया जारी रही है लेकिन 2009–10 में अचानक से पैंशन का 48 परसैंट तक बढ़ जाना किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है। आखिर ऐसी क्या बात थी जो इस तरह बढौत्तरी की गई? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पैंशन बढ़ने के आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010–11 में 29 परसैंट, वर्ष 2011–12 में 3.6 परसैंट जो कि पिछली बढ़ोतरी से कम रही, इसके बाद के वर्षों में पैंशन में 13.5 परसैंट, 14.7 परसैंट, 10.4 परसैंट, 17.6 परसैंट के हिसाब से बढौत्तरी की गई। अध्यक्ष महोदय, 2016–17 में 4.6 परसैंट पैंशन के हिसाब से पैंशन में बढौत्तरी हुई लेकिन वर्ष 2017–18 में पैंशन फिर से बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय अगर वर्ष 2006–07 में वेतन आयोग मिलने की वजह से पैंशन रिवाइज्ड होती है और इसकी वजह से वर्ष 2006–07 की बजाय वर्ष 2007–08 में एरियर बढ़ जाता है तो यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस एरियर को वर्ष 2009–10 में यानी तीन साल बाद अधिकारियों/कर्मचारियों को देने का काम किया गया। क्या हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति ऐसा काम करना ठीक था? अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत हमारी सरकार ने वर्ष 2016–17 के एरियर अगले वर्ष यानी वर्ष 2017–18 में देने का काम किया था। विपक्ष के लोग हमारी कहां–कहां से बराबरी करेंगे? हमारी सरकार के समय में भी पैंशन में इंक्रीज होना स्वाभाविक बात है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों के एरियर बहुत होते हैं। एक साल के बाद अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर देना सरकार का दायित्व बनता है और सरकार ने एरियर दिया भी है। अगर सरकार अधिकरियों/कर्मचारियों की सैलरी या पैंशन दो–दो साल या तीन–तीन साल तक लटकायेगी तो इन अधिकारियों/कर्मचारियों या रिटायर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना जागृत होती है। जोकि हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी तरह से वर्ष 2019–20 में फिर 8 परसैंट पैंशन में बढौत्तरी हुई और वर्ष 2020–21 में 12 परसैंट की पैंशन में बढौत्तरी हुई। इस बार पैंशन में बढौत्तरी कुछ कम होगी, ऐसे आंकड़े लिखे गये हैं। मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि हो सकता है कि जो लोग वर्ष 2006 के बाद रिक्रूट हुए होंगे। इन अधिकारियों/कर्मचारियों की पैंशन का बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा। वर्ष 2006 के बाद के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या धीरे–धीरे, जैसे–जैसे इनकी रिटायरमैंट नजदीक आती जायेगी और इस दौरान नये

अधिकारी/कर्मचारी भी भर्ती होते जायेंगे तो सरकार पर इनकी पैंशन का भार भी धीरे–धीरे घटेगा इसलिए हमें इन बातों की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि न्यू पैंशन स्कीम के तहत सरकार को पैंशन नहीं देनी होती है। कर्मचारियों/अधिकारियों के अपने फंड्ज जमा होते हैं। वर्ष 2006 के बाद उन्हीं फंड्ज में से इनको पैंशन दी जाती है। जो इन कर्मचारियों/अधिकारियों की इन्वैस्टमैंट होती है और जो इनका डिविडैंड फंड होता है। उसके हिसाब से इनको पैंशन दी जाती है। अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से इंट्रैस्ट की बात है। इंट्रैस्ट भी लगातार 17 परसैंट, 21 परसैंट, 20 परसैंट, 18 परसैंट, 23 परसैंट, 18 परसैंट और 19 परसैंट इंक्रीज हुआ। वर्ष 2016–17 में यह अचानक 27 परसैंट इंक्रीज हुआ। इसका कारण यह रहा कि हमने मार्च, 2015 उदय स्कीम में 25 हजार करोड़ रूपये का पॉवर कम्पनीज का लोन अपने जिम्मे लिया था। इस प्रकार से जो मार्च, 2015 में लोन लिया तो वर्ष 2016–17 में उसका इंट्रैस्ट एकदम बढ़ा। यह भी हो सकता है कि हमने एक दो साल के इंट्रैस्ट का इक्ट्ठा भुगतान किया होगा। इसी कारण से इंट्रैस्ट 27 परसैंट हो गया। उसके बाद फिर यह 13, 14 और 15 परसैंट का इंक्रीज हमारे इंट्रैस्ट में रहा है। हर साल का इतना इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम बजट को कहते हैं कि बजट 13 परसैंट बढ़ गया। इस प्रकार से चाहे सैलरी हो या दूसरे खर्च जैसे इंट्रैस्ट या पैंशन हों प्रत्येक खर्च हर साल 13, 14 या 15 परसैंट बढ़ता ही है। इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती। इस प्रकार की चीजों का हिसाब हमको लगाना ही पड़ता है। इंट्रैस्ट का मेरे पास एक आंकड़ा और है। यह एक बड़ी मजेदार बात है कि इंट्रैस्ट के मामले में भी हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना पड़ता है कि इंट्रैस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाये? कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने इंट्रैस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सावधानी बरती है। इंट्रैस्ट रेट का विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। अगर इंट्रैस्ट का रेट बहुत ज्यादा हो जायेगा तो हमें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में आज के समय में जितने भी फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशंज हैं, उन सब में कम्पीटिशन है। इस कम्पीटिशन के युग में हमें कम से कम इंट्रैस्ट पर लोन कैसे मिले, इसके लिए अपनी आर्थिक स्थिति भी काम आती है और नेगोशिएशन भी काम आती है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो हर साल का हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट इस सम्बन्ध में पिछले 10 साल की पूरी जानकारी मेरे पास है। हालांकि रेट ऑफ इंट्रैस्ट कम भी होता है लेकिन मैं

हाईयैस्ट के बारे में बता रहा हूं। अगर कहीं रेट ऑफ इंट्रैस्ट बहुत ज्यादा कम होगा तो मैं उसके बारे में भी बताउंगा वरना ये ज्यादातर हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट साढ़े आठ परसैंट और 9.17 परसैंट के बीच में रहता है। वर्ष 2010–11 में रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8.59 परसैंट था, वर्ष 2011–12 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 9.22 परसैंट था, वर्ष 2012–13 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 9.17 परसैंट था, वर्ष 2013–14 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 9.80 परसैंट था, वर्ष 2014–15 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 9.07 परसैंट था, इसके बाद वर्ष 2015–16 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8.51 परसैंट पर आ गया था, वर्ष 2016–17 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 7. 98 परसैंट था, यहां पर नैगोशिएशन करके हम लोएस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट को भी 6. 86 पर लाकर लोन लेकर आये हैं। इसके बाद अगर वर्ष 2017–18 की बात की जाये तो वर्ष 2017–18 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8.45 परसैंट था, वर्ष 2018–19 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8.62 परसैंट था। वर्ष 2018–19 में हमने एक विषय और शुरू किया कि हमारी स्टेट के ऊपर महंगे रेट ऑफ इंट्रैस्ट के जितने भी लोन थे उन सभी की अदला–बदली करके कैसे सस्ते रेट ऑफ इंट्रैस्ट पर कैसे लिया जा सकता है हमने इस बारे में पूरी ऐक्सरसाइज की। इसके लिए यह करना होता है कि उस पीरियड का पूरा इंट्रैस्ट देकर उसके बाद परचेज ऑफ लोन की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से हमने भी परचेज ऑफ लोन की कार्यवाही की। वर्ष 2013 में हमारे प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा एक लोन 9.89 रेट ऑफ इंट्रैस्ट पर लिया हुआ था। उसको हमने बदल करके 7.5 परसैंट के रेट ऑफ इंट्रैस्ट पर किया यानि लोन की अदला–बदली करके हमने 1.5 परसैंट रेट ऑफ इंट्रैस्ट को कम किया। इस प्रकार से यह एक नया सिस्टम हमारी सरकार ने शुरू किया। अब अगर वर्ष 2019–20 की बात की जाये तो वर्ष 2019–20 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8.28 परसैंट था और लोएस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 6.90 परसैंट था। इसी प्रकार से तो वर्ष 2020–21 में हाईयैस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 8 परसैंट था और लोएस्ट रेट ऑफ इंट्रैस्ट 4.4 परसैंट था। हमारे लोन का रेट ऑफ इंट्रैस्ट का परसैंटेज कैसे कम हो उसके लिए हमें क्या–क्या करना होगा इसके लिए भी हमने बजट में प्रॉविजन करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार और पूरे के पूरे प्रशासन तंत्र की दिशा ठीक है तो प्रदेश का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन अगर किसी सरकार और प्रशासन की दिशा ही अगर गलत हो जाये तो फिर चाहे कितनी भी उसकी आलोचना की जाये और कितनी भी

उसमें कमियां निकाली जायें उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सूरज नजर आता है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ) तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुरनारंभ)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आलोचना करनी चाहिए इसका कोई गिला नहीं है। आलोचना करें लेकिन जब किसी से गिला रखें तो अपने सामने आइना जरूर रखना, उसके बिना ठीक नहीं लगेगा। यहां पर बजट की बहुत आलोचनाएं की गईं। मैं पिछले 5–6 साल से जब से हम बजट बना रहे हैं तब से हमारे विपक्ष के साथियों ने जो आलोचनाएं की हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 2015 के बजट के बारे में विपक्ष की तरफ से कहा गया कि बजट निराशाजनक है, वर्ष 2017 में कहा गया कि नीरस बजट पेश किया गया है। वर्ष 2018 में बजट को दिशाहीन बताया गया, वर्ष 2019 में बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया गया। इसी तरह से वर्ष 2020 में बजट को निराशाजनक और दिशाहीन कहा गया तथा वर्ष 2021 में बजट को निराशाजनक बताया गया तथा कहा गया कि बजट में प्रदेश के विकास की कोई दिशा नहीं है। एक ही फॉरमैट में बजट की आलोचना की जाती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो बात सही होगी वह तो कही जायेगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि हर बात अगर सही है तो मैंने जो पिछले आंकड़े बताए हैं कि हम किधर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वे सारे आंकड़े झूठे हैं? अगर यह मुहावरा भी

बोलना हो तो मैं बताता हूं कि अच्छी प्रकार से आलोचना कैसे की जाती है। आलोचना करना हो तो करनी चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि अगली बार आप आलोचना का फॉरमैट बदल लो और बजट की आलोचना कैसे करें यह सुनो– खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी मरी हुई। मैं परामर्श दे रहा हूं कि ये बजट की आलोचना का फॉरमैट बदल लें। अगर वास्तव में कोई कमी हो तो बताओ, हम उसका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के दौरान बहुत से विषय आए हैं। हालांकि सभी सदस्यों ने विषय तो बहुत निकाले हैं लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है यह तो सभी जानते हैं, विषय निकालने वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन चूंकि दो–तीन दिन की डिबेट होती है तो विपक्ष का धर्म है आलोचना करना उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ चीजें सच्ची भी होनी चाहिएं। यहां पर एक विषय रखा गया कि बजट के आंकड़े गलत रखे गये हैं। बजट में गलत आंकड़ों की भरमार है। हमारी बहन किरण जी की तरफ से उदाहरण दिया गया कि पैरा नं. 56 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों में हिन्दी और अंग्रेजी में अन्तर है। अब मैं बजट की प्रति का 56 नम्बर पैरा पढ़ कर सुनाता हूं:–

> "राज्य सरकार ने खरीफ, 2020 से एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। राज्य के हर ब्लॉक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13.27 लाख किसानों ने 2980.74 करोड़ रुपये की बीमा क्लेम राशि का लाभ उठाया है, जबकि खरीफ, 2020 के दौरान 9,14,273 किसानों को कवर किया गया था।"

मैं यहां पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि 9,14,273 किसानों को कवर किया गया है। यही पैरा मैंने इंगलिश में निकाला और देखा कि शुरू की तीन लाईनें ठीक हैं और चौथी लाईन में लिखा हुआ है कि–

> " a claim amount of Rs. 2980.74 crores under this scheme so far, while 9,14,253 farmers wer covered during Kharif 2020".

वहां पर हिन्दी में लिखा 9,14,273 और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 9.14 लाख फार्मर। इसको गलत बता कर आरोप लगाया जा रहा है। यह हर किसी को पता है कि जब डैसिमल में फिग्गर बदली जाती है तो उसको 2 डैसिमल तक राउंड फिग्गर बनाया जाता है। अगर यह 9,14,273 की बजाय 9,14,773 होता तो यह

फिग्गर 9.15 अपने आप हो जाती। यह तो कम्प्यूटर की एक कला है। अगर विपक्ष के साथी समय का ध्यान रख कर चीजों को ठीक सन्दर्भ में रखेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार जरूर कराना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यह अंग्रेजी–हिन्दी में ही है। मैंने जो बताया है वही आपको बता रहा हूं। उन्होंने पैरा नम्बर देकर बताया है। मैं तो उसी को मिलाऊंगा।(शोर एवं व्यवधान) मैंने बाकी को नहीं मिलाया है। इसमें मैं एक बात और बताता हूं कि जो बजट भाषण होता है। जो बोला हुआ होता है वही रिकॉर्ड पर होता है। जो छपा हुआ होता है वह रिकॉर्ड पर नहीं होता है इसलिए बहुत सी चीजें जैसे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको यह लगता है कि इस छपे हुए में मुझे कुछ परिवर्तन करना है, तो वह कर सकता है। जो छपा हुआ मेरे हाथ में आया था उसमें मैंने भी पांच परिवर्तन यहीं खड़े–खड़े किये थे। आखिर हमें भी यह बहुत पहले पढ़ने को नहीं मिलता है। आखिरी रात को ही मिलता है लेकिन इसमें आंकड़े नहीं बदले जाते। केवल हम उसका वाक्य देखते हैं। अगर उस वाक्य में सुधार करना है, तो हम उसको करते हैं। अब एक जगह परिवार पहचान पत्र के बारे में लिखा हुआ था जिसमें परिवार पहचान पत्र के 2.10 करोड़ लोगों का एक आंकड़ा दिया हुआ था। मैंने उसमें क्या किया क्योंकि अभी तो चल रहा है इसलिए मैंने उसको कहा कि अभी तक 2.10 करोड़ । अब इसमें मैंने अभी तक शब्द जोड़ दिया क्योंकि है ही अभी तक। वह अभी बदलना है। वह हर रोज बदलेगा इसलिए किस चीज को, किस शब्द को आगे–पीछे करना है वह देखना पड़ता है। यहां जो बोला जाता है, वही रिकॉर्ड पर होता है केवल उसी को देखना चाहिए बाकी चीजों की ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यह मेरा कहना है। आज भी जो बोला है। हां, उसमें भी गलती हुई। मैंने पहले दिन चर्चा के शुरू होने से पहले उस गलती को स्वीकार किया और प्रस्ताव रखा। गलती हो सकती है लेकिन उसको आलोचना के रूप में नहीं रखना चाहिए। आप सवाल ठीक पूछें और अगर सवाल गलता होगा तो उसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है। आखिर गलत सवाल होंगे तो कैसे पूछेंगे? सवालों पर आखिर मुनीर नियाजी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। मुनीर नियाजी ने क्या कहा– '' किसी को अपने अमल को हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे तो जवाब क्या देते।'' जब सवाल ही गलत होंगे तो जवाब देना कठिन होगा। एक विषय हमारी बहन जी ने उठाया कि सरस्वती जैसी कई घोषणाएं की गई और उसमें पता नहीं कितना पैसा खर्च किया गया? पहली बात तो यह है कि हम सरस्वती नदी के महत्व के

बारे में जाने कि सरस्वती नदी क्या है? मुझे लगता है कि हम जिस स्तर के लोग हैं शायद सभी को मालूम होगा। इतिहास की एक चीज, आज की नहीं हजारों साल पुरातन है और उससे इतिहास भरा पड़ा है। उस पर सैंकड़ों ग्रंथ लिखे गये हैं कि कभी पहाड़ों के अन्दर उथल–पुथल हुई और जो सरस्वती नदी जिसका उद्गम स्थान हरियाणा में ही आदिबद्री में माना जाता है। आज भी उसका उद्गम स्थान वहीं से माना जाता है। यह ठीक है कि पानी की धाराएं डायवर्ट हो गई। उसमें से कुछ पंजाब की नदियों में चली गई, कुछ सिंधु नदी में चली गई, कुछ यमुना और गंगा नदी में चली गई। आज भी यमुना व गंगा नदी का जहां संगम है वहां यह माना जाता है कि यहां त्रिवेणी है। वहां पानी के अन्दर से नीचे से सरस्वती नदी का भी उद्गम स्थान है। वहां पानी का रंग बदलता है। ऐसी वहां मान्यता है। एक सरस्वती जो सैटेलाईट के द्वारा प्रमाणित हुई है क्योंकि वह सैटेलाईट आज भी अण्डर करंट्स की फोटो लेता है तो उस अण्डर करंट्स में जो हम इस समय जहां मानते हैं वह राजस्थान और गुजरात है। राजस्थान और गुजरात के बाद अरब खाड़ी में जाकर वह दिखाई देती थी। उसमें आज भी अण्डर करंट्स ऐसे ही मिलती हैं कि पानी की ई–अण्डर करंट्स धरती के अन्दर बहुत नीचे से तेजी से चल रही हैं। अब वह 10 हजार फिट है, 20 हजार फिट है या 30 हजार फिट है लेकिन नदियों की अण्डर करंट्स भी होती हैं। उस मान्यता को ध्यान में रखते हुए यह आया कि सरस्वती नदी का एक मार्ग जो था उस पर थोड़ा सैंगटिटी बनानी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 1986 में संघ का प्रचारक था। इतिहासकार डॉ. वाकणकर जी किसी काम के लिए आए थे। मैं उनके साथ में तीन दिन पैदल घूमा था। आदिबद्री से शुरू किया और पिपली, कैथल से घग्गर नदी के रास्ता से कलायत होते हुए वह रास्ता सरस्वती में मिल जाता है। हम वहीं तक गये थे। उसके बाद फिर मैं वापिस आ गया था लेकिन वे आगे गुजरात तक गये थे। कुल मिलाकर के राजस्थान, गुजरात में एक मान्यता है और उस पर हमने कुछ काम करना शुरू किया है। वहां एक हैरिटेज बोर्ड बनाया है और उसके हम साल में छोटे–बड़े फंग्शन करते हैं। मैंने आज कुल मिलाकर उसके बारे में डिपार्टमैंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पर उनका 1 करोड़ 15 लाख रुपये का सालाना खर्च आता है। उसमें जो लोग इम्प्लौईज हैं उसके खर्च भी हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं उनके खर्च भी हैं और वहां छोटे–मोटे काम भी हो रहे हैं। कहीं एस.टी.पी. है, कहीं जमीन लेने का विषय है। उस जमीन का जहां कहीं इन्क्रौचमैंट है या जहां

कहीं रैवेन्यू में पुराने रैवेन्यू खोजे गये उसके अन्दर नदी का नाम लिखा है। आज लोगों के कब्जे हो गये, रैवेन्यू रिकॉर्ड बदल गये। एक टीम उसके काम में लगी भी हुई है। यहां 1 करोड़ 15 लाख रूपये को मुद्दा बनाकर बात कही जा रही है कि सरस्वती नदी पर कितना रूपया खर्च कर दिया गया। जब हमने इसके लिए 2 लाख करोड रुपये का बजट रखा हुआ है और उसमें से अगर 1 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च कर दिए तो अचरज किस बात का है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो मान्यतायें हैं, चाहे वह मान्यतायें सरस्वती के बारे में हों, चाहे गीता के बारे में हों या चाहे फिर गाय के बारे में हों अर्थात मान्यताओं से संबंधित किसी विषय पर काम करने के लिए आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। सदन में एक विषय विद्युतीकरण की सब्सिडी का भी आया। हमारी बहन किरण चौधरी ने बताया कि यह 440 करोड़ रुपये कम हो गई है। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि अगर बिजली में सब्सिडी कम हो गई है तो इसको हमारे खिलाफ दोषारोपण नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसके लिए हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। हमने बिजली की चोरी रोकी है, बिजली के लॉसिज कम किए है। बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर एनर्जी युक्त एफिशियेंट पम्प सैट्स लगाने का काम किया है और किसान को पानी की एक बूंद की भी कमी नहीं आने दी। यह एक अलग बात है कि जिस गति से नए ट्यूबवैल लगने चाहिए थे उस गति से नहीं लग सके लेकिन पहले वाला कोई एक भी कनेक्शन पैंडिंग नहीं रहा और जितने पानी की जरूरत थी, उतना पानी देने का काम किया गया। हम अगर सब्सिडी कम कर रहे हैं तो यह एक तरह से सरकार के लिए बचत करने का ही काम कर रहे हैं। अगर यह बचत होगी तो इस बचत का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। अब हम जबरदस्ती तो किसी को सब्सिडी दे नहीं सकते है? सब्सिडी देने की जो प्रक्रिया है इसके तहत सरकार की तरफ से डिपार्टमैंट्स को सब्सिडी दी जाती है। अगर मान लो किसी डिपार्टमैंट ने व्यवस्था सुधार कर अपने आपको अपलिफ्ट करने का काम कर लिया है तो सरकार उसको जबरदस्ती सब्सिडी थोड़े ही देगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सरकार, पावर डिपार्टमैंट को सब्सिडी देती है लेकिन पावर डिपार्टमैंट ने यूटिलिटिज में व्यवस्था सुधार ली तो क्या इसको अच्छा नहीं माना जायेगा? हमने देखा है कि पांच–छह पी.एस.यूज. जोकि घाटे में चल रहे थे, ने पिछले पांच साल में प्रोफिट में आने का काम किया है। हमारे एक सदस्य ने यह भी कहा था कि उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों का जो खर्चा सरकार ने अपने उपर ले

लिया था, अब उस पैसे को सरकार को वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि बिजली कंपनियां अब लाभ में आ गई हैं। लाभ में आ गई हैं तो यह अच्छी बात है और इस संबंध में सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस बार जो हमारी बिजली उत्पादन कंपनियां हैं, उन्होंने पहली बार 115 करोड़ रुपये का डिविडैंड सरकार को देने का काम किया है। अब हरेक कंपनी जब प्रोफिट में आयेगी, या तो वह कोई नया प्लॉन तैयार करेगी, या टैरिफ कम करेगी, या सरकार ने इन कंपनियों के पास जो इक्विटी लगाई हुई है, उसके बदले में वह कंपनियां डिविडैंड देने का काम करेगी और ऐसा होने के बाद इस पैसे का प्रयोग समाज हित के लिए किया जा सकेगा। हमने पावर में आने के बाद कुछ कैटेगरीज के लिए बिजली के क्षेत्र में यूनिट्स चार्जिज को कम करने का काम किया है। हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जहां पहले 7–8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी वहां पर अब 4 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कनैक्शन देने का भी काम किया गया है। यह ठीक बात है कि जितनी संख्या में यह कनैक्शन दिए जाने चाहिए थे उतनी संख्या में नहीं दिए जा सके, हालांकि कनेक्शन देना एक अलग विषय है क्योंकि अब मैं सदन में रेट्स कम करने के विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों में गउशालाओं में जहां पर पहले कमर्शियल रेट्स पर बिजली दी जाती थी वहां पर भी 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज करने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब यह है कि हम जहां कहीं भी अच्छा कर सकते हैं, हमने अच्छा करने का काम किया है और आगे भी करते जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, गउशालाओं के लिए यह प्रावधान तो हमारी सरकार ने भी किया था। अगर विश्वास नहीं है तो चैक करवा लीजिए? (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सरकार के समय गउशालाओं के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज करने का काम नहीं किया जाता था बल्कि हमारी सरकार में ऐसा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी उठी थी कि पहले कृषि पर कुल बजट का 32 परसेंट खर्च होता था जो अब घटकर कुल बजट का 14.2 परसेंट रह गया है। वैसे मुझे ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं कि कभी कृषि के उपर कुल बजट का 32 परसेंट खर्च किया गया हो परन्तु कुछ ग्रुप्स को मिलाकर ऐसा किया जाना संभव हो सकता है जैसेकि इस बार

कुछ विशेष प्रावधानों के साथ इरीगेशन में अचानक से 75 परसैंट की बढ़ौतरी की गई, अगर ऐसा ही कुछ अचानक तब हुआ होगा तो 32 परसैंट वाली बात सही हो सकती है, वैसे अगर 32 परसैंट कृषि पर खर्च किया भी गया होगा तो यह बात भी मुझे अच्छी लगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अगर बजट की आलोचना करनी है तो ठीक प्रकार से करनी चाहिए और अगर आलोचना करने संबंधी कोई विषय सामने नज़र नहीं आता है तो जितना चुप रहें उतना ही अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात इस बार के सत्र में यह भी देखी कि अबकी बार जो बजट पेश किया गया है उसकी आलोचना बहुत थोड़े लीडर्ज ने ही की है जबकि मैं जैसी आलोचना सोच रहा था वैसी आलोचना नहीं हुई क्योंकि इसके लिए विपक्ष के लोगों को बजट में जिन बिंदुओं की जरूरत होनी चाहिए थी, वह बजट में थे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदेश के कर्ज के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। प्रदेश में बच्चा पैदा होते ही उसके सिर पर लगभग 1 लाख रुपये का कर्ज होता है क्योंकि हमारे प्रदेश की आबादी 2 करोड़ के करीब है और हमारे प्रदेश पर कर्जा 2 लाख करोड़ रुपये के करीब है। इस हिसाब से आज कोई भी पता लगा सकता है कि हर व्यक्ति पर लगभग 1 लाख रुपये का कर्जा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में इतना ही कहना है कि हर सरकार कर्जा लेती है और आगे भी लेगी। कर्जा लेने का एक फॉर्मूला बना होता है चाहे हरियाणा में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो। यह बात सही है कि हर पांच साल में कर्ज की राशि डबल हो जाती है। चाहे हम वर्ष 1966 से ही गणना करना क्यों न शुरू कर दे। यह बात ठीक होगी कि वर्ष 1966 में 100–200 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और पांच साल बाद डबल यानी 400 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ी और उसके बाद अगले पांच साल 800 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003–04 में प्रदेश पर कर्जा 17 हजार करोड़ रुपये था और वर्ष 2008–09 में यह कर्जा बढ़कर 34–35 हजार करोड़ रुपये हो गया और फिर 5 साल बाद वर्ष 2014–15 में यह कर्जा प्रदेश में 70 हजार करोड़ रुपये हो गया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उस समय बिजली विभाग के घाटे का खाता अलग से चलता था। जब हमारी सरकार वर्ष 2014–15 में सत्ता में आई तो उससे पहले लगभग 26 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था। अगर यह घाटा कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जोड़ दिया जाये तो 70 प्लस 26 यानी 96 हजार करोड़ रुपये का घाटा बनता है। कांग्रेस पार्टी के राज में ही बिजली विभाग का घाटा एकदम से

6 हजार करोड़ रुपये से 10 हजार करोड़ रुपये हो गया। इसकी जांच के लिये विभागीय एक कमेटी भी बनी थी कि कैसे एकदम 4 हजार करोड़ रुपये बढ़े। उस कमेटी ने अपना जवाब जो बनाया सो बनाया बाद में रिप्लाई दिया कि कर्जा ठीक लेते थे। अध्यक्ष महोदय, उदय स्कीम की शुरूआत वर्ष 2010–11 में हुई थी लेकिन वर्ष 2015 में आई थी। इस स्कीम के अनुसार सारा का सारा कर्जा सरकारें ऑब्जर्व करेंगी। मान यह लिया गया कि सैंट्रल गवर्नमैंट ऑब्जर्व करेगी। इस प्रकार से जितने भी बिजली विभाग के इधर–उधर के घाटे हैं उसके कारण एकदम 6 हजार करोड़ रुपये से 10 हजार करोड़ रुपये कर दिये। यह बात रिकॉर्ड पर है। वर्ष 2015 में बिजली विभाग का पहले का कर्जा 25900 करोड़ रुपये इस सरकार ने अपने ऊपर लिया। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की एक योजना बनी थी और वह सारे प्रदेशों में बनी थी लेकिन हमारे यहां नहीं बनी थी। जितना भी बिजली उपयोगिता का कर्जा है, वे डूब जायेगा। जिसके कारण बिजली दे नहीं पायेंगे और वहां पर रेट ऑफ इन्ट्रस्ट ज्यादा था। जिसके कारण से बिजली की संपत्ति बिक जायेगी और कोई भी बिजली को उधार पर नहीं देगा। इसलिए उसे उदय योजना के अन्तर्गत सरकार के कर्ज में ऑब्जर्व करे। अध्यक्ष महोदय, यह योजना हमारी नहीं है बल्कि सैंट्रल गर्वनमैंट की योजना थी जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय से चली हुई योजना थी। केवल वर्ष 2014–15 में फलीभूत हुई थी। सरकार तो सरकार होती है कर्जा जो था उसको हमें मिलाना तो पड़ेगा ही, इस प्रकार से लगभग 96 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हो जायेगा। बिजली बिभाग के लिये नहीं लेते तो आज बिजली बिभाग का कर्जा 24 हजार करोड़ रुपये की बजाये 50 हजार करोड़ रुपये हो जाता। आज हमें हमारे बिजली बिभाग की जो लाभ में आने की स्थिति नजर आती है, वह नहीं बनती क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इन्ट्रस्ट 12–13 प्रतिशत था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, लोगों को बिजली के बिल भरने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हमने स्कीम चलाई थी और उसके बाद कई लाख लोगों ने बिल भरना शुरू कर दिया था । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2015 में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना का करनाल के गांव सटौण्डी से उद्घाटन किया था । इस बारे में मैं सदन को एक छोटा–सा किस्सा बताना चाहता हूं । एक बार मैं मार्च, 2015 में बाढड़ा में रैली करने जा रहा था तो उस समय के बाढड़ा विधान सभा के विधायक श्री

सुखविन्द्र माण्डी ने मुझे अपने क्षेत्र से संबंधित एक मांग–पत्र दिया । उस पर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम आपके क्षेत्र की सारी मांगे मान लेंगे लेकिन रैली में वहां की जनता से एक मांग मैं भी मांगूंगा । यह बात सुनकर श्री सुखविन्द्र माण्डी जी हैरान हो गये कि प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जनता से क्या मांग मांगेगा । इसके बाद वे मुझसे पूछने लगे कि आप जनता से जो मांग करोगे वह पहले मुझे बताओ । इस पर मैंने कहा कि मैं वहां की जनता से मांग करूंगा कि वे अपने बिजली के बिलों को भरना शुरू कर दें । इस पर श्री सुखविन्द्र माण्डी जी मुझसे कहने लगे कि फिर हम इस रैली को रहने ही देते हैं । मैंने उनसे कहा कि हम रैली भी करेंगे और जनता से मांग भी मांगेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैंने रैली में जाकर झोली फैलाकर लोगों से अपील की कि वे अपने बिजली के बिलों को भरना शुरू कर दें । मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने जनता के सामने इस तरह का व्यवहार किया होगा और ऐसी हिम्मत दिखाई होगी । मेरी जनता के सामने की गई उस अपील का परिणाम सामने आया और आज वहां के 52 गांवों में 24 घंटे बिजली चल रही है । इससे पहले वहां पर 32 परसैंट लाइन लॉसिज थे । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे है उससे पहले भी यह स्कीम बनी हुई थी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हुड्डा साहब के समय में अगर ऐसी कोई स्कीम होगी भी तो उस समय उसके परिणाम सामने नहीं आये थे । हमारी सरकार ने उस स्कीम के परिणाम निकाले हैं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यह न सोचें कि हरियाणा में सारा विकास कार्य ही इस सरकार ने किया है । सरकार एक ऑनगोइंग प्रोसैस है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह न सोचें कि हरियाणा भी इन्हीं ने बनाया है और सारा कुछ इन्होंने ही किया है । हमसे पहले भी सरकारें रही हैं और अपने समय में उन्होंने भी अच्छा काम किया था । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की बातें सही हैं । मैं इन बातों से मना नहीं करता लेकिन अब मैं कर्ज के विषय पर बात करना चाहता हूं । कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के हर एक बालक पर दो लाख रुपये का कर्ज हो चुका है । मेरा कहना है कि कर्ज की गणना की यह बात बिल्कुल सही है लेकिन मैं आपको एक और हिसाब भी बताता हूं । यह ठीक है कि सरकारी आंकड़ो में इस

प्रदेश का हर बच्चा 2 लाख रुपये का कर्जदार है । स्टेट की जी.डी.पी. स्टेट की असैट होती है और स्टेट के असैट्स को जोड़–भाग आदि करने का एक प्रोपर सिस्टम होता है । मेरा कहना है कि किसी स्टेट की जो असैट्स और प्रॉपर्टीज आदि होती हैं वे उस प्रदेश की जनता की ही होती हैं । इस तरह से हमारे स्टेट की जो असैट्स हैं अगर उनको जोड़ लिया जाए तो जिस बालक को 2 लाख रुपये का कर्जदार कहा जा रहा है वही बालक 12.91 लाख रुपये का मालिक भी है । इसका मतलब यह नहीं है कि ये रुपये उस बालक के घर में पहुंचा दिए जाएंगे । जिस तरह से स्टेट के लोन पर उस स्टेट के रहने वाले हर व्यक्ति से संबंध और वह उस लोन के कारण कर्जदार होता है उसी तरह से स्टेट की असैट्स भी उस स्टेट के रहने वाले हर व्यक्ति की होती है । हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए । मैंने डैट लायबिलिटी के बारे में साल–दर–साल का बता दिया है, इसलिए इसको दोबारा बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं । वर्ष 2009 में पिछली सरकार ने 5,686 करोड़ रुपये का लोन लिया था जोकि बढ़ते हुए 6,819 करोड़ रुपये हुआ, फिर 7,185 करोड़ रुपये, फिर 10,378 करोड़ रुपये हुआ, फिर 13,225 करोड़ रुपये हुआ और फिर 15,131 करोड़ रुपये हो गया । इसके बाद जब हमारी सरकार सत्ता में आयी तो वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 में हमें दो सालों में 'उदय' के लोन को कम्पलीट करने के लिए अडॉप्ट करना पड़ा । इस कारण हमें 'उदय' का लोन क्रमशः 33 हजार करोड़ रुपये और 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलाकर कुल लोन लगभग 57 हजार करोड़ रुपये हो गया । अगर हम इस 57 हजार करोड़ रुपये के लोन में से 25 हजार करोड़ रुपये घटा देते हैं तो वही लगभग 31 हजार करोड़ रुपये बचते हैं और इन दोनों सालों की ऐवरेज लगभग 15.50 हजार करोड़ रुपये की आती है । अतः स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये कर्ज का रेश्यो तो पहले से चला आ रहा है और हमने पॉवर डिपार्टमैंट के नाते से 'उदय' का उन 2 सालों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा कर्ज लिया है । यह हमने पॉवर डिपार्टमैंट के लिए लिया है। इस अमाउंट को धीर–धीरे करके 5 सालों में उतारेंगे। इसका पांचों में 15–20 प्रतिशत हिस्सा साथ–साथ पे करना पड़ता है और उसका इन्ट्रैस्ट भी पे करना पड़ता है। इस प्रकार पांच साल इसका इफैक्ट रहेगा। वर्ष 2017–18 में हमने 17,300 करोड़ रुपये लोन लिया था। वर्ष 2018–19 में 22,000 करोड़ रुपये लोन लिया था। वर्ष 2019–20 में 25,000 करोड़ रुपये लोन लिया था और वर्ष 2020–21 में 30,000

करोड़ रुपये लोन लिया है। इस लोन के बदले में प्रिंसिपल अमाउंट को उतारना ही पड़ता है। जो कर्जा 7–8 साल पहले लिया था, वह कर्जा अपने आप 8 साल के बाद ऑटोमैटिकली बैंक में से चला जाता है। उसके लिए कोई पूछता नहीं है, यह एक सिस्टम होता है। इसलिए जो कर्जा आज से 8 साल पहले लिया था, उसको आज हम उतार रहे हैं। हम जो आज कर्जा ले रहे हैं उसको भी 8 साल के बाद कोई उतारेगा। यह मैं एक विषय बता रहा हूं। ऐसे ही इन्ट्रैस्ट की बात है। इसमें भी हर साल का जितना अमाउंट होता है। फिर चाहे वह 5 साल पहले लिया हो, 6 साल पहले लिया हो या 7 साल पहले लिया हो। यह टोटल 7 या 8 साल का कर्जा होता है और उसका इन्ट्रैस्ट हर साल देना होता है। इन्ट्रैस्ट और मूलधन को मिलाकर हमने जो पैसा वापिस किया है। फिर चाहे वह किसी भी सरकार ने किया हो। उसमें टोटल रि–पेमैंट करने के बाद भी कुछ पैसा बाकी बचता है। जो पैसा बाकी बचता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं इकाई–दहाई को छोड़कर केवल सैंकड़े बोल रहा हूं। वर्ष 2009–10 में लगभग 2500 करोड़ रुपये बचा था। वर्ष 2010–11 में 3000 करोड़ रुपये बचा था। वर्ष 2011–12 में 2600 करोड़ और वर्ष 2012–13 में 4900 करोड़ रुपये बचा था। मैंने यह चार सालों का आंकड़ा बताया है और इन चार सालों में हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। इसमें शुरू में जो 2500 करोड़ रुपये बचा था उसके बदले में 5200 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बार 3,000 करोड़ रुपये बचा था उसके बदले में 4700 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। तीसरी बार 2600 करोड़ रुपये बचा था उसके बदले में 4900 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। चौथी बार 4900 करोड़ रुपये बचा था उसके बदले में 6200 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार बचे हुए लोन से हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। अगले चार साल में क्रमशः 6700, 7700, 23900, 13400 करोड़ रुपये बचा है। इसमें हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कम हुआ है। वर्ष 2013–14 और 2014–15 की अमाउंट हमारे खाते में जमा है। इसमें 6700 करोड़ रुपये से 4700 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया और 7700 करोड़ रुपये से 4500 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। इससे अगले साल 23,000 करोड़ रुपये से हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़ रुपये का हो गया। इसमें मात्र 1.50 प्रतिशत कम हुआ है। इसके अगले साल का 13,000 करोड़ रुपये से 11300 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसमें भी 5 या 6 प्रतिशत ही कम हुआ है। इसके बाद वर्ष 2017–18 में 17,000 करोड़ रुपये लोन लिया था और इसमें से 13,000

करोड़ रुपये इन्ट्रैस्ट और प्रिसिपल अमाउंट के वापिस किये हैं। इसमें 4200 करोड़ रुपये बाकी बचते हैं। हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 14,932 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यानी इससे साढ़े तीन गुना ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। जो हमारे पास बचा हुआ पैसा है, उसको रिवैन्यू रिसोर्सिज पर खर्च करते हैं। इससे अलग साल 5353 करोड़ रुपये बचे थे और खर्च 16,000 करोड़ रुपये किये हैं। यह पैसा तीन बार खर्च किया गया था। इससे अगले साल 6400 करोड़ रुपये बचे थे और हमने तीन बार में 18900 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अगला साल कोविड–19 का होने के कारण 8900 करोड़ रुपये बचा था और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 6900 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें कम खर्च हुआ है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि आप अगले साल सिर्फ 10,000 करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। यह आंकड़ा कई माननीय सदस्यों ने दिया था। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमने पिछली बार 40,000 करोड़ रुपये का लोन लेना था, परन्तु हमने 30,800 करोड़ रुपये का लोन लिया है। हमने 10,000 करोड़ रुपये कम लोन लिया क्योंकि आवश्यकता कम लोन की थी। इसलिए यह कम लिया है। हम यह 8500 करोड़ रुपये अगले साल लेंगे और यह पैसा भी लोन में जुड़ेगा। इसको हमने अगले साल के लिए अलग अकाउंट में रखा है। उस अकाउंट का नाम मीडियम टर्म एक्सपैंडीचर रिजर्व फंड रखा है। हमने हरियाणा प्रदेश में यह नयी प्रथा शुरू की है। इससे पहले यह प्रथा न तो हरियाणा प्रदेश में थी न ही केन्द्र सरकार में थी। हमारे ध्यान में यह बात आयी कि जो पैसा बचता है, उसको हम ऐसे फंड में डालें, जिसको अगले साल में कहीं पर जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके।

बैठक का समय बढ़ाना

20:00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———————————

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र यह बात भी ध्यान में आई कि जो पैसा किसी कारण से बचता है उस पैसे को ऐसे फंड में डाला जाए ताकि अगले साल अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उस पैसे का प्रयोग

किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर हमें हर नए काम के लिए अलग से फाइल बनानी पड़ती और उसकी एप्रूवल के लिए तमाम प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा तो इन सबसे बचने के लिए हमने एक अलग से छोटी कमेटी बनाकर इस कार्य के लिए एप्रूवल भी करा दिया और इसका फायदा यह हुआ कि हमें कोई भी कैपिटल ऐक्सिपेंडिचर अगर करना है तो यह किया जा सकता है और इसके लिए हमें किसी प्रकार के रिवाइज्ड बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जब बजट की फाइनल सैटलमैंट होगी तो इस पैसे का यह प्रावधान रखा गया है, यह भी समय आने पर समायोजित हो जायेगा। कई बार क्या होता है कि हम बजट किसी फंड में ज्यादा तय कर देते हैं लेकिन उसमें उतना खर्च नहीं होता है तो उस पैसे को उससे अगले साल के लिए रिजर्व कर देंगे ताकि वह पैसा काम आ सके। कहीं भी एक बार रिजर्व किये हुए पैसे को हमारी सरकार वेस्ट नहीं होने देगी। आज हमें देखने में यही आता है कि यह पैसा लैप्स हो गया, काम पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कहने का भाव यही है कि परिस्थितियां बदलती रहती है लेकिन हमने इसको भी एक तरह से स्पैशल बनाने का काम किया है और यही कारण है कि अगले साल हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 हजार करोड़ की बजाय 19 हजार 142 करोड़ रूपये होगा, इसलिए इस बात को भी ध्यान जरूर रखा जाये। यह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एडीशन होगा। मैंने पहले ही फिस्कल डैफिसिट के बारे में बता दिया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के आंकड़े आसपास के प्रदेशों से बहुत अच्छे हैं। मैंने सब्सिडी कम करने की बात भी बताई है। हमने इसमें संशोधन इतना ही किया है कि सब्सिडी कम नहीं की है बल्कि सब्सिडी को बढ़ाया है क्योंकि हमने आर.ई. में सब्सिडी के खर्चे के रूप में 5149 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और इसी प्रकार डी.ई. के तहत 5600 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है जो कि एक तरह से 550 करोड़ रूपये ज्यादा है। डी.ई. में जितना पैसा रखा गया है उससे कम ही खर्च किया गया है यह भी अपने आप में एक उपलब्धि ही है। हमारी सरकार ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं। जैसा मैंने इस सदन में पहले भी इस विषय के बारे में जानकारी दी थी कि सरकार ने एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेम वर्क रिजर्व फंड भी बनाया। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई व्यवस्था है। हमारी सरकार ने दूसरा प्रयोग यह किया है कि जो आउट कम बेस्ड है वह हमारा आउट पुट होना चाहिए। हमारी सरकार ने यह भी एक नई व्यवस्था बनाई है। अभी तक हम बजट के एक्सीपैंडीचर को ही अपना

आउट कम मान लेते है। जैसे मान लो हमारा बजट हजार करोड़ रुपये का है तो इसमें से 800 करोड़ रुपये खर्च हो गया तो हम इसको 80 परसैंट प्रोग्रैस मान लेते हैं। हम सभी यह बात जानते हैं कि इस बजट का दुरुपयोग कैसे–कैसे होता है और खास करके जो साल के आखिरी महीने होते हैं उनमें हमें इस पर चैक लगाना है कि साल के आखिरी महीनों में अनाप–शनाप बजट का खर्च करके इसी को प्रोग्रैस न माना जाये बल्कि हमारे बजट का सिस्टम आउटकम बेस्ड होना चाहिए। आने वाले समय में हमारी सरकार आउटपुट के पैरामीटर भी बनायेगी कि प्रदेश में कितना काम हुआ? अगर कोई कम बजट में ज्यादा काम करता है तो उसको शाबाशी दी जायेगी। ज्यादा बजट में ज्यादा काम हर कोई कर सकता है लेकिन हमारी सरकार आने वाले समय में कम बजट में अच्छा काम करने की पद्धति खड़ी करने का काम करेगी। हम इसका सिस्टम बनायेंगे। मैं इस सदन में एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। अब इसके अंदर हर परिवार का एक डाटा इक्ट्ठा कर रहे हैं जो गरीब परिवार हैं। उन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनके परिवार उत्थान का सिस्टम कैसे तैयार किया जाये? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि अब इसके अंदर कोई एक विभाग काम नहीं करेगा। हमारी सरकार को इसके अंदर एक विभाग के गजट की जरूरत नहीं है। इसमें प्रदेश के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। विभाग के अपने–अपने बजट के अनुसार काम करेंगे। जिस विभाग के पास जितना बजट होगा उसके हिसाब से वह विभाग काम करेगा। हमारी बहन शकुन्तला जी कह रही थी कि सरकार ने एस.सी. वर्ग का ध्यान नहीं रखा, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा और किसान का ध्यान नहीं रखा। हमारी सरकार इस प्रकार की श्रेणी बनायेगी। जिसमें महिला भी होगी, जिसमें गरीब भी होगा, जिसमें किसान भी होगा, जिसमें मजदूर भी होगा, जिसमें युवा भी होगा, जिसमें एस.सी. भी होगा, जिसमें बी.सी. भी होगा और जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा। हमारी सरकार ने एक ऐसे ही प्रोग्राम की शुरूआत की है। इसके पहले चरण में एक लाख परिवारों की आय को देखा जायेगा कि एक लाख परिवार की अपर सीमा क्या निकलती है? बाकायदा तौर पर इसका सर्वे किया जायेगा और यह अपर सीमा सर्वे के बाद निकाली जायेगी लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि जिन परिवारों की साल की आमदनी 30–40 हजार रुपये है, वे परिवार ही एक लाख के करीब इसमें शामिल होंगे। गरीब परिवार की कल्पना बहुत से लोगों को

नहीं है लेकिन मुझे इनके बारे में अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं गरीब परिवारों की बस्तियों में जाता रहता हूं। मुझे ऐसे–ऐसे लोग मिले हैं। जो एक छोटे से कमरे में चार–चार लोग, तीन–तीन लोग और पांच–पांच लोग सोते हैं। कोई चारपाई पर सो जाता है तो कोई नीचे सो जाता है। जिनकी रसोई छोटी सी होती है तो उसमें वे अपनी टांगे सिकोड़कर सो जाते हैं। कई बार उनको दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है। वे लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको समय पर मजदूरी भी नहीं मिलती है। हमारी सरकार ने ऐसे परिवारों के बारे में अलग–अलग विभागों के सामने बात भी की है। चाहे उसके अंदर हमारा ग्राम विकास हो, चाहे शहरी स्थानीय निकाय हो, चाहे एनीमल हसबैंड्री हो, चाहे रोजगार विभाग हो और चाहे स्किल डिवैल्पमैंट विभाग हो सब विभाग अपने–अपने तरीके से काम करते हैं। जहां तक बात सैल्फ हैल्प ग्रुप की है, एम. एस.एम.ई. की है तथा इन्डस्ट्री है ये सब अपने–अपने तरीके से काम करती हैं। हमारी सरकार ऐसे सब लोगों को बैचिज में काम देने के बारे में विचार कर रही है। हम ऐसी खुली घोषणा नहीं करते कि पांच लोग आ जाओ हम आपको काम देंगे। पहले एक लाख उसके बाद अगला एक लाख उसके बाद आगे के एक लाख लेकिन lowest one इसको हम अंत्योदय कहते हैं अर्थात् अंतिम का उदय। हमारी ये सभी योजनायें महात्मा गांधी जी के नाम से और पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से चल रही हैं। मनरेगा भी हमारे यहां है। मनरेगा में भी बहुत से लोगों को काम मिलता है और बहुत से लोगों को काम नहीं मिलता है। जो lowest income group के लोग हैं, उनको हम सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ेंगे। चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की कोई योजना हो lowest income group के सभी लोगों को हम उनके दायरे में लेकर आयेंगे। केन्द्र सरकार की योजनाओं के अपने पैरामीटर्ज होते हैं हम उनको भी कहेंगे कि जो कम से कम पैरामीटर्ज के लोग हों, सबसे पहले उन्हीं लोगों को सहायता दी जाये। चाहे मकान की बात हो, चाहे पारिवारिक फंक्शन की बात हो, चाहे बेटी को पढ़ाने की बात हो और लड़की की शादी की बात हो इन सभी के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्कीमें हैं लेकिन हम इन सभी स्कीमों की शुरूआत सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता से करेंगे। गरीबी का एक पैमाना समरसता के लिए जरूरी है। हम समाज को जो अलग–अलग वर्गों में सोचते हैं कि कोई एस.सी. है, कोई बी.सी. है, ये फलां जाति का है, बी.सी. में भी दो ग्रुप हैं

और एस.सी. में भी दो ग्रुप हैं। इस प्रकार से हम जाति और फिर जाति में भी जाति के मकड़जाल में उलझे रहते हैं। ये सभी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है। इनमें भी जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, हमें सबसे पहले उनके उत्थान के बारे में सोचना होगा। अगर इनके बारे में सोचा जायेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक सुखी समाज होगा हम इसकी कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से जो जो विभिन्न विभाग हैं जिनके बजट का आबंटन हम आज तक अलग–अलग करते रहे हैं कि इस विभाग का इतना बजट और किसी दूसरे विभाग का इतना बजट होगा। किसी विभाग का बजट 100 करोड़ रूपये है और किसी विभाग का बजट 500 करोड़ रुपये है। ये अलग–अलग विभागों के अलग बजट की परम्परा को हमने बदला है। हमने इसमें कुछ सैक्टर्स के समूह बनाये हैं। सोशल सैक्टर में कौन–कौन से विभाग आते हैं? इंफ्रांस्ट्रक्चर के कौन–कौन से विभाग आते हैं? स्वास्थ्य के नाते क्या–क्या चीजें हो सकती हैं? अब स्वास्थ्य में आर्युवेद भी है, स्वास्थ्य में मैडीकल एजूकेशन भी है, स्वास्थ्य में आयुष्मान भी है, स्वास्थ्य में वैलनैस सैंटर्ज भी हैं और स्वास्थ्य में व्यायाम व योगशालायें भी हैं। स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आदमी पहले तो बीमार ही न हो इसकी योजना बनानी पड़ेगी। अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करना हमारा दायित्व है वह हम करेंगे ही करेंगे लेकिन उससे पहले अगर हमने योजना बनाकर आदमी के बीमार होने के कारणों का पता लगा लिया तो फिर उसके बीमार पड़ने की सम्भावना ही कम हो जायेगी। अगर व्यक्ति के शरीर का ठीक प्रकार से पालन पोषण हो जाये और उसके खाने–पीने व दूसरी सुविधाओं का पूर्ण इंतजाम हो जाये और उसको डायटीशियन की सेवायें भी प्राप्त हो जायें तो व्यक्ति कम से कम बीमार पड़ेगा। इन सभी का इंतजाम हमको करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने अपनी योग व्यायाम शालाओं के अंदर 1000 वैलनैस सैंटर्ज इस साल खोलने की योजना बनाई है। भविष्य में इसको और भी आगे बढ़ाया जायेगा। इसी प्रकार से प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रदेश के संसाधनों को जुटाना पड़ेगा और परिसम्पत्ति का मुद्रीकरण करना पड़ेगा। प्रदेश में जमीनों से सम्बंधित इतने झगड़े हैं और इतनी दुनिया भर की स्कीमें हैं हम उन सभी को एक हैड के अंतर्गत लेकर आये हैं। उस हैड में जो सम्बंधित डिपार्टमैंट्स हैं वे एक साथ मिलकर योजनायें बनायेंगे और मिलकर योजनायें बनाने में किसी एक जगह का बजट दूसरी जगह भी हमको खर्च करना है। हम उसमें सुविधायें देंगे ताकि उस

पूरे सैक्टर का लोगों को लाभ मिल सके। यह भी हमें करना है। इसकी भी हमने योजना बनाई है। एक विषय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से सम्बंधित है। उस संशोधन में यह कहा गया है कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय दोनों को मजबूत किया जाये। मुझे यह बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि संविधान में 72वां और 73वां संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था लेकिन 29 साल से हम इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाये हैं। हम उसमें एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे सैंट्रल लैवल पर इंटर स्टेट काउंसिल होती है। इसी प्रकार से जैसे पहले हमारे यहां योजना आयोग होता था और अब नीति आयोग हो गया है। उसके अंतर्गत यह काम किया जाता है। उसके द्वारा हर स्टेट का ध्यान रखा जाता है और खास करके जो स्टेट्स ज्यादा पिछड़ी हुई हैं उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने के लिए नीति आयोग विभिन्न योजनायें बनाता है। ऐसे ही इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उन स्थानीय निकायों को जो अपेक्षाकृत ज्यादा पिछड़े हुए हैं विकेन्द्रीयकरण करके उनको ज्यादा ताकत देंगे और उनको ज्यादा अधिकार दिये जायेंगे। उनको जो फण्ड्ज राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से मिलने होंगे वे भी उनको देंगे। उसका भी बजट में उल्लेख होगा लेकिन हम यह चाहते हैं कि हरेक इकाई अपना बजट स्वयं बनाये ताकि हर इकाई की इंकम बढ़े। हम यह अधिकार भी उनको देंगे। हम प्रत्येक मद के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करेंगे कि किसी संस्था द्वारा किसी मद में कम से कम कितना खर्च किया जा सकता है। अगर कोई भी संस्था उससे ज्यादा लगाना चाहेगी तो हमारे यहां डैमोक्रेटिक सिस्टम है ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की कोई भी संस्था अपने स्तर पर फण्ड्ज का बंदोबस्त करके लगा सकती है क्योंकि लोगों ने करों का भुगतान करना है और सम्बंधित संस्थाओं ने करों को लेना है। हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थायें स्थानीय निकाय का काम करें। इस प्रकार से इस व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कांसैप्ट के ऊपर भी हमने पिछले सालों के दौरान बहुत सा काम शुरू कर दिया है। अब इस साल में हम इसको और आगे बढ़ायेंगे। एक विषय यह आया कि 2 प्रतिशत की स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है यह ठीक नहीं है। शहरी इकाइयों में तो हम 2 प्रतिशत की स्टैम्प ड्यूटी पहले भी लेते थे लेकिन अब उनको कंसौलिडेटिड फंड में न ला कर सीधा देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न यह भी आया कि स्टैम्प ड्यूटी

की इन्कम बजट में कम क्यों हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि 6 प्रतिशत ऐवरेज होती है। महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत तथा पुरूषों के लिए स्टैम्प ड्यूटी 7 प्रतिशत होती है। इस प्रकार से ऐवरेज 6 प्रतिशत में यह मान कर चलो कि 1/3 यानी 2 प्रतिशत सीधा शहरी इकाइयों को चला जायेगा वह साढ़े 7 हजार की बजाय 5 हजार सरकार को चला जायेगा और 2500 संबंधित शहरी इकाई को सीधा जायेगा वह कंसौलिडेटिड फंड में नहीं आयेगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी क्योंकि वहां बिक्री बहुत ज्यादा नहीं होती है और दूसरा विषय यह है कि वह स्टैम्प ड्यूटी किसी गांव के आदमी पर नहीं लगती है बल्कि खरीददार पर लगती है लेकिन उसका लाभ उस गांव को हो जायेगा जिस गांव में जमीन बिकती है। वहां पर भी हमने 2 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी लगाई है। 1 प्रतिशत सीधा गांव को जायेगी और 1 प्रतिशत हम जिला परिषद् और पंचायत समितियों में बंटवारा करेंगे ताकि उनको भी इन्कम हो जाये। ऐसी इन्कम के प्रावधान, साधन स्थानीय निकाय के ज्यादा करेंगे, उनको पूरी छूट देंगे। इसीलिए बतरा जी ने कहा कि स्थानीय निकाय का बजट 18 प्रतिशत कम हो गया है, इसका वही कारण है कि अढाई हजार करोड़ रुपया हमने उनको सीधा दे दिया है। इसलिए हमारे बजट का अढाई हजार करोड़ नहीं कुछ कम हुआ है लेकिन अढाई हजार करोड़ की इन्कम हमने सीधे उनको दे दी है। इधर से बजट कम है और उधर से उनका खर्चा कम है। अब विषय फोकस पर आता है। फोकस में मैंने कई बार कहा है कि हमारे 5 एस. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन और स्वाभिमान। ये हमारे 5 विषय हैं और पांचों पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। कृषि की बात मैंने बताई है वह स्वावलम्बन में आती है। शिक्षा के बारे में हमारी बात पहले भी हो गई है और शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में आप सभी को पता है कि हम इस बार ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में सुधार कैसे और ज्यादा हो उस पर फोकस कर रहे हैं। जो हमारे रनिंग स्कूल्स हैं, इनको अपग्रेड करके शिक्षा में सुधार किया जायेगा। इस बारे में एक किसी माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया था कि ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए गये हैं इनको तो जो पहले वाले स्कूल हैं, उनका बोर्ड बदल दिया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि यह किसी ने नहीं कहा कि हम नये संस्कृति मॉडल स्कूल्स खोलेंगे। पहले वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हो यही हमारा प्रयास रहता है क्योंकि नये स्कूल खोलने का मतलब है कि पहले वाले स्कूल अच्छी तरह से चल रहे हों क्योंकि हमारे पास

स्कूल्स की संख्या कम है। हमारे बहुत से स्कूल इसलिए बंद करने पड़े कि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या 20–25 है और वहां पर 3–4 अध्यापक पहुंचते हैं और उन अध्यापकों की ड्यूटी वहां पर बनी रहे इसलिए एडमिशन के अन्दर बहुत मैनिपुलेशन होता था। जब हमने इसको ऑनलाईन किया, आधार बेस्ड एडमिशन किया उसके बाद हमारे 2 लाख बच्चों की एडमिशन की संख्या कम हुई। बच्चे कम नहीं हुए लेकिन वे दो लाख चूंकि सरकारी स्कूल में भी एडमिशन था और प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन था। अभिभावक अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते थे और पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में थे। यहां से लाभ उठा कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। इसके हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। अब चूंकि एडमिशन आधार बेस्ड हो गया तो एक ही जगह पर एडमिशन लिया जा सकता है तो उन्होंने सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया जिसके कारण 2 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में कम हो गये। इसके कारण हमारे 400–500 स्कूल ऐसे थे जहां कि एडमिशन संख्या 25 से कम हो गई। लेकिन जहां पर संख्या कम है हमने केवल उनको ही छेड़ा है। इसमें कोई व्याख्यान का विषय नहीं है कि बच्चे 20–25 बैठे हैं और टीचर 2–3 बैठे हैं। हमने उन बच्चों को पास वाले स्कूल में शिफ्ट किया है। बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां पर दो–दो स्कूल्स हैं। सबसे पहले चरण में तो हमने उन्हीं स्कूलों को बंद किया है जहां दो स्कूल थे। ऐसे स्कूल्स की क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए उन्हीं टीचर्स का इंटरव्यू लेकर जो अच्छे लेवल के टीचर हैं, इन संस्कृति मॉडल स्कूलों में लगायेंगे तथा उनका अलग कैडर बनायेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, संस्कृति मॉडल स्कूल, सीनियर सैकेंड्री स्कूल्स हैं। सबसे पहले तो हमने जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनका ही नाम बदल कर संस्कृति मॉडल स्कूल में कन्वर्ट किया था। पहले ये स्कूल्स हमारे भिवानी बोर्ड से ऐफिलिएटिड होते थे। भिवानी शिक्षा बोर्ड को नैशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। अब सरकार इन संस्कृति मॉडल स्कूलों को भिवानी शिक्षा बोर्ड से हटा कर सी.बी.एस.ई. से ऐफिलिएटिड कर रही है जबकि दिल्ली में दिल्ली सरकार सी.बी.एस.ई. की बजाय दिल्ली शिक्षा बोर्ड बनाने जा रही है और हम यहां पर अपने भिवानी बोर्ड के स्कूल खत्म करके मॉडल संस्कृति स्कूलों का केवल नाम रख रहे हैं और साथ में उनको सी.बी.एस.ई. से ऐफिलिएटिड कर रहे हैं। सर, इसमें तीसरी बात यह है कि पहले आपने मुफ्त शिक्षा के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक कहा है इसमें भी सरकार ने फीस लगाने का काम कर दिया है। जो ये एग्जिस्टिंग स्कूल्ज हैं मान

लीजिए मेरी विधान सभा में लडायन या सालावास में जो एग्जिस्टिंग स्कूल्ज हैं वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने उसमें इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। जो बच्चा पहली कक्षा से लेकर 9वीं., 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा तक हिन्दी मीडियम में पढ़ा है। एक दम से आप उसको इंग्लिश मीडियम में कंवर्ट करते हैं तो उनका तो भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री जी इसमें जो नियुक्तियां की जा रही हैं। हमारे पास तो पहले ही 46 हजार के करीब टीचर्स की कमी है। हमारे यहां पी.जी.टी. की इतनी ज्यादा कमी है तो हम बजाय इन स्कूल्ज के नाम और संख्या बढ़ाने के जिसमें आप धड़ाधड़ पत्थर लगाते जा रहे हैं। मैंने इस चीज पर पहले भी ऑब्जैक्ट किया था कि आप मॉडल संस्कृति स्कूल्ज बनाएं, बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिएं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कूल्ज में केवल मात्र नाम लगा देने से काम नहीं चलेगा हम इसका विरोध करेंगे। इसमें बहुत से ऐसे गरीब तबके के बच्चे भी हैं जो उन स्कूल्ज में पढ़ते थे। अब उन्होंने उन स्कूल्ज से अपने को विद्ड्रॉ करने का काम किया है। दूसरा इसमें मेरा ऑब्जैक्शन यह है कि जब मैं बोल रही थी, उस समय मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी पूछा था। मॉडल संस्कृति स्कूल्ज की एक लिस्ट वैबसाईट और सभी जगह अवेलेबल है। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो 17 रिजर्व विधान सभाएं हैं क्या उनमें स्पैशल कोई ध्यान दिया जा रहा है? तो क्या आवश्यकता पड़ी है कि जब आप स्कूल्ज को मॉडल संस्कृति में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी विधान सभा के नाम के आगे लिखे बवानी खेड़ा रिजर्व, मुलाना रिजर्व, झज्जर रिजर्व। ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता है। मैं इस पर भी ऑब्जैक्शन करती हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मॉडल संस्कृति स्कूल्ज काइंडली आप नये खोल दें और सी.बी.एस.ई. से ऐफिलिएटिड करना चाहे तो आप नये स्कूल्ज को कर दें क्योंकि ऑलरेडी आरोही मॉडल स्कूल्ज में अभी तक हमारी भर्ती नहीं हुई है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये परम्परा सही नहीं है।

श्री मनोहर लाल : गीता जी, अगर कहीं उस विधान सभा के नाम के आगे रिजर्व लिखा गया है तो आपकी यह बात ठीक है। मैं भी उसको नहीं चाहूंगा कि ऐसा लिखा जाए। हम इसके लिए मना करेंगे कि किसी भी विधान सभा के नाम के आगे रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। हम विधान सभा को रिजर्व क्यों लिखें। गांव का स्कूल है तो उस पर केवल गांव का नाम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उस जिले का नाम हो जाए जैसे स्कूल का नाम होता है। यह ठीक है कि जब ये योजना बनी

तो उसमें यह था कि हर विधान सभा में वहां के लोगों से बातचीत करके एक स्कूल जरूर बनाया जाए क्योंकि कोई ऐसा न कहे कि हमारे यहां एक भी ऐसा स्कूल नहीं है। अभी 100–150 स्कूल्ज की फीस ज्यादा नहीं थी। जहां पर डिमांड आए वहां एक से ज्यादा स्कूल बनाए जाएं। पहली बात तो हम इसको डिमांड बेस्ड बनाना चाह रहे हैं। अगर कहीं की डिमांड नहीं होगी तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कहीं स्कूल खोलने का बोर्ड लग भी गया है और वहां के अभिभावक यह कहते हैं कि नहीं, हमें यह स्कूल नहीं चाहिए तो हम उसको बन्द कर देंगे। दूसरा इन स्कूल्ज की जो फीस है वह भी बहुत सिस्टम से बनाई गई है। उसमें आय का एक लैवल रखकर के उसमें फीस माफी का भी एक लैवल होगा, आधी फीस माफी का भी एक लैवल होगा, लेकिन जो लोग फीस पे कर सकते हैं, मेरा सोशल सर्विसिज के बारे में यह मानना है कि अगर हमें अच्छी सोशल सर्विसिज देनी है चाहे वह हैल्थ की हैं, चाहे एजूकेशन की हैं, चाहे कोई और सर्विसिज हैं। उसमें सारे समाज के लोग आने चाहिएं। जो अच्छे वैल सैटल्ड हैं अर्थात फीस को पे कर सकने वाले लोग हैं उनके बच्चे भी वहां आएं। मैं समाज की एक धारणा बता रहा हूं आज धारणा यह है कि यह मुफ्त का है, यह बेकार है। चाहे वह इलाज करवाने वाला आदमी हो, वकील को भी आदमी यह कह देता है कि यह कम पैसे लेने वाला वकील है तो यह बेकार होगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : मुख्यमंत्री जी, हमने फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन तो कर दिया है लेकिन अगर कुछ फैमिलीज जो वैल ऑफ हैं और अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं तो अगर वे फीस देना चाहें तो उनको जरूर देनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : गीता जी, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो उसमें आना चाहेंगे आएंगे क्योंकि सारे स्कूल तो बन्द हो नहीं रहे हैं। आखिर तो कितने हजारों स्कूल्ज हैं। उनमें से हम केवल 136 स्कूल्ज ही ले रहे हैं। यह एक प्रयोग है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कोई मना करेगा तो हम वह स्कूल बन्द भी कर देंगे। उनमें गरीब बच्चों की फीस माफ होगी। यह हमारा पूरा प्लान बना हुआ है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मुख्यमंत्री जी, वकील की तो एक रैपुटेशन होती है। उसका पता होता है कि यह वकील अच्छा है। उसमें यह नहीं होता कि कम फीस लेगा। वकील फ्री भी काम कर देता है। वकील की तो एक रैपुटेशन होती है। कम या ज्यादा फीस का कोई मतलब नहीं होता है।

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, मैं तो लोगों की बात बता रहा हूं। वकील अच्छा है तो अच्छा ही है। आप वकील हैं तो अच्छे ही हैं। मैं वकील की निन्दा नहीं कर रहा हूं। आप वकील हैं और अच्छे वकील हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी अंजाने में मर्डर कर बैठा उसने सोचा कि गलती तो हो गई है लेकिन अब इसके लिए केस तो लड़ना ही पड़ेगा। वह एक वकील के पास गया और उसने सारा मामला बता दिया। वकील ने केस पढ़कर कहा कि मैं तेरा केस लडूंगा लेकिन रूपये 21000 लगेंगे। वह आदमी सोचता है कि मर्डर का केस है और वकील केवल 21000 रुपये मांग रहा है, यह मुझे नहीं छुटवा पायेगा तो वह इसके बाद किसी दूसरे अच्छे वकील के पास चला जाता है और उसको सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर वह दूसरा वकील कहता है कि केस के 2 लाख रुपये लगेंगे। उस आदमी ने सोचा कि यह महंगा वकील है तो अच्छा ही होगा और उसने उस वकील को अपना केस लड़ने के लिए रख लिया। महीने–दो महीने–साल तक तारीखें लगती रही और उसके बाद जब कोर्ट का डिसीजन आया तो उस आदमी को उम्र कैद की सजा दे दी गई। सजा होने के बाद जब वकील और वह दोषी व्यक्ति बाहर आ रहे थे तो रास्ते में 21 हजार रुपये वाला वकील मिल गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या रहा केस में तो दोषी व्यक्ति ने बताया कि उसको तो उम्र कैद हो गई है तो जो सस्ता वकील था उसने झट से कहा कि दो लाख में उम्र कैद कराकर आया है यह काम तो मैं 21 हजार में ही कर रहा था। (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करके वकीलों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं भी एक वकील हूँ। मेरे साथ बैठे जगबीर सिंह मलिक भी वकील हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं वकीलों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बल्कि मैं तो इस घटना के माध्यम से व्यक्ति की मानसिकता के बारे में बताने का प्रयास कर रहा था। आदमी तकरीबन इसी प्रकार की सोच रखता है कि जो सस्ता है वह बेकार है और जो मंहगा है वह अच्छा है। इस प्रकार की मनोवृत्ति आमतौर पर इंसान की होती है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अब जबकि बात उठी है तो मैं भी एक सच्चा वाक्या सुनाता हूँ। मैं खुद भी एक वकील रहा हूँ। हमारे जो क्लाइंट होते हैं वह कितने भोले होते हैं, इसकी एक बात बताता हूँ। मैं इस घटना का चश्मदीद

गवाह हूँ। हमारे साथी चौधरी जगबीर सिंह एक बहुत अच्छे सिविलियन वकील हैं, अब भी हैं लेकिन अब वे कोर्ट में नहीं जाते। एक दिन हम दोपहर को कोर्ट में बैठे चाय पी रहे थे। एक भोला आदमी खून में लथपथ मेरे वकील दोस्त के पास आया तो मेरे दोस्त ने उसको पहचान लिया और पूछा कि क्या हुआ तो वह बोला कि फलां आदमी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और मेरे को पीट भी दिया। वकील साहब बोला कि कल तेरे को स्टे लेकर दिया था तो वह बोला कि वकील साहब तेरा स्टे भी मेरे साथ मेरी जेब में ही पिटा था। (हंसी एवं विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं हंसी मजाक के इस माहौल में अब सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगी और वह यह है कि एजूकेशन में जिस प्रकार एन.सी.आर.टी. या एस.सी.ई.आर.टी. होते हैं ठीक उसी प्रकार डाइट और गैटी भी होते हैं। डाईट के तहत डी.एड. के एडमिशंज होते थे और इसमें 4–5 रिजर्व सीटों का भी प्रावधान होता था। यही नहीं चार या पांच हजार की फीस में जे.बी.टी. या डी.एड. के कोर्सिज हो जाया करते थे लेकिन वर्ष 2018 के बाद से डाईट्स के एडमीशंज लगातार बंद हैं और महज सैल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ही यहां पर बी.एड. या जे.बी.टी. के एडमीशंज हो रहे हैं जिनमें 40 से 50 हजार रुपये की मोटी फीस का प्रावधान रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि सरकारी स्तर पर एडमीशंज दोबारा से शुरू किए जायें ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी यहां पर आकर शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके हितों का हनन न हो। वैसे प्रदेश के 21 के 21 जिलों में डाईट्स के जो एडमीशंज बंद किए गए हैं इनका कोई विशेष कारण नज़र नहीं आता है।

श्री जगबीर सिह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यहां पर नॉन अटैंडिंग बेसिज पर एडमिशंज दिए जाते हैं, अब आप ही बताओ कि जो टीचर क्लॉस अटैंड तक नहीं करते वह बच्चों को क्या पढ़ायेंगे?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चर्चा के लिए अब समय ठीक नहीं है। अब तो बीच में कोई विषय ऐसा आ गया था कि मुझे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी घटना का वर्णन करना पड़ा वरना यह समय चर्चा का नहीं बल्कि सदन के नेता द्वारा अपना उत्तर देने का होता है। अभी सदन की कार्यवाही दो दिन और चलेगी आप इन विषयों को उस समय उठा लेना, निश्चित रूप से उस समय चर्चा की जायेगी। इस प्रकार के विषयों पर चर्चा के लिए बहुत समय की जरूरत होती है लेकिन अब चूंकि सदन का समय कम बचा है इसलिए मैं अपने

उत्तर के माध्यम से केवल जो मोटी–मोटी बातें आई हैं, उनके बारे में ही बताना चाहूंगा क्योंकि यदि मैं एक–एक जगह का एक–एक घटना का या फिर एक–एक स्कूल का जिक्र करने लग जाउंगा तो समय बहुत लंबा लग जायेगा। अब मैं विषय पर आता हूँ। जहां तक व्यवस्था परिवर्तन की बात है तो इसके लिए हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू किया है। यह एक बहुत बड़ी वृहत योजना है जिसके लिए हमने अलग से डिपार्टमैंट बनाने तक का काम किया है। इस डिपार्टमैंट को क्रिड यानि सिटिजन रिर्सोर्सिज इंफारमेंशन डिपार्टमैंट के नाम से जाना जाता है। इस डिपार्टमैंट के माध्यम से सभी नागरिकों की सभी प्रकार की इंफारमेशंज लेने का हम प्रयास कर रहे हैं जैसेकि उसकी शिक्षा क्या है, उसका रोजगार क्या है, वह बेरोजगार है या नहीं, उसके पास खेती है या नहीं तथा उसकी क्या आवश्यकतायें हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह भी सोच है कि जो अच्छी कैपेसिटी वाले संपन्न लोग हैं उनका हम किस प्रकार से योगदान ले सकते हैं क्योंकि केवल मात्र सरकार के इम्पलॉईज पर ही निर्भर रहकर हम समाज व प्रदेश का ज्यादा भला नहीं कर पायेंगे बल्कि समाज व प्रदेश का भला करने के लिए हमें सामाजिक संस्थाओं, एन.जी.ओज., सोशल वोलंटियर्ज की पार्टिसिपेशन भी करवानी पड़ेगी। वैसे पार्टिसिपेशन अभी लिमिटेड ही है लेकिन बावजूद इसके हमारा पूरा प्रयास है कि हम ऐसी योजनायें बनाएं जिनके माध्यम से एक–एक परिवार, एक–एक व्यक्ति तथा साधन संपन्न ऐसे परिवार जोकि प्रदेश के विकास में योगदान कर सकते हैं, की सहायता ली जा सके । अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि लाखों ऐसे पैंशनर्ज हैं जो पैंशन तो ले रहे हैं लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। कई लोगों को तो घरों में खाली बैठकर समय व्यतीत करना ही मुश्किल हो जाता है। हम तो कहते हैं कि समाज के कामों में समाज कल्याण की ऐसी योजनाएं बनायेंगे और उसमें उन्हें शामिल करेंगे। इस प्रकार से हम 'किसान मित्र योजना' को हम लागू करेंगे और 'वन मित्र योजना' को भी लागू करेंगे। जब भी परिवारों का सर्वे होगा उसमें स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकत्ताओं को जोड़ेंगे। सरकारी व्यवस्थाओं का ठीक प्रकार से नीचे तक लाभ नहीं पहुँचता है। जब कोई एस.सी. व बी.पी.एल. का डाटा देखते हैं तो बहुत से लोग रोते और चिल्लाते हैं कि मेरा बी.पी.एल. कार्ड नहीं बना। जिसके पास अपनी मोटर कार और तीन मंजिला मकान है, उसका तो बी.पी.एल. कार्ड बना हुआ है। इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास कम से कम आये, इसके लिये हमें सभी का सहयोग की आवश्यकता है। इस

प्रकार से जो भी योजनाएं बनेंगी वे सभी को बता दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, 1.80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार को हम बी.पी.एल. की श्रेणी में लायेंगे। जिस परिवार की 15 हजार रुपये प्रति महीना की आय हो तो उस परिवार को बी.पी.एल. का लाभ मिलना चाहिए। बी.पी.एल. का लाभ भी साल में कुल मिलाकर 15–20 हजार रुपये ही मिलता है। इस प्रकार से 1000–1500 रुपये प्रति महीना का लाभ ही मिलता है। इस प्रकार से हम एक सर्वे करेंगे चाहे इसमें 5 लाख परिवार निकलें, 10 लाख परिवार निकलें या फिर 15 लाख परिवार निकलें इनकी एक फाइनल लिस्ट बनायेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी परिवार की वार्षिक आय 1.80 हजार रुपये है और उस परिवार में से कोई सरकारी नौकरी पर आ गया है तो स्वाभाविक है कि उस परिवार की आय 15 हजार रुपये प्रति महीना से कम नहीं होगी तो तुरंत उस परिवार का नाम बी.पी.एल. से बाहर हो जायेगा। इस योजना में परिवार में जन्म का रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी, मृत्यु रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी, मैरिज रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी आदि ऐसी सभी चीजों का प्रावधान उसमें किया जायेगा। परिवार के रियल डाटा का पता लगना चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या की गणना 10 साल बाद होती है लेकिन बहुत से देशों में जनसंख्या गणना हर साल होती है। मेरे पास यू.के. का एक प्रतिनिधि मण्डल आया था और उन्होंने बताया कि हमारे यहां जनसंख्या की गणना हर साल होती है। परिवार पहचान पत्र स्कीम में हम कितने सफल होते हैं और कितने सफल नहीं होते हैं यह तो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करेगी। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के संबंध में सदन को बताना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर सामान्य अस्पतालों को 100 बिस्तरों को अपग्रेड करके 200 बिस्तरों का करेंगे और जहां पर जिला स्तर का अस्पताल नहीं है अर्थात् नूंह जिले में वहां पर इस साल 100 बिस्तरों का अस्पताल खोलेंगे। इस समय 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 बिस्तरों का अस्पताल है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, 5–6 वर्ष पहले मैडिकल की सीटें 700–800 थी, जिसे बढ़ाते–बढ़ाते आज 1700–1800 सीटों के करीब पहुँच गई हैं और आगे भी सीटों के बढ़ने का प्रोसैस जारी रहेगा। आज जो बच्चे एडमीशन ले रहे हैं वे 5 साल बाद डॉक्टर बनकर निकलेंगे। प्रदेश में नियमित रूप से डॉक्टर्ज के पदों की भर्ती करेंगे और जो भी डॉक्टर्ज के रिक्त पद पड़े हैं, उनको जल्दी ही भरने का काम करेंगे। वोकेशनल स्टडीज के ऊपर सरकार का पूरी तरह से फोकस रहेगा ताकि प्रदेश के बच्चों को कम पढ़ाई के बाद भी साथ–साथ दूसरा कोर्स

आदि करके कोई लाभ भी मिल सके। आठवीं से 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा सामन्य राजकीय स्कूलों में करेंगे। संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा फ्री करेंगे। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

.....

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारंभ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं रिवैन्यू एक्सपैंसिज के विषय पर बात करना चाहूंगा । रिवैन्यू एक्सपैंसिज सरकार का बहुत बड़ा खर्च है । कैपिटल एक्सपैंस का हमारा लगभग 3 गुना रिवैन्यू एक्सपैंस हो जाता है । सभी कैपिटल एक्सपैंस को बढ़ाने के लिए कहते हैं । कैपिटल एक्सपैंस को बढ़ाने के लिए 2–3 तरीके हैं । इसके लिए या तो बजट बढ़ाओ या फिर ऋण ज्यादा लो या फिर हमें रिवैन्यू एक्सपैंस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए । इसके लिए हम हर क्षेत्र में रैशनेलाइजेशन कर सकते हैं फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर रिवैन्यू का क्षेत्र हो । इसमें हमें देखना होगा कि हमें कितने और संस्थान खोलने चाहिए और कौन–से संस्थान अनप्रॉडक्टिव हैं आदि । जो संस्थान अनप्रॉडक्टिव हैं, उनको बदलकर किसी अन्य काम में उपयोग करना चाहिए । हमें इम्पलॉइज की रैशनेलाइजेशन भी करनी चाहिए । आज युग बदल चुका है और आज टैक्नोलॉजी का युग है । अतः आज हमें टैक्नोलॉजी को जानने वाले युवाओं की जरूरत है क्योंकि आज आई.टी. का जमाना है । आज युवा कम्प्यूटर पर बैठकर काम करते हैं । अतः पहले जिस काम के लिए 4 आदमियों की जरूरत थी आज उसी काम को केवल एक आदमी भी कर सकता है । कम्प्यूटर से किये जाने वाले कार्य के लिए हमें सुपरवाइजरी स्टाफ की संख्या अवश्य बढ़ानी पड़ेगी । हमें अपने स्टाफ की कम्प्यूटर से संबंधित स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी और ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी । इससे हम प्रॉडक्टिव और क्वालिटी का स्टाफ तैयार कर पाएंगे । अतः हमें कर्मचारियों की रैशनेलाइजेशन करनी पड़ेगी और जरूरत के मुताबिक विभागों में

स्टाफ की बढ़ौत्तरी और घटौत्तरी करनी पड़ेगी । इसके अलावा हमें प्रॉडक्टिव और नॉन–प्रॉडक्टिव के अंतर को भी अवश्य ध्यान करना पड़ेगा । हमने देखा है कि विभिन्न विभागों में जनता से जुड़ी हुई समस्याओं और विवादों की संख्या बहुत ज्यादा है । हमने हाल ही में एच.एस.वी.पी. विभाग से जुड़े हुए एक मामले को सॉल्व किया है जिससे लगभग 60–62 हजार आम लोगों को फायदा हुआ है । इसी प्रकार से रिवैन्यू डिपार्टमैंट से संबंधित बहुत–से विवाद हैं और लाखों की संख्या में लिटिगेशन चल रही हैं, लोगों के टैक्स के एरियर्स के बहुत–से मामले हैं, कुछ मामले कोर्ट में पैंडिंग हैं और कुछ मामले रिवैन्यू कोर्ट में पैंडिंग हैं । सैंट्रल गवर्नमैंट ने ऐसे ही विवादों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना बनाई है और इसमें उनको सफलता मिल रही है । इसी तर्ज पर हम भी अपने प्रदेश में 'विवादों का समाधान' योजना शुरू कर रहे हैं । हम 'विवादों का समाधान' योजना शुरू होने के बाद सभी विभागों से कहेंगे कि इस तरह के पैंडिंग विवादों को लिस्ट कीजिए और पॉलिसी में बदलाव करके या कोई नई स्कीम बनाकर उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कीजिए । हम 'विवादों का समाधान' योजना बहुत जल्द शुरू करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य सम्पूर्ण हरियाणा में विकास करवाना है । कल माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी कह रहे थे कि मैं रोहतक शहर का निवासी हूं और हमने रोहतक में फलां–फलां काम करवाए हैं तथा मुझे रोहतक पर बहुत गर्व है । मेरा कहना है कि रोहतक से मेरा भी संबंध है और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब का भी संबंध है । रोहतक पर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब को भी अवश्य गर्व होगा और हम सबको रोहतक पर गर्व है । मेरा कहना है कि मुझे अपने पूरे हरियाणा प्रदेश पर गर्व है और बजट से पूरे हरियाणा में विकास के काम होंगे । ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में कम काम होंगे और किसी क्षेत्र में ज्यादा काम होंगे । हम पूरे हरियाणा में बराबर विकास के काम करवायेंगे । यह बजट कोई आंकड़ों की अभिव्यक्ति नहीं है । यह प्रदेश के हर आदमी की आवाज है कि वह सरकार से क्या चाहता है । हम हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि हम जो बजट लेकर आये हैं इसकी इम्पलीमैंटेशन बिना किसी भेदभाव के करेंगे । हम अपने प्रदेश की समस्याओं का निदान और हरियाणा का नव–निर्माण करेंगे । हमारा यही संकल्प रहेगा कि हम हमारे हरियाणा प्रदेश का नव निर्माण करेंगे और एक नया हरियाणा बनाएंगे। यही

हमारा संकल्प रहेगा कि हरियाणा का विकास हर तरीके से हो। मैं हिन्दी के एक महान् कवि श्री दुष्यंत जी की एक कविता को पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

हो गयी पीर पर्वत सी पिंघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए
सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद नहीं।
मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बहुत तफसील से सारी बातें कही गयी हैं। मैं इसमें लम्बा चौड़ा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में 4–5 बातों को कम्पेयर करने पर जोर दिया है। इन्होंने हरियाणा प्रदेश को पंजाब और राजस्थान से कम्पयेर किया है। हमारा उनका क्या कम्पेरिजन है ? आज से नहीं बल्कि वर्ष 2005 से देखें कि पंजाब राज्य का प्लान बजट क्या था ? हमारे प्रदेश का वर्ष 2005 में पंजाब राज्य से आधा बजट था। वर्ष 2013–2014 में हमारे प्रदेश का प्लान बजट पंजाब राज्य से डबल था। पंजाब तो एक डैट रिडन राज्य है और उसकी इकॉनोमिक कंडीशन खराब है। राजस्थान और पंजाब राज्य से हमारे प्रदेश का मुकाबला न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश से ही मुकाबला करें कि आज हरियाणा प्रदेश कहां पर खड़ा है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,55,645 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो बजट होता है वह 10–15 प्रतिशत इन्फ्लेटिड होता है। क्या आप यह लिमिट फिक्स कर सकते हैं ? मेरे पास वर्ष 2019–20 के आंकड़े हैं जिसमें यह इन्फ्लेशन 23 प्रतिशत था। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिवैन्यू बी और एक्चुअल में 76 प्रतिशत और एक्सपैंडीचर बी और एक्चुअल में 77 प्रतिशत है। यानी इसमें 23 प्रतिशत की एवरेज आयी है। इन्होंने कहा है कि इसमें एक साल के बाद फिक्स कर सकते हैं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा इन्फ्लेशन देंगे। सरकार ने 1,55,645 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, परन्तु उसमें से 1,20,000 या 1,15,000 करोड़ रुपये ही निकलेंगे। इससे यही होगा कि सरकार की कोई भी स्कीम कामयाब नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें फिक्स कर दें कि 10 प्रतिशत इन्फ्लेशन देंगे। इसका मतलब यह है कि

आज सरकार का बजट कहां पर है और सरकार के पास क्या है ? मुख्यमंत्री जी ने बजट में बताया है कि टोटल रिवैन्यू की रिसीट्स पिछले साल 40 प्रतिशत के करीब थी और वह अबकी बार 54 प्रतिशत हो गयी है। सैलेरी और पैंशन पर 40 प्रतिशत बजट खर्च करते हैं। इस प्रकार इस टोटल बजट में से 94 प्रतिशत बजट तो वैसे ही चला गया है। इस प्रकार सरकार के पास केवल 6 प्रतिशत बजट ही बाकी रहता है। इसके अतिरिक्त लोन की बात की है। यह बात ठीक है कि स्टेट पहले भी कर्जा लेता रहा है, लेकिन आज हम इस मामले में कहां पर खड़े हैं ? ऑन एन एवरेज वर्ष 2014–15 के बाद हमारी लायबलिटीज 18 प्रतिशत बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री जी ने जी.डी.पी. की ग्रोथ की बात की है। इसमें भी 8 प्रतिशत की एवरेज आ रही है। इसमें कितना डिफरैंस है ? यानी लायबलिटीज 18 प्रतिशत बढ़ी है और जी.डी.पी. की 8 प्रतिशत की एवरेज आ रही है। अगर सरकार इसी प्रकार से चलती रही और संभली नहीं तो प्रदेश इन्सॉलवैंसी की तरफ जा सकता है। हमारा प्रदेश डैट में डूब जाएगा। अगर सरकार इस पर अभी संभल गयी तो हमारे प्रदेश की इकॉनोमी आगे बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों की बात की है। सरकार ने यह कहा है कि उसने यह बजट किसानों के नाम कर दिया है। इसके बारे में मेरा यही कहना है कि पिछली बार किसानों के लिए 4.2 प्रतिशत बजट था और अबकी बार उसको 3 प्रतिशत कर दिया है। इस प्रकार किसानों के लिए बजट घटाया है। दूसरे महकमों की बात तो छोड़ दें क्योंकि यह आंकड़ों का खेल है, लेकिन असलियत यही है। किसानो की आमदनी दोगुनी करने की बात की गयी है और उनको खुशहाल बनाने की बात की गयी है। आज कंस्टैंट प्राइस की बात करें तो किसान की पर कैपिटा इन्कम 63,743 रुपये है। इसका मतलब यह है कि उनकी इन्कम मिनिमम वेजिज से भी कम है। आज मिनिमम वेजिज भी किसान की पर कैपिटा इन्कम से ज्यादा है। जहां तक सरकार द्वारा किसान की आमदनी बढ़ाकर उसको खुशहाल करने की बात कही गई है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जहां पहले कंस्टैंट प्राइस के हिसाब से किसान की पर कैपिटा इनकम 176194 रुपये हुआ करती थी वह आज की तारीख में 63743 हजार रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। आज किसान की पर कैपिटा इन्कम मिनिमम वेजिज से भी कम हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कितनी विडम्बना की बात है कि मिनिमम वेजिज भी किसान की पर कैपिटा इन्कम से ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने एजूकेशन के बारे भी बात कही थी और इसके अलावा सरकार ने बहुत सी बातें भी इस सदन में

कही है। एक तरफ तो सरकार किसान के नाम से बजट दे रही है और दूसरी तरफ किसान मॉडल स्कूल को बंद करने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश में किसान मॉडल स्कूल खोलने की स्कीम शुरू की थी। हमने यह स्कीम इसलिए शुरू की थी ताकि उस स्कूल में किसानों के बच्चे पढ़ाई कर सकें। मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि कई जगहों पर किसान मॉडल स्कूल के लिए बिल्डिंग तैयार है। सरकार ने इन स्कूलों में अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि सरकार ने बुढ़ापा पैंशन के बारे में भी बात कही थी। किस पार्टी ने क्या वायदा किया? यह बात आज सरकार को नजर नहीं आती है। सरकार ने बुढ़ापा पैंशन 2500 रुपये प्रति महीने करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बढ़ी हुई बुढ़ापा पैंशन को यहीं पर आकर बंद कर दिया जायेगा या फिर इसको साल दर साल बढ़ाया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। इसमें मेरा यही कहना है सरकार को संभलकर आगे कदम बढ़ाने चाहिएं अगर यही टैंडैंसी चलती रही, 18 परसैंट के हिसाब से लायबिलिटीज इंक्रीज होती रही तथा जी.डी.पी. की ग्रोथ 8 परसैंट के स्तर पर इस प्रकार से चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश आर्थिक संकटों से घिरता हुआ नजर आयेगा। सरकार द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि आज भी सरकार के पास 32 परसैंट तक लोन ले लेने की क्षमता है परन्तु अगर इसी प्रकार प्रदेश की इकोनोमी चलती रही तो आने वाले समय में यह आंकडा 25 परसैंट तक रह जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन स्टेटों से क्यों कम्पेयर करती है जो कि अपने आप डैट रिडन स्टेट है। सरकार ने पंजाब प्रांत के साथ अपने स्टेट को कंपेयर करते हुए 5 परसैंट फिस्कल डैफिसिट की बात कही लेकिन असल में पंजाब प्रदेश का फिस्कल डैफिसिट साढ़े पांच परसैंट है लेकिन सरकार इसी तरह चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब प्रदेश पर आर्थिक संकट के बादल छा जायेंगे इसलिए मेरा यही कहना है कि सरकार को आगे सोच समझकर कदम बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। सरकार के पास बजट के आंकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए जनता से ज्यादा वायदा न किया जाये तो अच्छा रहेगा क्योंकि वायदों को पूरा करने के लिए सरकार को लोन ही लेना पड़ेगा। इनकम का कोई अन्य जरिया तो प्रदेश में है नही? अगर बावजूद इसके सरकार चार्वाक की उस नीति पर है कि कर्जा लो, घी पीओ उस के बाद कौन देखने वाला है, इस नीति

पर चलना चाहती है तो चले लेकिन यह प्रदेश के हित में बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर हमारी पार्टी की सरकार हो, आखिरकार कर्ज का बोझ तो प्रदेश की जनता को ही सहन करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका भार अवश्य ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार के पास यही वक्त है, अगर इस वक्त में संभल गये तो संभल जाओगे। आज प्रदेश की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है।

Shri Manohar Lal: Speaker Sir, I would like to sum up and conclude the answer. आखिरी में जो हुड्डा साहब ने कमेंट्स किये हैं। वित्त मंत्री होने के नाते से इन कमेंट्स को कन्कलूड करना ही चाहिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी भी कोने में नजर दौड़ाकर देखोगे तो आपको प्रदेश में हर क्षेत्र में आग लगी हुई दिखाई देगी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कादियान जी ने कहा, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो बातें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कही गई है, मैं इनकी बातों का जवाब दे चुका हूं। हुड्डा साहब ने यह बात कही थी और जहां तक मैं इनकी बात समझ पाया हूं वह यह है कि हमारी सरकार पंजाब प्रांत से और राजस्थान प्रांत से कम्पेयर करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पंजाब प्रांत और राजस्थान प्रांत से अपने कार्यकाल के आंकड़ों को कम्पेयर किया है और वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2014 तक के आंकड़ों को भी कम्पेयर किया है। हमारी सरकार इन आंकड़ों से पीछे नहीं है। (विघ्न) हुड्डा साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन करता हूं। मैं इनको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। पंजाब प्रांत के कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी है। उन्होंने पिछले दिनों पंजाब असैम्बली में कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश से क्यों नहीं सीखते हैं। मैं उनकी एक महत्वपूर्ण स्टेटमैंट पढ़कर सुना देता हूं:–

> "Why can't we give MSP on this? The Haryana Government is procuring oilseeds and selling oil out of that. We too can do this."

अब यह स्टेटमैंट श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी की है। मैंने उनको यह स्टेटमैंट देने के लिए नहीं कहा है। जब आसपास के लोग हमारी सरकार पर भरोसा करते हैं तो हमारे लोग भी थोड़ा बहुत विश्वास रखें। अब समस्या यह है कि इस बजट

के मामले में कभी तो कहेंगे कि फिस्कल डैफिसिट कम होना चाहिए, फिर कहेंगे कि टैक्स नहीं लगना चाहिए और फिर कहेंगे कि capital expences भी बढ़ना चाहिए। आखिर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट को किसी न किसी तरह से चलाना तो पड़ेगा। अगर एक्सपैंसिज बढ़ाने हैं तो फिर रेवेन्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे। अगर विपक्ष के साथी टैक्स नहीं लगाने देंगे तो फिर लोन लेना पड़ेगा। विपक्ष के साथी सरकार के किसी भी काम से सहमत नहीं होते। जैसे एक कहावत है कि–मारूं भी और रोण भी कोनी दूं। विपक्ष के हालात कुछ–कुछ ऐसे ही हो गये हैं। ऐसा नहीं हो सकता? मैं विपक्ष के साथियों को एक–एक बात समझाऊंगा। उसके बाद विपक्ष को मानना ही पड़ेगा कि यह ठीक रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंडा मेरे बाप का।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, यह फार्मूला मुख्यमंत्री जी का ही है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, यह फार्मूला मेरा नहीं है। यह फार्मूला हुड्डा साहब और इनकी पार्टी का है। ये ही लोग यह कहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यह किसी भी सूरत में नहीं चल सकता इसलिए मेरा यह कहना है कि–अब किश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें, लहर–लहर तूफान मिले और मौज–मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। धन्यवाद।

.....

वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गईं (डिमांड्स नम्बर 1 से 45) एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमाण्ड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमाण्ड का नंबर बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि राजस्व खर्च के लिए 82,80,51,000/- रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **157,29,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
कि राजस्व खर्च के लिए **456,69,44,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3**8,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1573,31,77,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **205,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **261,01,41,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **40,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **5–आबकारी एवं कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **19335,14,97,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,32,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **6–वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **46,20,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **402,00,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1436,71,96,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2035,69,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **8–भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **17162,01,81,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **445,90,75,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने

के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **9—शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **678,04,11,000 /-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **22,00,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **10—तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **372,73,10,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **55,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **66,28,07,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **12—कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **6177,81,73,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1158,73,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **134,73,45,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1000,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **14—नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष कि राजस्व खर्च के लिए **4101,10,00,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष कि राजस्व खर्च के लिए **67,90,58,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,01,00,000/-** से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **16—श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के कि राजस्व खर्च के लिए **882,49,84,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **17—रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **760,29,44,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **107,68,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **522, 90,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,61,20,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **19—अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **7800,59,02,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **34,65,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1474,13,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **146,87,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **21—महिला तथा बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **168,91,31,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
कि राजस्व खर्च के लिए **665,47,20,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिये **15233,28,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या —**23—खाद्य एवं आपूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी ।

कि राजस्व खर्च के लिए **3066,14,36,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1915,02,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **24—सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष
कि राजस्व खर्च के लिए **462,03,48,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **20,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **25—उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22
कि राजस्व खर्च के लिए **233,95,71,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **26—खान एवं भू—विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **3301,07,28,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **27—कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **1186,52,71,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **38,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **28—पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **124,59,90,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **29—मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **655,17,31,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **30—वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **14,14,85,175/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **5836,16,50,000/-** रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **150,01,00,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों

कि राजस्व खर्च के लिए राजस्व खर्च के लिए **504,20,60,000/-** रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **121,29,60,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **33—सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **2328,61,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **396,92,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **34—परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्चे के लिए **79,31,50,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **33,60,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **35—पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22

कि राजस्व खर्च के लिए **5605,88,96,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **235,01,00,000 /-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **36—गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021—22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **108,73,75,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **11,50,00,000 /-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **37–निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष
कि राजस्व खर्च के लिए **2030,34,50,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1393,51,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **212,34,00,000/-**रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **88,10,00,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **6452,78,11,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **763,41,41,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **40–ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **102,74,00,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **879,00,01,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **290,01,90,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **36,06,41,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1,50,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **44–मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1239,42,61,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा**

<u>कर्ज तथा पेशगियां</u> के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, डिमाण्ड्स पर हमारी पार्टी के बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए आप वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के विषय के सदन की कल की कार्यवाही में शामिल कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हमने सभी माननीय सदस्यों को सारी डिमाण्ड्ज उनके टैबलैट्स पर 12.03.2021 को भेज दी थी। आप सभी अपने टैबलैट्स में देखें। किसी भी डिमाण्ड के लिए कट मोशन देने के लिए दो दिन का समय निर्धारित होता है। माननीय सदस्यगण, हम विधान सभा की कम्पलीट कार्यवाही को पेपरलैस बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इसीलिए सभी डिमाण्ड्ज को सभी माननीय सदस्यों के टैबलैट्स पर 12 मार्च, 2021 को भेजा गया था। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को यह पढ़कर सुना देता हूं। ये है Budget 2021-22 के सीरियल नम्बर–4 पर लिखा हुआ है कि– Budget 2021-22, Volume-II Demands for Grants with Detailed Estimates of Expenditure for the Year 2021-22. इस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों को उनके टैबलैट्स पर डिमाण्ड्ज 12 मार्च, 2021 को भेजी जा चुकी हैं। अगर कोई माननीय सदस्य उसको नहीं पढ़ेगा तो उस स्थिति में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी को डिमाण्ड्ज सहित सभी पेपर 12 मार्च, 2021 को दे दिये गये हैं। मैं इससे सम्बंधित रूल आप सभी को पढ़कर सुना देता हूं – Notice of such motions shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion अर्थात् किसी भी माननीय सदस्य को दो दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। हमने बजट टैबलैट्स के अंदर दिया है। डिमाण्ड्ज से सम्बंधित सभी पेपर भी सभी माननीय सदस्यों को दिये हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी आपने टैबलैट्स की बात कही। मेरा इस बारे में यही कहना है कि मैंने तो आज तक टैबलैट को खोला ही नहीं है। मैं जल्दी ही टैब खोलना सीखूंगा। मैं तो कागज पढ़ता हूं और मेरे पास कागज आये नहीं हैं। अगर आपने डिमाण्ड्ज से सम्बंधित पेपर भी भिजवाये हैं तो मैंने उनको देखा नहीं है। स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि आप सदन के नेता से

पूछ लें अगर उनको कोई एतराज न हो तो आप डिमाण्ड्ज वाले इश्यू को कल टेक–अप कर लें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आज की जो सिटिंग एक्सटैंड की थी वह इसी को लेकर की थी कि आज सदन के नेता ने बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देना है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारंभ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय 10 मिनट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक मिनट में ही काम चल जायेगा। आप यह कह दीजिए कि डिमांड्ज पर डिस्कशन कल कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांण्ड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि राजस्व खर्च के लिए **82,80,51,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
>
> कि राजस्व खर्च के लिए **157,29,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
>
> कि राजस्व खर्च के लिए **456,69,44,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **38,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
>
> कि राजस्व खर्च के लिए **1573,31,77,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **205,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **261,01,41,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **40,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **5–आबकारी एवं कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **19335,14,97,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,32,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **6–वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **46,20,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **402,00,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1436,71,96,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2035,69,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **8–भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **17162,01,81,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **445,90,75,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **9–शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।
कि राजस्व खर्च के लिए **678,04,11,000 /-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **22,00,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **10–तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **372,73,10,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **55,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **66,28,07,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **12–कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **6177,81,73,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1158,73,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **13–स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **134,73,45,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1000,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **14–नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।
कि राजस्व खर्च के लिए **4101,10,00,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए **67,90,58,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,01,00,000/-** से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **16–श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए **882,49,84,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,00,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **17–रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **760,29,44,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **107,68,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **522, 90,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,61,20,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **7800,59,02,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **34,65,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1474,13,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **146,87,00,000/-**रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **21–महिला तथा बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **168,91,31,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **665,47,20,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिये **15233,28,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या –**23–खाद्य एवं आपूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3066,14,36,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1915,02,00,000/-** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **24–सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **462,03,48,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **20,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **25–उद्योग** के अधीन व्ययों के कि राजस्व खर्च के लिए **233,95,71,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **3301,07,28,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **27–कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **1186,52,71,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **38,01,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **28–पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **124,59,90,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **29–मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **655,17,31,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **30–वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **14,14,85,175/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **31–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **5836,16,50,000/-** रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **150,01,00,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा**

कि राजस्व खर्च के लिए राजस्व खर्च के लिए **504,20,60,000/-** रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **121,29,60,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **33–सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **2328,61,20,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **396,92,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **34–परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्चे के लिए **79,31,50,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **33,60,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **35–पर्यटन** के अधीन व्ययों के

कि राजस्व खर्च के लिए **5605,88,96,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **235,01,00,000 /-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **36–गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **108,73,75,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **11,50,00,000 /-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **37–निर्वाचन** के अधीन व्ययों

कि राजस्व खर्च के लिए **2030,34,50,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1393,51,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **212,34,00,000/-**रूपये से तथा पूंजीगत खर्च के लिए **88,10,00,000/-** रूपये अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **6452,78,11,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **763,41,41,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **40–ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **102,74,00,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **879,00,01,000/-**रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **290,01,90,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए **36,06,41,000/-**रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1,50,00,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **44–मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1239,42,61,000/-** रूपये से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2021–22 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार दिनांक 17 मार्च, 2021 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित किया जाता है।

*20.51 बजे (तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

———